सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 03, अंक 214, नई दिल्ली, शनिवार 11 अक्टूबर 2025, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

आपकी कल्पना आपके पंख हैं, जिनके सहारे आप असंभव को भी पार कर सकते हैं।

03 ₹20,000 करोड़ से अधिक के विशाल बाजार में रणनीतिक प्रवेश का संकेत

06 श्रवणशक्ति से भी जुड़ी है बुजुर्गों की सुरक्षा

08 राउरकेला सरकारी अस्पताल में हाउसकीपिंग-सेक्योरिटी टेंडर विवाद पर स्वास्थ्य विभाग ने झाड़ा पल्ला

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) की सख्त मांग:

एनएचएआई की राजामुंडा-बारकोट सड़क परियोजना में वर्षों की देरी, वित्तीय अनियमितताओं और खनन रॉयल्टी की सीबीआई जांच हो – डॉ. राजकुमार यादव

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली/राउरकेला। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव ने आज एनएचएआई (नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया) द्वारा संचालित राजामुंडा से बारकोट खंड की सड़क एवं पुल निर्माण परियोजना में भारी अनियमितताओं, लंबी देरी और संदिग्ध खनन आपूर्ति तथा रॉयल्टी भुगतान की जांच की कड़ी मांग उठाई है। डॉ. यादव ने कहा कि यह परियोजना ओडिशा के सुंदरगढ़ और देवगढ़ जिलों में ट्रक ट्रांसपोर्टरों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन दशक भर से अधिक समय से लटकी हुई है, जिससे दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं, आर्थिक नुकसान हो रहा है और भ्रष्टाचार की बू आ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार, ओडिशा सरकार, सीबीआई और ईडी से तत्काल स्वतंत्र जांच की अपील की है, ताकि दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों पर कठोर कार्रवाई हो और परियोजना को तेजी से पूरा किया जाए।

डॉ. यादव ने प्रेस नोट में जोरदार तरीके से कहा, ₹यह सड़क ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी की रीढ़ है। खराब हालत से हर साल सैकड़ों दुर्घटनाएं हो रही हैं, ईंधन बर्बाद हो रहा है और माइनिंग क्षेत्र का व्यापार ठप्प पड़ रहा है। एनएचएआई की मिलीभगत से ठेकेदारों ने फंड्स का दुरुपयोग किया है। हम मांग करते हैं कि खनन परमिशन, खनन सामग्री की आपूर्ति,खनन क्षेत्र की फोसील जाँच,रॉयल्टी राशिदों की जाँच और भुगतान के क्रम की गहन जांच हो। यदि अनिमियता साबित होता है, तो सभी जिम्मेदारों को जेल भेजकर उनकी सम्पत्ति सरकारी खाते मे लाया जाये और परियोजना को नई समयसीमा के साथ तकनीकी व वास्तविक रूप से पूरा किया जाए।₹

घटनाक्रम की विस्तृत और अद्यतन समयरेखा के तहत परियोजना की शुरुआत से अब तक का क्रम आधिकारिक दस्तावेजों, एनएचएआई रिपोर्ट्स और समाचार स्रोतों पर आधारित है, जो देरी और अनियमितताओं को उजागर करता है:

2005-06: NH-143 के 126 किमी खंड (बिरमित्रपुर से बारकोट) को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना-IV में शामिल किया गया, जिसमें राजामुंडा-बारकोट हिस्सा भी था।

2010: गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को DBFOT आधार पर ठेका मिला, लेकिन विलंब शुरू हो गया।

2015: केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पूरे खंड को चार-लेन बनाने के निर्देश दिए, लेकिन परियोजना को तीन पैकेजों में बांटा गया।

2020-2021: कोविड-19 के कारण समयसीमा जून 2022 तक बढ़ाई गई, लेकिन ठेकेदार कम्पनी की वित्तीय समस्याओं से काम रुक गया। एनएचएआई ने कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने की चेतावनी दी।

2022: परियोजना अभी भी अधर में, ठेकेदार कम्पनी ने काम बंद कर दिया। एनएचएआई ने नया टेंडर फ्लोट करने की बात कही, लेकिन कोई प्रगति नहीं।

अगस्त 2024: परियोजना तीन साल से अधिक पीछे, नई डेडलाइन दिसंबर 2024। कुल 13 एनएच परियोजनाएं ओडिशा में विलंबित, जिसमें यह शामिल। भूमि अधिग्रहण, मंदिर शिफ्टिंग और विरोध जैसे मुद्दे प्रमुख रहे1

जुलाई 2025: सुंदरगढ़ के कोइडा माइनिंग क्षेत्र में भूस्खलन से NH-520 (कनेक्टेड रूट) पर ट्रैफिक रुका, जो अप्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना को प्रभावित करता है।

2025 तक: परियोजना खानापूर्ति के साथ पूरी, वित्तीय अनियमितताओं के आरोप। कोई नया ठेकेदार नहीं नियुक्त, काम बाकि1

अतिरिक्त तथ्यात्मक जानकारी और अनियमितताओं के मजबूत संकेत के अनर्गत परियोजना का महत्व और प्रभाव: यह राजमार्ग ओडिशा के माइनिंग बेल्ट से गुजरती है, जहां दैनिक हजारों ट्रक लौह अयस्क, फ्लाइ एस (राख) और अन्य सामग्री ढोते हैं। देरी से दुर्घटनाओं में वृद्धि (ओडिशा में NH पर सालाना 5,000+ दुर्घटनाएं), ईंधन लागत में 20-30% बढ़ोतरी और आर्थिक नुकसान (माइनिंग सेक्टर को ₹1,000 करोड़+ का वार्षिक घाटा) 1 ट्रक ट्रांसपोर्टरों को सबसे ज्यादा नुकसान, क्योंकि वैकल्पिक रूट नहीं।

खनन आपूर्ति और रॉयल्टी के तहत निर्माण में माइनर मिनरल्स (गिट्टी,बालू, मुरुम) की आपूर्ति संदेहास्पद है1 वहीं राइट टू इनफार्मेशन के तहत जानकारी आपस मे मेल नहीं खाती1 क्या इस परियोजना में अवैध स्रोतों से सामग्री ली गईं, क्या उसके रॉयल्टी रशीद आपूर्ति व खनन से मिलान खाते हैं1

भुगतान और वित्तीय अनियमितताएं:ठेकेदार ने काम रोका, लेकिन एनएचएआई ने अनधिकृत सब-कॉन्ट्रैक्टिंग को फ्रॉड माना (2025 नीति)। फंड्स का दुरुपयोग संभावित, जिसमें फर्जी बिलिंग और घूसखोरी शामिल। भूमि अधिग्रहण में 30 एकड़ पेंडिंग, ओडिशा हाईकोर्ट में केस। कुल लागत में असंगतियां (₹394 करोड़ से ₹641 करोड़ तक रिपोर्ट्स)।

अन्य संदिग्ध तथ्य: ओडिशा में अन्य एनएच प्रोजेक्ट्स विलंबित, जिसमें NH-520 (कोइडा-राजामुंडा) भी शामिल, जो इस रूट से जुड़ा है। मंदिर शिफ्टिंग और भूमि विवाद जैसे बहाने, लेकिन असल में ठेकेदारों की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता 1

डॉ. यादव ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, "यदि जांच में देरी हुई, तो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा पूरे देश में ट्रक हड़ताल और धरना प्रदर्शन शुरू करेगा। ट्रांसपोर्टरों का हक नहीं छीना जाएगा। हम पारदर्शिता और न्याय की लड़ाई लड़ेंगे!"

राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा (ट्रक ट्रांसपोर्ट सारथी) ट्रक मालिकों, चालकों और परिवहन क्षेत्र के हितों की रक्षा करने वाला प्रमुख संगठन है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार संघर्ष कर रहा है।

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ द्वारा "DTC बचाओ अभियान" पांचवां दिन

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: दिल्ली परिवहन मजदूर संघ ने "DTC बचाओ अभियान" की शुरुआत के चलते पांचवें दिन इस भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता, तथा विधान सभा के विधायकों के अंतर्गत आने वाले DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने मिलकर दिल्ली के सभी 70 विधायकों को मांग पत्र देने की कड़ी में आज आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी को भी ज्ञापन सौंपा,

ज्ञापन में दी गई मांगों पर विस्तृत चर्चा हुई विधायक जी ने तुरंत अपने PA द्वारा मुख्यमंत्री और परिवहन मंत्री के नाम पत्र लिखकर कर्मचारियों के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय मांगा, इससे कर्मचारियों में काफी उम्मीदें बढ़ी कि उनकी इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द होगा तथा DTC के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों ने दिल्ली के 3 और विधायकों के निवास स्थान पर जाकर ज्ञापन दिया,

दिल्ली की विधानसभाओं के विधायक

1. वजीरपुर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक श्रीमति पूनम शर्मा जी
2. हरी नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री श्याम शर्मा जी
3. आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक श्री राजकुमार भाटिया जी

तक पहुंचें और उन्हें (DTC)दिल्ली परिवहन निगम की गंभीर समस्याओं से अवगत कराकर पत्र सौंपा1

यह अभियान दिल्ली के 70 विधायकों तथा 7 लोकसभा सांसदों को मांग पत्र सौंपे जाने तक चालू रहेगा, अभी तक दिल्ली के लगभग 18 विधायकों तक यह पत्र पहुंच चुके हैं पत्र को लेकर दिल्ली सरकार से DTC कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को बड़ी उम्मीद है कि जल्द उनको जॉब सिक्योरिटी और बेसिक DA ग्रेड PAY प्राप्त होगा तथा दिल्ली की परिवहन व्यवस्था में दिल्ली सरकार की खुद की दिल्ली परिवहन निगम की बसें आयेंगी,

इस अभियान का तहत दिल्ली की जनता की जीवन रेखा डीटीसी बस सेवा को सशक्त बनाना,निगम के कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना तथा दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करना है,

16/nov/2024 को एक ट्वीट के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी ने कहा कि दिल्ली में हमारी सरकार बनते ही एक कमेटी का गठन किया जाएगा जिसमें DTC के सभी कांटेक्ट कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाएगा,सरकार बनने के लगभग 9 महीने बाद भी DTC के कर्मचारियों की समस्या का समाधान ना होने पर उनमें काफ़ी रोष है,

DTC के एक कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी ने नाम न बताने की शर्त पर यह तक कहा कि दिल्ली जैसे शहर में आज मात्र 862 रुपए में कोई भी कर्मचारी अपना घर नहीं चला पा रहा है इसलिए उन्हें समान काम समान वेतन व जॉब सिक्योरिटी चाहिए,कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की इन समस्याओं का अगर समाधान नहीं हुआ तो इसका प्रभाव आने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी होगा, दिल्ली में कई और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का धरना लगातार जारी है, ऐसे में अगर दिल्ली को चलाने वाली DTC, इलेक्ट्रिक व क्लस्टर बसों में कार्य कर रहे कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ जाएंगे तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था को चलाने वाली मुख्य बिंदु दिल्ली परिवहन निगम एकदम से ठप हो जाएगी, और दिल्ली के लगभग 40 लाख लोगों पर इसका प्रभाव पड़ेगा1

रिपोर्टर पंकज शर्मा

दिल्ली परिवहन मजदूर संघ प्रदेश कार्यालय अजमेरी गेट दिल्ली 110006

1. अध्यक्ष: गूगन सिंह
2. महामंत्री: भानु भास्कर

राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति के मांग पत्र से सरकार को एक बार फिर ड्राइवर आयोग की मांग के लिए मांग पत्र दिया गया

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। राष्ट्रीय ड्राइवर संयुक्त मोर्चा समिति के मांग पत्र से सरकार को एक बार फिर ड्राइवर आयोग की मांग के लिए मांग पत्र दिया गया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, श्रम मंत्रालय, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन क्रांतिकारी जी को पत्र भेजा गया है और सरकार से यह मांग करते हैं जल्द से जल्द ड्राइवर आयोग की स्थापना की जाए जिससे कि तमाम देश के 24 करोड़ चालकों को उनका अधिकार मिले। संस्थापक सुमेर अम्बावता एवं शैलेश पाठक जी, महासचिव रवि राठौर के द्वारा पत्र दिया गया।

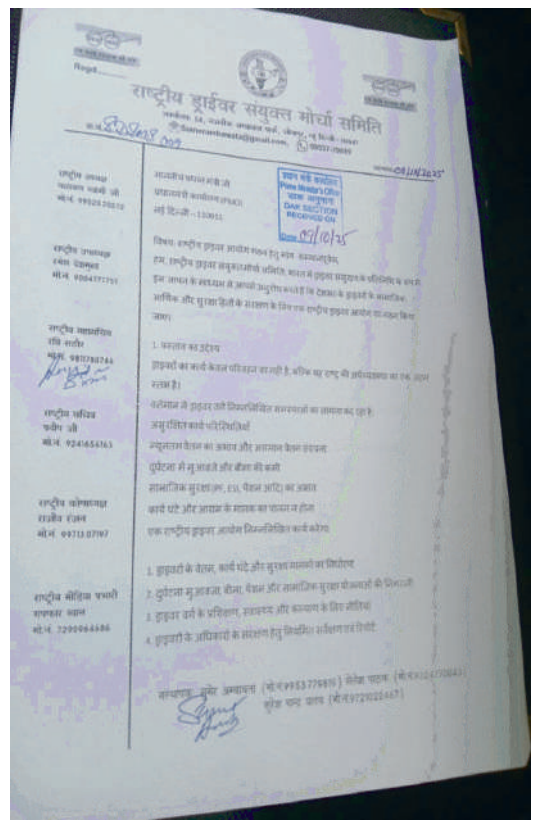

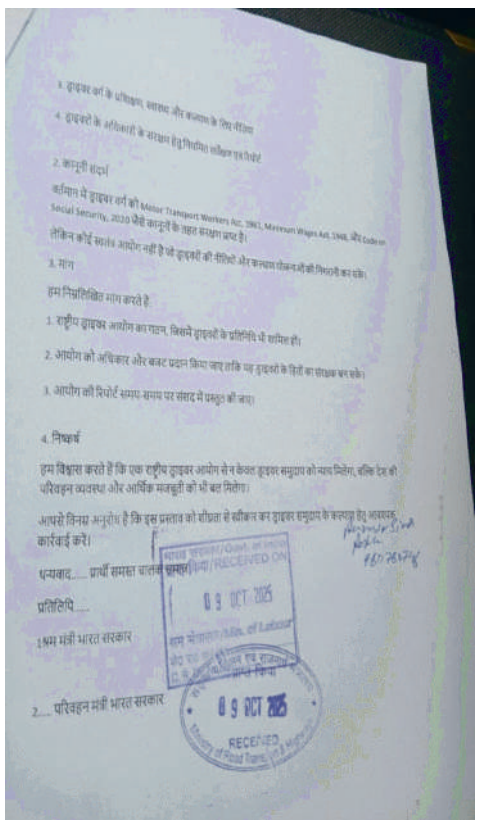

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से आत्मीय भेंट कर दिल्ली के समग्र विकास आदि कार्यों को लेकर दी शुभकामनाएं

परिवहन विशेष न्यूज

दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी से आत्मीय भेंट कर उनकी सरकार द्वारा दिल्ली के समग्र विकास ,जनकल्याण कार्यों ,और जनसेवा कार्यों के प्रति समर्पण भावना की सराहना करते हुये उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी।

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में "विकसित दिल्ली" के संकल्प को साकार करने हेतु हमारा सामूहिक प्रयास निरंतर जारी रहेगा- राजेश भाटिया

अपने माता पिता, बहन भाइयों, महिलाओं एवं बुजर्गों का सम्मान करें।

दिल्ली में जल्द ही पर्यटकों के लिए चलेंगी बैंगनी रंग की बसें

दिल्ली में पर्यटकों के लिए खुशखबरी! दिल्ली सरकार अगले महीने से बैंगनी रंग की विशेष बसें शुरू करने जा रही है। ये बसें पर्यटकों को दिल्ली के प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएंगी और पर्यटन को बढ़ावा देंगी। बसों में पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

नईदिल्ली। नई दिल्ली क्षेत्र के लोकप्रिय स्थलों प्रधानमंत्री संग्रहालय से दिल्ली हाट तक का भ्रमण पर्यटक जल्द ही बैंगनी रंग से सजी बसों में कर सकेंगे। इन पर सिग्नेचर ब्रिज और भारत मंडपम जैसे ऐतिहासिक स्थलों को भी दर्शाया गया होगा। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली सरकार का पर्यटन विभाग इस सेवा को इसी माह या अगले महीने शुरू करने की योजना बना रहा है।

एक अधिकारी ने कहा, 'हम पर्यटकों के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय से भारत मंडपम, युद्ध स्मारक, नए संसद परिसर, दिल्ली हाट आदि जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के लिए शाम के ट्रिप शुरू करने की योजना बना रहे हैं। इसके माध्यम से, हम दिल्ली आने वाले विदेशियों और पर्यटकों को लक्षित करने की योजना बना रहे हैं। हमने डीटीसी से नौ मीटर लंबी नई इलेक्ट्रिक बसें किराए पर ली हैं।' उन्होंने कहा, 'चूंकि संग्रहालय शाम छह बजे बंद हो जाता है, इसलिए हम वहीं से ट्रिप शुरू करेंगे और फिर अन्य स्थलों की ओर बढ़ेंगे।'

बसें बैंगनी रंग की होंगी और उन पर सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट और भारत मंडपम जैसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों की तस्वीरें होंगी। अधिकारी ने बताया कि यह उन्हें सड़कों पर चलने वाली दूसरी बसों से अलग दिखाएगा। बस में यात्रा का किराया वयस्कों के लिए 500 रुपये और छह से बारह साल के बच्चों के लिए 300 रुपये होगा। अधिकारी ने आगे बताया कि बस में एक गाइड भी होगा जो पर्यटकों को उनके द्वारा देखे जाने वाले स्थलों के महत्व के बारे में जानकारी देगा। अपने बजट भाषण में, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की थी कि उनकी सरकार युद्ध स्मारक, कर्तव्य पथ, प्रधानमंत्री संग्रहालय और नए संसद परिसर को शामिल करते हुए एक नया पर्यटन सर्किट विकसित करेगी।

पर्यटन विभाग ने "होप आन-होप आफ" (हो-हो) बस माडल को पुनर्जीवित करने की योजना पर भी चर्चा की थी, जो 2020 में कोविड महामारी के कारण रुक गई थी। हालांकि, अधिकारियों का कहना है कि दिल्ली जैसी जगह के लिए यह मॉडल टिकाऊ नहीं हो सकता है।

"टेंपल आफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर अलाइड ट्रस्ट पंजीकृत" सेवा ही संकल्प है!

पिंकी कुंडू, महासचिव टोलवा ट्रस्ट

हमारा मकसद सिर्फ मदद नहीं, बदलाव लाना है।

A voice for the voiceless, and a hand for the helpless.

हमारा उद्देश्य है समाज के उन हिस्सों तक पहुँचना जो आज भी भूख, शिक्षा और आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। हम जरूरतमंदों को बिना भेदभाव के भोजन, बच्चों को मुफ़्त शिक्षा, और समाज को जागरूकता देने का कार्य कर रहे हैं।

क्या मिलेगा हमसे जुड़कर

Ground-level food distribution,

Getting children free education,

हम मानते हैं – छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है।

If you believe in humanity, equality, and service — then you're already a part of our family.

हमें सपोर्ट करें और एक आवाज़ बनें इस बदलाव की।

Together, let's serve. Together, let's change.

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से जुड़ने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और फार्म भरकर जुड़े,

www.tolwa.com/member.html

स्कैनर को स्कैन कर के भी आप टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत से फार्म भर कर जुड़ सकते हैं,

वेब साइट पर www.tolwa.com पर भी जाकर आप फार्म भर के टोलवा ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं। www.tolwa.com

SCAN ME

टोलवा ट्रस्ट पंजीकृत
tolwaindia@gmail.com
www.tolwa.com

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल -0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063

कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

भगवान श्रीकृष्ण बार बार जरासंध को युद्ध हारने के बाद भी जीवित छोड़कर जाने देते इसके पीछे का राज

कंस की मृत्यु के पश्चात उसका ससुर जरासन्ध बहुत ही क्रोधित था, उसने कृष्ण व बलराम को मारने हेतु मथुरा पर बार बार आक्रमण किया।

प्रत्येक पराजय के बाद वह अपने विचारों का समर्थन करने वाले तमाम राजाओं से सम्पर्क करता और उनसे महागठबंधन बनाता और मथुरा पर हमला करता था

और श्री कृष्ण पूरी सेना को मार देते, मात्र जरासन्ध को ही छोड़ देते...

यह सब देख श्री बलराम जी बहुत क्रोधित हुये और श्री कृष्णजी से कहा...

बार-बार जरासन्ध हारने के बाद पृथ्वी के कोनों कोनों से दुष्टों के साथ महागठबंधन कर हम पर आक्रमण कर रहा है और तुम पूरी सेना को मार देते हो किन्तु असली खुराफात करने वाले को ही छोड़ दे रहे हो..

तब हंसते हुए श्री कृष्ण ने बलराम जी को समझाया...

हे भ्राताश्री मैं जरासन्ध को बार बार जानबूझकर इसलिए छोड़ दे रहा हूँ कि ये जरासन्ध पूरी पृथ्वी के दुष्टों को खोजकर उनके साथ महागठबंधन करता है और मेरे पास लाता है और मैं बहुत ही आसानी से एक ही जगह रहकर धरती के सभी दुष्टों को मार दे रहा हूँ नहीं तो मुझे इन दुष्टों को

मारने के लिए पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना पड़ता,

और बिल में से खोज-खोज कर निकाल निकाल कर मारना पड़ता और बहुत कष्ट झेलना पड़ता।

"दुष्टदलन" का मेरा यह कार्य जरासन्धने बहुत आसान कर दिया है:"..

"जब सभी दुष्टों को मार लूंगा तो सबसे आखिरी में इसे भी खत्म कर ही दूंगा " आप चिन्ता न करे भ्राताश्री..

सदैव प्रसन्न रहिए जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।

रोहिणी व्रत आज

कार्तिक माह में पड़ने वाला रोहिणी व्रत मुख्य रूप से जैन समुदाय के लोगों के लिए बहुत खास है। यह व्रत उस दिन किया जाता है जब रोहिणी नक्षत्र पड़ता है, इसलिए इसे रोहिणी व्रत कहते हैं। वहीं, ज्योतिष और हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने वाली महिलाओं को अखंड सौभाग्य और उनके पति को दीर्घायु प्राप्त होती है। साथ ही, यह व्रत करने से व्यक्ति के आत्मा के विकार दूर होते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है और घर से दरिद्रता व आर्थिक समस्याएं नष्ट हो जाती हैं और सुख-समृद्धि का वास होता है। यही कारण है कि हर माह में पड़ने वाले रोहिणी व्रत से कही अधिक ज्यादा शुभ माना जाता है कार्तिक माह का रोहिणी व्रत।

कार्तिक रोहिणी व्रत कब है?

==========

कार्तिक माह में रोहिणी व्रत कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि पर पड़ता है। ऐसे में हिन्दू पंचांग के अनुसार, इस साल पंचमी तिथि का आरंभ 10 अक्टूबर, शुक्रवार के दिन शाम 7 बजकर 38 मिनट से हो रहा है। वहीं, इसका समापन 11 अक्टूबर, शनिवार के दिन शाम 4 बजकर 43 मिनट पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, कार्तिक रोहिणी व्रत 11 अक्टूबर को रखा जाएगा।

कार्तिक रोहिणी व्रत चंद्रमा पूजन मुहूर्त

==========

कार्तिक माह में पड़ने वाले रोहिणी व्रत यानी 11 अक्टूबर, शनिवार के लिए चंद्रमा पूजन का मुहूर्त रात्रि में रहेगा क्योंकि यह कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है और इस तिथि पर चंद्रमा देर से उदय होता है। पंचांग के अनुसार, इस दिन चंद्रोदय का समय रात 09 बजकर 10 मिनट है। ऐसे में चंद्रमा की पूजा एवं चंद्र अर्घ्य इसके समय के बाद कभी भी दिया जा सकता है।

कार्तिक रोहिणी व्रत महत्व

==========

कार्तिक माह में पड़ने वाला रोहिणी व्रत रखने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है यानी विवाहित महिलाओं को उनके पति की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, यह व्रत करने से व्यक्ति के सभी पाप और दुख दूर होते हैं, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है और घर में सुख-समृद्धि तथा धन-धान्य का आगमन होता है।

रोहिणी व्रत की पूजा विधि

==========

* ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें।

* आचमन कर व्रत का संकल्प लें और सूर्य भगवान को जल अर्पित करें।

* पूजा स्थल की साफ-सफाई के बाद वेदी पर भगवान वासुपूज्य की मूर्ति स्थापित करें।

* पूजा में भगवान वासुपूज्य को फल-फूल, गंध, दूर्वा, नैवेद्य आदि अर्पित करें।

* सूर्यास्त होने से पहले पूजा कर फलाहार करें।

* अगले दिन पूजा-पाठ करने के बाद अपने व्रत का पारण करें।

* व्रत के दिन गरीबों में दान जरूर करें।

ध्यान रखें ये नियम

==========

जैन धर्म में रोहिणी व्रत एक पवित्र अनुष्ठान है, ऐसे में इस दिन स्वच्छता और शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। महिलाओं के साथ-साथ पुरुष भी रोहिणी व्रत कर सकते हैं। सूर्यास्त के बाद इस व्रत में भोजन नहीं किया जाता। इस व्रत को लगातार तीन, पांच या सात साल तक रखना जरूरी माना जाता है। पारण अनुष्ठान करने के बाद ही इस व्रत को पूर्ण माना जाता है।

चंद्रप्रभा चूर्ण – चंद्र जैसी शांति देने वाली आयुर्वेदिक औषधि

आयुर्वेद में "चंद्रप्रभा" शब्द दो भागों से बना है — "चंद्र" यानी चाँद, और "प्रभा" यानी प्रकाश या आभा।

जैसे चाँद अपनी ठंडी किरणों से मन को शांति देता है, वैसे ही चंद्रप्रभा चूर्ण शरीर की गर्मी, सूजन और विकारों को शांत कर शरीर को आभामय बनाता है।

यह औषधि मूत्र संस्थान (Urinary System), जननांग रोगों, त्वचा रोग, थायरॉइड, मधुमेह और शरीर की थकावट में अत्यंत उपयोगी है।

$ चंद्रप्रभा चूर्ण के मुख्य घटक

चंद्रप्रभा चूर्ण कई शक्तिशाली औषधियों का अद्भुत मिश्रण है —

1. गुग्गुलु (Commiphora mukul)
2. त्रिफला (हरड़, बहेड़ा, आंवला)
3. त्रिकटु (सौंठ, काली मिर्च, पिपली)
4. चंदन (सफेद चंदन)
5. विदंग
6. नागरमोथा
7. हरीतकी
8. दारुहल्दी
9. शिलाजीत
10. गोखरू
11. मुलेठी
12. गुडुची (गिलोय)
13. वचा
14. भल्लातक
15. लौह भस्म
16. सूतशेखर रस (कभी-कभी)

यह सब मिलकर शरीर की सूजन, संक्रमण, गर्मी और अशुद्धि को दूर करते हैं।

चंद्रप्रभा चूर्ण बनाने की विधि (Preparation Method)

1. उपर्युक्त सभी औषधियों को सुखाकर बारीक पीस लें।
2. प्रत्येक औषधि समान मात्रा (लगभग 10 ग्राम) लें।
3. सबको मिलाकर महीन छलनी से छानें।
4. साफ शीशी या कांच के जार में भरकर रखें।
5. छाया में सूखी जगह पर स्टोर करें।

इससे तैयार होता है — शुद्ध, प्रभावी चंद्रप्रभा चूर्ण

चंद्रप्रभा चूर्ण के आयुर्वेदिक लाभ (Ayurvedic Benefits)

1. मूत्र संबंधी विकारों में अमृत समान

बार-बार पेशाब आना, जलन, दर्द, मूत्र संक्रमण (UTI) में अत्यंत लाभकारी।

गुर्दों (Kidneys) को मजबूत बनाता है।

2. मधुमेह (Diabetes) में सहायक

शुगर को नियंत्रित करने में मदद करता है।

थकान व जलन जैसी समस्या कम करता है।

3. पुरुष एवं स्त्री रोगों में लाभकारी

वीर्य दोष, स्वप्नदोष, स्त्रियों में श्वेत प्रदर (Leucorrhea), मासिक धर्म विकार में लाभदायक।

4. थायरॉइड, मोटापा और सूजन में उपयोगी

शरीर की अतिरिक्त गर्मी और सूजन को घटाता है।

मेटाबॉलिज़्म को संतुलित करता है।

5. त्वचा रोग और रक्त विकारों में लाभदायक

त्वचा पर चमक लाता है।

रक्त की शुद्धि करता है।

6. स्नायु और जोड़ों के दर्द में राहत

वात दोष को शांत करता है।

गठिया, सूजन, कमर दर्द में उपयोगी।

सेवन विधि (How to Take Chandra Prabha Churna)

मात्रा: 1 से 3 ग्राम (लगभग ½ चम्मच)

सेवन समय: भोजन के बाद

सेवन विधि:

गुनगुने पानी या दूध के साथ

या डॉक्टर की सलाह अनुसार "गोक्षुरादि क्वाथ" के साथ

⚠ सावधानी:

गर्भवती महिलाएँ या गंभीर रोगी चिकित्सक की सलाह से ही लें।

अधिक मात्रा में सेवन से दस्त या कमजोरी हो सकती है।

संक्षेप में – "चंद्रप्रभा" का अर्थ ही है शरीर और मन को चाँद-सी शांति देना!

यह औषधि न केवल रोग मिटाती है, बल्कि शरीर की आभा, ऊर्जा और संतुलन को भी पुनः स्थापित करती है।

मस्तिष्क को तेज़, चुस्त और तंदुरुस्त बनाए रखने वाली 10 आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ - आपके किचन से

दिमाग हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका सही तरह से काम करना हमारी याददाश्त, सोचने-समझने की क्षमता और भावनात्मक संतुलन को बनाए रखता है। लेकिन बढ़ती उम्र, खराब लाइफस्टाइल, नशा, तनाव और पोषण की कमी के कारण मस्तिष्क कमजोर हो सकता है।

पर आयुर्वेद के अनुसार, कुछ आसानी से उपलब्ध जड़ी-बूटियाँ दिमाग को फिर से तेज, सक्रिय और स्वस्थ बना सकती हैं। ये जड़ी-बूटियाँ आपके किचन में ही मिल जाती हैं और बिना किसी साइड इफेक्ट के धीरे-धीरे अपना असर दिखाती हैं।

आइए जानें 10 बेहतरीन आयुर्वेदिक जड़ी-बूटियाँ जो आपके Brain Health को बेहतर बनाएं:

1. जटामांसी (Jatamansi)

यह मस्तिष्क के लिए अत्यंत लाभकारी औषधि है। इसके नियमित सेवन से मानसिक तनाव कम होता है और स्मरण शक्ति बढ़ती है।

कैसे लें: 1 चम्मच जटामांसी पाउडर को एक कप दूध में मिलाकर रात को लें।

2. ब्रह्मी (Brahmi)

Brahmi को Brain Tonic भी कहा जाता है। यह मन को शांत करता है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है।

कैसे लें: आधा चम्मच ब्राह्मी पाउडर + 1 चम्मच शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिएं।

3. शंखपुष्पी (Shankhpushpi)

यह Learning और Creativity को बढ़ावा देती है। दिमागी थकान दूर करने के लिए बेहद उपयोगी है।

कैसे लें: आधा चम्मच शंख पुष्पी को गर्म पानी में मिलाकर सेवन करें।

4. दालचीनी (Cinnamon)

दालचीनी मानसिक तनाव कम करने में सहायक होती है। यह दिमागी कोशिकाओं को पोषण देती है।

कैसे लें: रात को सोने से पहले एक चुटकी दालचीनी पाउडर + शहद के साथ लें।

5. हल्दी (Turmeric)

हल्दी में मौजूद Curcumin मस्तिष्क की कोशिकाओं को रिपेयर करता है और Alzheimer जैसे रोगों से सुरक्षा करता है।

कैसे लें: हल्दी वाला दूध रोजाना रात में पिएं।

6. जायफल (Nutmeg)

थोड़ी मात्रा में जायफल का सेवन करने से मस्तिष्क तेज होता है और भूलने की बीमारी दूर होती है।

कैसे लें: एक चुटकी जायफल पाउडर को दूध में मिलाकर लें।

7. अजवाइन की पत्तियाँ (Carom Leaves)

इनमें मौजूद Anti-Oxidants दिमाग की कोशिकाओं को Free Radicals से बचाते हैं और Brain Function को बढ़ाते हैं।

कैसे लें: इनकी चाय बनाकर या सलाद में उपयोग करें।

8. तुलसी (Tulsi)

Tulsi तनाव को कम करती है और मानसिक स्पष्टता को बढ़ाती है। यह Blood Circulation को भी बेहतर करती है।

कैसे लें: रोज सुबह 5-6 तुलसी के पत्ते चबाएं या तुलसी की चाय पिएं।

9. केसर (Saffron)

अनिद्रा और Depression को दूर करने में मददगार। यह Mood Uplift करने और दिमाग को तेज करने में मदद करता है।

कैसे लें: गर्म दूध में 3-4 केसर के रेशे मिलाकर रात को लें।

10. काली मिर्च (Black Pepper)

इसमें मौजूद Piperine रसायन दिमाग को शांत करता है और Depression से राहत दिलाता है।

कैसे लें: सुबह गर्म पानी में एक चुटकी काली मिर्च पाउडर डालकर पिएं।

बढ़ रहा खतरा, कैंसर अब दुनिया में हृदय संबंधी रोगों के बाद मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बना

अंतरराष्ट्रीय जर्नल द लैंसेट के अनुसार 2050 तक तीन करोड़ मामले और 1.86 करोड़ मौतों का अंदेशा

पुनीत उपाध्याय

कैंसर अब दुनिया में हृदय संबंधी रोगों के बाद मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण बन गया है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रिका द लैसेंट ने कैंसर को लेकर चिंताजनक तस्वीर साझा की है। लैसेंट के अनुसार 1990 से 2023 के बीच दुनिया भर में कैंसर के मामले और मौत तेजी से बढ़ी हैं। 2023 में दुनिया भर में 1.85 करोड़ लोगों को कैंसर हुआ था। वहीं 1.04 करोड़ लोग इस बीमारी का शिकार बन गए थे। इनमें से करीब 58 फीसदी नए मामले और करीब 66 फीसदी मौतें कमजोर और मध्यम आय वाले देशों में हुई। अध्ययन में 1990 से 2023 के बीच 204 देशों और क्षेत्रों में 47 प्रकार के कैंसर और 44 जोखिम कारकों का विस्तृत आकलन प्रस्तुत किया गया है।साथ ही 2050 तक कैंसर के मामलों के बारे में भी अनुमान लगाया गया है। लेख में वैज्ञानिकों ने यह भी चेताया है कि 2050 तक 3.05 करोड़ लोगों को कैंसर हो सकता है इसके साथ ही 1.86 करोड़ लोगों की मौत भी हो सकती है। आधे से ज्यादा मामले और दो.तिहाई मौतें कमजोर और मध्यम आय वाले देशों में होंगी, यानी अगले 25 वर्षों में 2050 तक कैंसर के नए मामलों में 60.7 फीसदी जबकि मौतों में 74.5 फीसदी की वृद्धि का अंदेशा है।

स्तन कैंसर से हर घंटे हो रही 76 महिलाओं की मौत

अध्ययन के मुताबिक सबसे तेज बढ़ोतरी कमजोर और मध्यम आय वाले देशों में होगी जहां कैंसर से होने वाली मौतों में करीब 91 फीसदी तक की बढ़ोतरी का अंदेशा है जबकि अमीर देशों में यह बढ़ोतरी करीब 43 फीसदी रह सकती है। 2023 में स्तन कैंसर सबसे आम था जबकि फेफड़ों का कैंसर सबसे ज्यादा मौतों का कारण बना। रिपोर्ट के मुताबिक तंबाकू मौत का सबसे बड़ा कारण है। दुनिया भर में कैंसर से होने वाली मौतों के 21 फीसदी के लिए जिम्मेवार तंबाकू जिम्मेदार है।। रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में पुरुषों में कैंसर से हुई 46 फीसदी और महिलाओं में 36 फीसदी मौतें इन रोके जा सकने वाले कारणों से जुड़ी पाई गई। इस दौरान पुरुषों के लिए प्रमुख जोखिम तंबाकू, शराब, खराब खानपान, कार्यस्थल पर जोखिम और वायु प्रदूषण रहे। वहीं महिलाओं में तंबाकू, असुरक्षित यौन संबंध, मोटापा और हाई ब्लड शुगर प्रमुख कारण रहे।अध्ययन में यह भी सामने आया है कि 2023 में कैंसर से जुड़ी करीब 42 फीसदी (43 लाख) मौतें ऐसे कारणों से हुई जिन्हें रोका जा सकता था।

भारत सरकार सचेत, केंद्रीय बजट 2025-26 में कैंसर देखभाल को प्राथमिकता

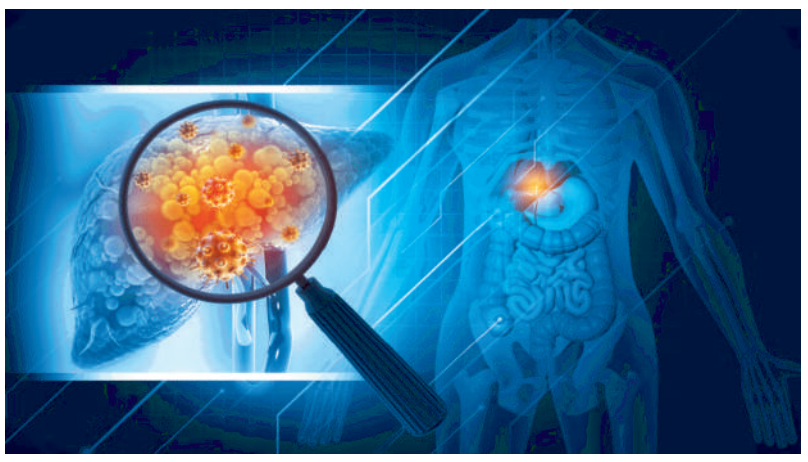

भारत में राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम (एनसीआरपी) 1982 से शुरू हुआ जिसके तहत कैंसर की घटनाओं, उनके बोझ और प्रवृत्तियों पर नज़र रखी जाती है। यह डेटा एकत्र करने और उनका विश्लेषण कर नीतिगत निर्णय लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। राष्ट्रीय कैंसर निवारण एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईसीपीआर) एनपीसीडीसीएस के अंतर्गत अनुसंधान और स्क्रीनिंग दिशानिर्देश तैयार करने वाली नोडल एजेंसी है। भारत सरकार ने देश भर में रोकथाम, शीघ्र पहचान, उपचार और रोगी देखभाल को बेहतर बनाने के लिए मज़बूत नीतियां, रणनीतिक हस्तक्षेप और वित्तीय सहायता योजनाएं शुरू की हैं। केंद्रीय बजट 2025.26 में कैंसर देखभाल को प्राथमिकता दी गई है। सरकार ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को कुल 99 हजार 858.56 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं जिसमें से 95 हजार 957.87 करोड़ रुपये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए और 3 हजार 900.69 करोड़ रुपये स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग के लिए निर्धारित हैं।

केंद्रीय बजट 2025-26 कई प्रमुख पहलों के माध्यम से कैंसर देखभाल को बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। सरकार अगले तीन वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर सेंटर स्थापित करने की योजना बना रही है जिसके लिए 2025-26 तक 200 केंद्र निर्धारित हैं। उपचार लागत को कम करने के लिएए कैंसर, दुर्लभ बीमारियों और पुरानी बीमारियों के इलाज के लिए 36 जीवन रक्षक दवाओं और औषधियों को मूल सीमा शुल्क (बीसीडी) से पूरी तरह छूट दी गई है। छह जीवन रक्षक दवाओं पर 5 फीसदी की रियायती सीमा शुल्क लागू होगा। इसके अलावा दवा कंपनियों द्वारा संचालित रोगी सहायता कार्यक्रमों के तहत निर्दिष्ट दवाओं और औषधियों को बीसीडी से पूरी तरह छूट दी गई है। भारत में 19 राज्य कैंसर संस्थान (एससीआई) 20 तृतीयक देखभाल कैंसर केंद्र (टीसीसीसी) हरियाणा के झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान और कोलकाता में चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान का दूसरा परिसर अत्याधुनिक कैंसर उपचार और अनुसंधान के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

आयुष्मान भारत योजना 30 दिनों के भीतर कैंसर रोगियों का समय पर उपचार सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए कैंसर के इलाज के लिए कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी को कवर करती है। स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि, राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत स्वास्थ्य मंत्री कैंसर रोगी निधि गरीबी रेखा से नीचे के रोगियों को कैंसर के इलाज के लिए 5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत अधिकतम स्वीकार्य वित्तीय सहायता 15 लाख होगी। यह 27 क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों में उपचार को कवर करती है। राष्ट्रीय कैंसर ग्रिड की स्थापना 2012 में पूरे भारत में उच्च गुणवत्ता वालीए मानकीकृत कैंसर देखभाल सुनिश्चित करने के लिए की गई थी। आठ साल बादए यह 287 सदस्यों के साथ दुनिया के सबसे बड़े कैंसर नेटवर्क के रूप में विकसित हो गया है जिसमें कैंसर केंद्र, अनुसंधान संस्थान, रोगी वकालत समूह, धर्मार्थ संगठन और पेशेवर समाज शामिल हैं।

दिल्ली में गिरी एक और इमारत, दो मंजिला मकान के मलबे में दबने से मां की मौत; बेटी जख्मी

पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में एक दो मंजिला इमारत ढह गई, जिससे कई लोग मलबे में दब गए। दमकल और एनडीआरएफ की टीमों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया और एक बच्ची व महिला को मलबे से निकाला। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बेटी जख्मी है। अन्य लोगों की तलाश जारी है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। उत्तम नगर थाना क्षेत्र स्थित हस्तसाल विहार में शुक्रवार दोपहर एक दो मंजिला इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे में मकान मालिक की पत्नी पूनम की मौत हो गई, वहीं पांच साल की बेटी नव्या मामूली रूप से घायल हो गई।

मकान के गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। आसपास के लोग तुरंत वहां पहुंचकर राहत बचाव के साथ-साथ घटना की जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। सूचना मिलते ही दमकल, पुलिस, एनडीआरएफ और राहत से जुड़ी अन्य एजेंसियों के कर्मचारी मौके पर पहुंच गए।

टीम ने मलबे को हटाने का काम शुरू कर दिया। कुछ देर में बचाव दल ने मलबे से पांच साल की बच्ची और एक महिला को बाहर निकालकर पास के अस्पताल में पहुंचाया। बच्ची को मामूली चोट लगी थी, वहीं महिला बेहोशी की हालत में थी।

अस्पताल में चिकित्सकों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। जिस महिला की मौत हुई है, उनका नाम पूनम है। जबकि घायल बच्ची उनकी बेटी नव्या है। जिसे प्राथमिक इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गई।

मलबे में अन्य लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए एजेंसियां मलबे हटाने का काम करने में जुट गई। अग्निशमन विभाग के अनुसार शुक्रवार दोपहर 3:10 बजे हस्तसाल गांव उत्तम नगर में एक दो मंजिला इमारत गिरने और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की सूचना मिली।

सूचना मिलते ही दमकल की पांच गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। मकान गिरने की आवाज आने के बाद आस पास के लोग तुरंत भागकर वहां पहुंचे और मलबा हटाने का काम करने में जुट गए। थोड़ी ही देर में गली में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई।

पुलिस ने लोगों को वहां से हटाकर घटनास्थल के पास घेराबंदी की। दमकल कर्मियों के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, एंबुलेंस और सिविक एजेंसी की टीम मौके पर पहुंच गई। टीम तुरंत मलबा हटाने में जुट गई।

दमकल कर्मियों ने अन्य लोगों की फंसे होने की आशंका को देखते हुए मलबा को हटाने में जुटे थे। करीब 6:50 बजे मलबा हटाने का काम खत्म हो गया। मलबा के नीचे और कोई नहीं मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि मकान जर्जर हालत में था। पुलिस मकान गिरने के कारणों की जांच कर रही है।

इतिहास का पलटवार: अब भारत देता है, ब्रिटेन लेता है

[लूट से नेतृत्व तक: ब्रिटेन के दरवाज़े पर भारत की दस्तक]

कभी वह दौर था, जब सूरज ब्रिटिश साम्राज्य पर नहीं डूबता था और भारत उसका सबसे कीमती लूट का रत्न था। दिल्ली, कोलकाता और मद्रास के खून-पसीने से लंदन की सड़कें चमकती थीं। जहाजों में ठूंसे गए भारतीय संसाधन और मजदूर ब्रिटेन के कारखानों में गुलामों-सा खटते थे। ब्रिटिश अहंकार दहाड़ता था कि भारत उनके बिना एक कदम भी नहीं चल सकता। लेकिन 10 अक्टूबर को, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर 125 उद्योगपतियों के साथ मुंबई की धरती पर उतरे, इतिहास ने पलटा खाया। आज भारत लूट का शिकार नहीं, बल्कि ब्रिटेन को निवेश का सहारा देने वाला शक्तिशाली राष्ट्र है। 64 भारतीय कंपनियों ने 1.3 बिलियन पाउंड (लगभग 13,800 करोड़ रुपये) के निवेश का ऐलान किया, जो ब्रिटेन में 6,900 नौकरियां पैदा करेगा। यह महज आर्थिक सौदा नहीं, बल्कि एक पूर्व उपनिवेश की वह हुंकार है, जो औपनिवेशिक शासक को घुटनों पर ला रही है। आइए, आंकड़ों और तथ्यों के साथ इस ऐतिहासिक क्षण की गहराई में उतरें।

18वीं सदी से 1947 तक, ब्रिटेन ने भारत को लूट का खुला अड्डा बनाए रखा। इतिहासकार यू.टी. पटेल के अनुसार, ब्रिटिश शासन ने भारत से 45 ट्रिलियन डॉलर (आज की कीमतों में) की संपदा चुराई। कपास, चाय, नील और अफीम के साथ भारतीय मजदूरों को भी जहाजों में भरकर अमानवीय हालात में ब्रिटेन भेजा गया। 1700 में वैश्विक जीडीपी में भारत की 25% हिस्सेदारी 1947 तक 3% पर सिमट गई। ब्रिटिश नीतियों ने भारत को जानबूझकर पिछड़ा रखा—रेलवे लूट के लिए, शिक्षा क्लर्क गढ़ने के लिए। मगर स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी नियति खुद लिखी। 1991 के उदारीकरण से लेकर डिजिटल इंडिया तक, भारत ने आत्मनिर्भरता का रास्ता चुना। आज विश्व बैंक के आंकड़े गवाही देते हैं: 3.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि 3.3 ट्रिलियन पर ठहरे ब्रिटेन को पछाड़ चुका है। यह उलटफेर संयोग नहीं, बल्कि दशकों की मेहनत और नीतिगत सुधारों का परिणाम है।

8-9 अक्टूबर को कीर स्टार्मर का भारत दौरा कूटनीति से कहीं बढ़कर था—यह ब्रिटेन की आर्थिक मजबूरी का जीवंत दस्तावेज था। उनके साथ आए 125-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में बीपी, रोल्स-रॉयस और बीटी जैसी दिग्गज कंपनियां शामिल थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता में जुलाई 2025 में हस्ताक्षरित यूके-इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) की समीक्षा हुई, जो 99% भारतीय निर्यात को ड्यूटी-फ्री पहुंच देता है। इस दौरे की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 1.3 बिलियन पाउंड के निवेश की घोषणा, जिसके तहत 64 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में 6,900 नौकरियां सृजित करेंगी। ये नौकरियां बेसिंगस्टोक से बर्मिंघम, लंदन से लिवरपूल तक फैलेंगी, जो इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों को नई गति देंगी। ब्रेक्सिट के बाद आर्थिक मंदी से जूझ रहे ब्रिटेन के लिए यह निवेश किसी संजीवनी से कम नहीं। यह पल न केवल आर्थिक है, बल्कि उस ऐतिहासिक घाव का प्रतीकात्मक जवाब है, जो भारत ने कभी सहा था।

भारत की आर्थिक ताकत अब विश्व मंच पर गूंज रही है। टीवीएस मोटर कंपनी 250 मिलियन पाउंड के निवेश से सोलिहुल में नॉर्टन मोटरसाइकिल्स का विस्तार करेगी, जहां इलेक्ट्रिक वाहन और 1,000 नौकरियां जन्म लेंगी। साइएंट इंजीनियरिंग 100 मिलियन पाउंड से सेमीकंडक्टर और स्वच्छ ऊर्जा में क्रांति लाएगी, जो ब्रिटेन को वैश्विक चिप युद्ध में बढ़त देगी। मस्तेक 2 मिलियन पाउंड से लंदन और लीड्स में एआई केंद्र स्थापित करेगी। एटुल-डेट पाम 11 मिलियन पाउंड से एग्री-टेक में सतत नवाचार लाएगी, तो नेओसेल्टिक ग्लोबल 5 मिलियन पाउंड से कार्डिफ और लंदन में 85 नौकरियों के साथ ऑर्थोपेडिक समाधान पेश करेगी। अल्कोर लॉजिस्टिक्स 4 मिलियन पाउंड से लिवरपूल में सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार, ये सौदे एफटीए के तीन महीनों में ही फल दे रहे हैं—भारत के प्रति वैश्विक विश्वास का जीवंत प्रमाण।

ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन आर्थिक तूफान में फंसा है। 2024 में इसकी विकास दर महज 0.6% रही, महंगाई 2.5% पर अटकी, और बेरोजगारी 4.4% तक पहुंची, जिसमें युवा बेरोजगारी 13% के करीब है। ऐसे में भारतीय निवेश ब्रिटिश श्रमिकों के लिए संजीवनी है। स्टार्मर ने स्वीकारा, ₹ये निवेश हमारे लोगों की जेब में पैसा डालेंगे।₹ लेकिन विडंबना देखिए: जिस ब्रिटेन ने कभी भारत को ₹अक्षमऱ ठहराया, आज वह उसकी पूंजी पर निर्भर है। यूके में 950 भारतीय कंपनियां पहले से 600,000 नौकरियां दे रही हैं, और 2.6% भारतीय डायस्पोरा वहां की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यह आर्थिक जीत ही नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक विजय है—एक पूर्व उपनिवेश का अपने शासक को सहारा देना।

यह भारत के गर्व का क्षण है, मगर चुनौतियां बाकी हैं। स्टार्मर ने वीजा नियमों में ढील देने से इनकार किया, जो भारतीय पेशेवरों के लिए रुकावट है। फिर भी, यूके-इंडिया विजन 2035 रोडमैप—जो व्यापार, तकनीक, रक्षा, और जलवायु पर केंद्रित है—भविष्य की नींव रखता है। 7% विकास दर, 1 लाख से अधिक स्टार्टअप्स, और डिजिटल इंडिया की ताकत ने भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का केंद्र बनाया है। सेमीकंडक्टर से स्वच्छ ऊर्जा तक, भारत अब सिर्फ बाजार नहीं, नवाचार का स्रोत है।

यह कहानी निवेश की नहीं, शक्ति के उलटफेर की है। कभी ₹सूर्यास्त न होने वाला साम्राज्यऱ कहलाने वाला ब्रिटेन आज भारत की छाया में सांस ले रहा है। 1.3 बिलियन पाउंड और 6,900 नौकरियां महज आंकड़े नहीं, इतिहास का प्रतिशोध हैं। जैसा कि मोदी ने कहा, ₹यह साझेदारी नई ऊर्जा और विश्वास की है।₹ भारत अब सहारा नहीं मांगता, देता है। मगर सतर्कता जरूरी है—वैश्विक मंच पर संप्रभुता बनाए रखते हुए। यह वह क्षण है, जब भारत ने न केवल अपनी आजादी, बल्कि अपनी श्रेष्ठता साबित की। यह यात्रा अभी शुरू हुई है—एक ऐसे भविष्य की ओर, जहां भारत विश्व का नेतृत्व करेगा।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी (मप्र)

₹20,000 करोड़ से अधिक के विशाल बाजार में रणनीतिक प्रवेश का संकेत

मुख्य संवाददाता

भारत की अग्रणी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल कंपनियों में से एक क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आज एक ऐतिहासिक उपलब्धि की घोषणा की, कंपनी ने तेलंगाना बाजार में ₹52 करोड़ का अपना पहला बड़ा सोलर रूफटॉप ऑर्डर प्राप्त किया है।

यह रणनीतिक कदम क्रॉम्पटन की सतत ऊर्जा समाधान क्षेत्र में वृद्धि को गति देने की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। अपने विश्वसनीय ब्रांड, मजबूत वितरण नेटवर्क और तेजी से विस्तार की क्षमता के बल पर कंपनी इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की मजबूत स्थिति में है।

क्रॉम्पटन ₹20,000-₹25,000 करोड़ के बड़े और बढ़ते सोलर रूफटॉप बाजार का लाभ उठाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जिसके 20% से अधिक की तीव्र गति से बढ़ने की उम्मीद है।

यह महत्वपूर्ण उपलब्धि क्रॉम्पटन के सोलर रूफटॉप श्रेणी में व्यावसायिक पदार्पण को मजबूत बनाती है और कंपनी को भारत के सौर ऊर्जा बाजार में एक विश्वसनीय एवं सक्षम खिलाड़ी के रूप में स्थापित करती है।

सोलर रूफटॉप क्षेत्र में क्रॉम्पटन का प्रवेश इसके व्यापक रणनीतिक लक्ष्य के अनुरूप है, जिसके तहत कंपनी अपने कुल संबोधित किए जा सकने वाले बाजार (Total Addressable Market - TAM) को ₹75,000–₹1 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹2 लाख करोड़ तक विस्तारित करना चाहती है।

इस अवसर पर प्रोमीत घोष, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने कहा, "नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, विशेष रूप से सोलर रूफटॉप सेगमेंट, भारत के ऊर्जा परिदृश्य में परिवर्तनकारी अवसर प्रस्तुत करता है। इस सेगमेंट में क्रॉम्पटन का प्रवेश हमारी सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हमारा उद्देश्य केवल उच्च प्रदर्शन और नवोन्मेषी उत्पादों की आपूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत के हरित ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एक प्रमुख योगदानकर्ता बनना भी है, जिससे क्रॉम्पटन की तीव्र वृद्धि के साथ राष्ट्र के लिए एक सतत भविष्य का निर्माण हो सके।"

उन्होंने आगे कहा, " हमारा पहला बड़ा सोलर रूफटॉप ऑर्डर हासिल करना इस श्रेणी में एक अहम मील का पत्थर है। यह हमारी क्षमताओं को प्रमाणित करता है और ऐसे क्षेत्र में तीव्र वृद्धि के लिए आधार तैयार करता है, जिसमें जबरदस्त मांग देखी जा रही है। अपनी ब्रांड की साख और वितरण क्षमता का लाभ उठाते हुए, हम उपभोक्ताओं और पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सार्थक मूल्य सृजन के लिए पूरी तरह तैयार हैं।हम सार्थक प्रभाव पैदा करने और अपने उपभोक्ताओं और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को मूल्य प्रदान करने के लिए अच्छी स्थिति में हैं। ₹20,000–₹25,000 करोड़ के इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, और हम नवाचार व उत्कृष्टता के साथ अपना विस्तार जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

भारत की सौर ऊर्जा क्षमता का सक्रिय रूप से उपयोग करते हुए, क्रॉम्पटन अपने पर्यावरण, सामाजिक एवं शासन (ईएजी) लक्ष्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और मजबूत कर रहा है तथा भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं की अगली लहर का लाभ उठाने के लिए एक दूरदर्शी कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लीडर के रूप में अपनी भूमिका को सुदृढ़ कर रहा है।

अमिताभ बच्चन, भारतीय सिनेमा का अमर दीप, मेहनत के रास्ते शिखर तक,

डॉ.मुश्ताक अहमद शाह

सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भारतीय सिनेमा की उस विराट मूर्ति का नाम हैं, जो न केवल कला जगत बल्कि करोड़ों दिलों की धड़कन में रचे बसे हैं, प्रयागराज शहर में जन्मे कविता की संवेदनाओं और संस्कृति के संस्कारों में पले अमिताभ ने संघर्ष के सुरों में जीवन रचा, प्रारंभिक फिल्मों में विफलता का स्वाद चखा, बार-बार नकारे गए, आवाज़ और कद पर सवाल उठाए गए, पर उन्होंने हार नहीं मानी, मंच पर जूझते रहे, अभिनय से अपना अस्तित्व गढ़ा, पहली सफलता 'ज़ंजीर' से मिली, जब एंग्री यंग मैन के रूप में समाज के आक्रोश को स्वर मिला, शोले, दीवार, डॉन, त्रिशूल, नमक हलाल, मुकद्दर का सिकंदर, सिलसिला, कभी-कभी, अग्निपथ,हर फिल्म में अमिताभ ने चरित्रों को जीने का नया अर्थ दिया, उनकी अभिनय शैली, संवाद अदायगी और व्यक्तित्व ने फैंस का दिल जीत लिया, कुली की शूटिंग के दौरान घातक हादसे के बाद देशभर में प्रार्थनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा, वे मौत के मुहाने से लौटे, तभी से वे सिर्फ कलाकार नहीं, बल्कि देश के अभिमान बन गए, रचनात्मकता, अनुशासन, निरंतरता, संघर्ष, नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई, कौन बनेगा करोड़पति जैसे कार्यक्रमों ने उनकी लोकप्रियता को घर-घर पहुँचाया, विज्ञापन, सामाजिक कार्य, जनजागरण से वे लगातार समाज को दिशा देते रहे, अमिताभ केवल अभिनय में महान नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व में भी अनुकरणीय हैं, अनेक राष्ट्रीय,अंतरराष्ट्रीय सम्मान, पद्म पुरस्कार, डॉक्टरेट, उनकी उपलब्धियां हैं, उन्होंने यह साबित किया कि जीवन की कठिनाइयाँ केवल परीक्षा हैं, हार केवल एक पड़ाव, जो मेहनत के रास्ते नए शिखर तक ले जाती है, अमिताभ बच्चन का हर शब्द आज भी उनके चाहने वालों के लिए प्रेरणा है, जन्मदिन पर भारत की कला, संस्कृति और सिनेमा का यह भीष्म पितामह हमारे अभिमान का उज्ज्वल नक्षत्र है।

'डर्टी एंटरटेनर्स: द बिज़नेस ऑफ़ इंडियन इरोटिका' ने दिखाए परदे के पीछे का सच

मुख्य संवाददाता

नई दिल्ली, आईएन10 मीडिया नेटवर्क के वैश्विक डॉक्यूमेंट्री प्लेटफ़ॉर्म डॉक्यूबे ने अपनी नई और साहसिक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्री 'डर्टी एंटरटेनर्सः द बिज़नेस ऑफ़ इंडियन इरोटिका' रिलीज़ की है। हीना डी'सूजा के निर्देशन और ह्यूमरा मूवी (HumaraMovie) के निर्माण में बनी यह फ़िल्म भारत के भूमिगत इरोटिका उद्योग की उस हकीकत को सामने लाती है, जो अब तक परदे के पीछे रही है।

डॉक्यूमेंट्री में इस उद्योग से जुड़े कलाकारों और निर्माताओं की निजी कहानियों के ज़रिए यह दिखाया गया है कि सेंसरशिप, सामाजिक कलंक और ओटीटी प्रतिबंधों के बीच यह इंडस्ट्री कैसे अपने अस्तित्व को बनाए रखती है। फ़िल्म में शेक्सपीयर, माया जाफ़र और राजसी वर्मा जैसे नामचीन कलाकारों के

साक्षात्कार शामिल हैं, जो इस दुनिया की सच्चाई और संघर्ष को खुलकर सामने रखते हैं।

आईएन10 मीडिया नेटवर्क के प्रबंध निदेशक आदित्य पिट्टी ने कहा, "हमारी कोशिश हमेशा से ऐसे विषयों पर काम करने की रही है, जिन पर लोग खुलकर बात नहीं करते। 'डर्टी एंटरटेनर्स' एक ऐसा ही प्रयास है जो बोल्ड, प्रासंगिक और वास्तविक है।"

DocuBay के मुख्य परिचालन अधिकारी समर खान ने कहा, "यह डॉक्यूमेंट्री सिर्फ इरोटिका की दुनिया नहीं दिखाती, बल्कि उसके आर्थिक पक्ष, कंटेंट और सेंसरशिप के जटिल रिश्ते को भी उजागर करती है।"

निर्माता अभिषेक गौतम ने बताया, "हमने उन कलाकारों को मंच देने की कोशिश की है जो इस उद्योग में वर्षों से काम कर रहे हैं लेकिन कभी अपनी बात खुलकर नहीं कह पाए। DocuBay के माध्यम से यह कहानी वैश्विक दर्शकों तक पहुँचेगी।"

निर्देशक हीना डी'सूजा के अनुसार, "इस फ़िल्म का मक़सद इस दुनिया को इंसानियत की नज़र से दिखाना था — बिना निर्णय के, सिर्फ़ सच्चाई के साथ।"

निजी पानी टैंकरों पर एनजीटी प्रतिबंध अनुचित और अव्यवहारिक

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली भाजपा पूर्व विधायक डॉ. विजय जौली ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के 28 मई 2025 के न्यायिक आदेश पर आपत्ति दर्ज की। जिसमें दिल्ली में निजी पानी के टैंकरों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया गया है। डॉ. जौली ने इसे अनुचित व अव्यवहारिक बताया क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दिल्ली के 2.23 करोड़ नागरिकों को अपर्याप्त मात्रा में पानी की आपूर्ति हो रही है।

डॉ. जौली ने बताया कि दिल्ली में पानी की मांग 1,290 गैलन प्रतिदिन (एमजीडी) है। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड केवल 990 एमजीडी पानी की आपूर्ति कर पाता है। इस कमी को निजी पानी के टैंकर पूरा करते हैं। निजी टैंकरों पर प्रतिबंध से दिल्ली में भ्रष्टाचार व बेरोजगारी बढ़ेगी।

भाजपा नेता डॉ. जौली ने आगे कहा कि दिल्ली की 1,731 अनधिकृत कॉलोनियों में 50 लाख गरीब नागरिक रहते हैं। दिल्ली जल बोर्ड उनकी पीने के पानी की मांग को पूरा करने में असमर्थ है। दि.ज.बो. का पानी टैंकर मांग के 3 से 4 दिनों के उपरांत उपलब्ध होता रहा है।

लेकिन दिल्ली जल बोर्ड द्वारा हाल ही में शुरू की गई 1,111 जीपीएस-सक्षम जल टैंकरों की योजना को डॉ. जौली ने सराहा। लेकिन उन्होंने इसे दिल्ली में पानी की मांग और आपूर्ति के अंतर को पाटने के लिए बहुत कम और अपर्याप्त बताया।

डॉ. जौली ने निजी जल टैंकरों को दिल्ली की जीवन रेखा कहा। यह न केवल अमीर और गरीब की प्यास बुझाते हैं अपितु दिल्ली के निर्माण कार्यों में भी अथक मदद करते हैं। इस लिए दिल्ली में बिना पर्याप्त जलापूर्ति की व्यवस्था किये, एनजीटी के हालिया आदेश को डॉ. जौली ने अनुचित व अव्यवहारिक करार दिया। डॉ. जौली ने दिल्ली सरकार से इस मामले पर तुरंत संज्ञान लेने तथा हस्तक्षेप करने की मांग भी की।

राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ कर रही है :- राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरजीत कुमार

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली। विश्व हिंदू परिषद दिल्ली प्रांत की ओर से रोहिणी शिव बालेश्वर मंदिर दिल्ली में भव्य रूप से मनाई गई भगवान वाल्मीकि जयंती। इस आयोजन में मिलिंद परांडे जी संगठन महामंत्री -विश्व हिंदू परिषद का उद्बोधन रहा । उन्होंने कहा की हम सब एक ही ऋषि की संताने हैं । समय काल खण्ड में जो असमानताएं/कटुताऐ आ गई हैं;उन्हें दूर करने का काम हम सभी का हैं ।विश्व हिंदू परिषद सामाजिक समरसता पर काम कर रही है ।समाज को एक सूत्र में बांधने का काम बड़ी तेजी से हो रहा है ।इसके अच्छे परिणाम जल्द देखने को मिलेंगे.. भगवान महर्षि वाल्मीकि जी केवल लेखन में ही दक्ष नहीं थे बल्कि वे स्वयं 64 युद्ध कलाओं में भी परांगत थे। उन्होंने लव-कुश को युद्ध कलाएं सिखाई , रामायण को कैसे गा कर सुनाया जा सकता है;

उन्होंने लव-कुश को सिखाया। वह स्वयं आदर्श व्यक्तित्व के धनी थे ;इसीलिए उन्होंने प्रभु राम को एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत किया ।विश्व हिंदू परिषद भगवान महर्षि वाल्मीकि की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेगा ।

कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सुरजीत कुमार ने कहा हम सभी का उद्गम एक जगह से हुआ है और हम सभी को एक जगह ही जाना है तो फिर; ऊंच-नीच ;जाति -पाति का कोई अर्थ नहीं है। प्रत्येक जन समान है ।जब ईश्वर ने कोई असमानता नहीं दिखाई तो हम कौन होते हैं समाज को बांटने वाले। राष्ट्रीय हित में अपनी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने का काम शिरोमणि गुरु रविदास विश्व महापीठ कर रही है। उन्होंने भगवान वाल्मीकि की जयंती की सभी को बधाई दी ।श्री गुरु रविदास मंदिर तुगलकाबाद दिल्ली की जगह को सरकार ने समाज को 23/9/25 को सौंप दिया ।इसके लिए सरकार का अभिनंदन किया और समाज को बधाई दी।

कार्यक्रम में साध्वी रेणुका जी ने भी सभी को आशीर्वचन दिया ।कार्यक्रम में मुख्य रूप से वरिष्ठ प्रचारक भाला जी, सुबोध जी प्रांत संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद, ओंकार जी प्रांत समरसता प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, मनोज कुमार आजाद जी अध्यक्ष दिल्ली प्रांत श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, विक्रम जीत जी राष्ट्रीय मंत्री श्री गुरु रविदास विश्व महापीठ, अशोक जी राष्ट्रीय महामंत्री ज्वेलर्स संघ, मधुसूदन शर्मा जी, भगत सिंह जी, कृष्णा पासवान जी, धारा सिंह जी, रामजीत जी, चंद्र कुमार जी, दिनेश शर्मा जी, विजय मल्होत्रा जी, कृष्ण भारद्वाज जी, सुखविंदर जी नरेंद्र कुमार जी, विनय कुमार जी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।

हमें अपने व्यापार, रोजगार और संस्कृति की रक्षा के लिए स्वदेशी को जीवनशैली में शामिल करना होगा - यदि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो स्वदेशी को व्यवहार में उतारना ही एकमात्र रास्ता

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा, संजय साग़र सिंह। देशहित में, वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने सभी देशवासियों से स्वदेशी वस्तुओं को प्राथमिकता देने और विदेशी ऑनलाइन कंपनियों के बहिष्कार के लिए देशभर में जनजागरण यात्रा अभियान चलाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यदि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, तो स्वदेशी को व्यवहार में उतारना ही एकमात्र रास्ता है।

श्री खुराना ने विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं से आग्रह किया कि वे खरीदारी करते समय स्वदेशी उत्पादों को ही चुनें। जब हम विदेशी कंपनियों के उत्पादों को खरीदते हैं, तो हमारे देश की पूंजी विदेश चली जाती है और देश की आर्थिक नींव कमजोर होती है।

उन्होंने विशेष रूप से अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी विदेशी ऑनलाइन कंपनियों से दूरी बनाने का सुझाव देते हुए कहा कि ये प्लेटफॉर्म देश की खुदरा बाजार व्यवस्था को प्रभावित कर रहे हैं और देशी कारोबारियों के लिए संकट का कारण बन रहे हैं।

उन्होंने सभी व्यापारियों और नागरिकों से इस आंदोलन में सक्रिय सहयोग देने की अपील की। उन्होंने सुझाव दिया कि देशभर में जनजागरण अभियान चलाया जाए और दुकानों पर स्वदेशी अपनाओ के स्टिकर लगाकर इस मुहिम की शुरुआत की जाए।

आखिर में वरिष्ठ समाजसेवी राजेश खुराना ने कहा, स्वदेशी अपनाना केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि यह देशभक्ति का प्रतीक है। हमें अपने व्यापार, रोजगार और संस्कृति की रक्षा के लिए स्वदेशी को जीवनशैली में शामिल करना ही होगा। स्वदेशी अपनाने से देश की आर्थिक नींव और भी मजबूत होंगी। इसलिए खरीदारी करते समय देशहित में स्वदेशी उत्पादों को ही चुनें।

बिल्सी थाना पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता बड़ी चोरी की घटना का खुलासा

परिवहन विशेष न्यूज

गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से चोरी किये हुए 02 लाख 70 हजार रुपये व 03 अदद तमंचा (315 बोर) व 03 अदद जिन्दा कारतूस व 03 अदद खोखा कारतूस(315 बोर) व एक अदद पिकअप गाडी (UP 25 DT 5910) बरामद की गयी।

मुखबिर खास सूचना मिली एक पिकअप गाडी जिस पर अमर उजाला प्रेस लिखा है और उघैती की तरफ से आ रही है जिसमे संदिग्ध व्यक्ति है। थोडी देर बाद सामने से आती एक पिकअप गाडी को रोकने का इशारा किया गया तो उक्त पिकअक के चालक ने पुलिस पार्टी को देखकर एकदम सकपकाकर गाडी को बिल्सी की ओर भगाने लगा तभी सामने वाली सीट पर बैठे दोनों व्यक्तियों ने गाडी के दाहिने व बायी खिडकी से पुलिस पार्टी की तरफ जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर किये जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा अपने आप को बचाते हुए घेरकर आवश्यक बल प्रयोग कर उक्त पिकअप गाडी को बडनोमी तिराहा पर रोक लिया। पिकअप में सवार 04 अभियुक्तों को पकड लिया। गिरफ्तार अभि0गण से पूछताछ की गयी तो बताया कि साहब हम लोग इस पिकअप में मछली बेचने जाते है और मछली बेचने की आड में हम चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। हम लोग मिलकर अपने आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये लोगो के घरो में दीवार से कूद कर चोरी कर लेते है और चोरी करने के बाद इसी पिकअप गाडी से भाग जाते है जिससे लोग हम लोगों पर शक भी नही कर पाते है। हम लोगो नें मिलकर कुछ दिन पहले थाना उझानी क्षेत्र में चोरी की घटना की थी तथा 20 दिन पहले थाना बिल्सी क्षेत्र के ग्राम हरदासपुर व ग्राम पिण्डोल में चोरी की थी । थाना बिल्सी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरदासपुर में हुई चोरी की घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0376/25 धारा 305/331(4) बी0एन0एस0 व ग्राम पिण्डोल में हुई चोरी की घटना से सम्बन्ध में मु0अ0सं0 0377/25 धारा 305/331(4) बी0एन0एस0 पंजीकृत है । अभियुक्तगण की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के आधार पर थाना बिल्सी पर मु0अ0सं0 402/25 धारा 109 बी0एन0एस0 (पु0 मुठभेड) व 3/25/27(1-B)(a) आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । गाडी पिकअप UP 25 DT 5910 को सीज किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण व बरामद माल को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. मनुआ पुत्र शादिक उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
2. बनिया पुत्र नूर मौहम्मद उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
3. आजिम मिया पुत्र महेन्दी हसन उम्र करीब 35 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली
4. हनीफ पुत्र हव्वन उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली

अभियुक्तगण से बरामदगी का विवरण-

1. अभियुक्त मनुआ उपरोक्त से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस व कुल 70000/- रुपये व बरामद ।
2. अभियुक्त आजिम मिया उपरोक्त से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस व कुल 67500/- रुपये बरामद ।
3. अभियुक्त हनीफ उपरोक्त से एक अदद तमंचा 315 बोर तथा 01 जिन्दा कारतूस व एक खोखा कारतूस व कुल 72500/- रुपये बरामद ।
4. अभियुक्त बनिया उपरोक्त से 60000/- रुपये व एक अदद पिकअक UP 25 DT 5910 बरामद

आपराधिक इतिहास (मनुआ पुत्र शादिक उम्र करीब 30 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली)

1. मु0अ0सं0 376/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी, बदायूँ
2. मु0अ0सं0 377/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी, बदायूँ
3. मु0अ0सं0 402/25 धारा 109 BNS 3/25/27(1-b)a A ACT थाना बिल्सी, बदायूँ
4. मु0अ0सं0 396/25 धारा 305 BNS थाना उझानी बदायूँ

आपराधिक इतिहास (बनिया पुत्र नूर मौहम्मद उम्र करीब 42 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली)

1. मु0अ0सं0 376/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी बदायूँ
2. मु0अ0सं0 377/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी बदायूँ
3. मु0अ0सं0 402/25 धारा 109 BNS 3/25/27(1-b)a A ACT थाना बिल्सी, बदायूँ
4. मु0अ0सं0 396/25 धारा 305 BNS थाना उझानी बदायूँ

आपराधिक इतिहास (आजिम मिया पुत्र महेन्दी हसन उम्र करीब 35 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली)

1. मु0अ0सं0 376/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी बदायूँ
2. मु0अ0सं0 377/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी बदायूँ
3. मु0अ0सं0 402/25 धारा 109 BNS 3/25/27(1-b)a A ACT थाना बिल्सी, बदायूँ
4. मु0अ0सं0 396/25 धारा 305 BNS थाना उझानी बदायूँ

आपराधिक इतिहास (हनीफ पुत्र हव्वन उम्र करीब 45 वर्ष नि0 ग्राम अगूरी टाडा थाना सुभाषनगर जनपद बरेली)

1. मु0अ0सं0 376/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी बदायूँ
2. मु0अ0सं0 377/25 धारा 305/331(4) BNS थाना बिल्सी बदायूँ
3. मु0अ0सं0 402/25 धारा 109 BNS 3/25/27(1-b)a A ACT थाना बिल्सी, बदायूँ
4. मु0अ0सं0 396/25 धारा 305 BNS थाना उझानी बदायूँ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. निरीक्षक मनोज कुमार थाना बिल्सी बदायूँ मय टीम
2. प्रभारी निरीक्षक SOG श्री माधौ सिह विष्ट मय टीम
3. उ0नि0 श्री राजेश कौशिक SOG टीम
4. उ0नि0 श्री धर्वेन्द्र सिह प्रभारी सर्विलांस मय टीम

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में एक्शन शुरू हो गया है....

अंकित गुप्ता

हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या मामले में एक्शन शुरू हो गया है. चंडीगढ़ पुलिस ने हरियाणा पुलिस के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर समेत उन 13 अधिकारी व पूर्व अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है, जिनके नाम सुसाइड नोट में लिखे गए थे. यह FIR सेक्टर-11 पुलिस थाने में दर्ज की गई.

2001 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने कई पन्नों के सुसाइड नोट में कुल 13 अधिकारियों के नाम लिए थे, जिनमें हरियाणा डीजीपी शत्रुजीत कपूर और रोहतक के SP नरेंद्र बिजारनिया के भी नाम हैं. उनके सुसाइड नोट में उन्होंने आरोप लगाया कि वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें मानसिक प्रताड़ना, जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न का शिकार बनाया, जिससे वे मानसिक रूप से टूट गए और यह दुखद कदम उठा रहे हैं.

FIR दर्ज, जांच प्रक्रिया शुरू

गुरुवार को चंडीगढ़ पुलिस ने FIR संख्या 156 दर्ज की. यह एफआईआर BNS की धारा 108 (आत्महत्या के लिए उकसाने) और एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. पुलिस का कहना है कि FIR वाई पूरन कुमार के अंतिम सुसाइड नोट में उल्लिखित सभी आरोपियों के खिलाफ दर्ज की गई है. पुलिस के अनुसार, जांच अभी जारी है और सभी साक्ष्यों, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड्स और प्रशासनिक कागजात की समीक्षा की जा रही है.

IAS पत्नी ने भी पुलिस में दी थी शिकायत

कुमार के आरोपों के आधार पर उनकी पत्नी और वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनीत पी. कुमार ने भी बुधवार को सेक्टर 11, चंडीगढ़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में डीजीपी और एसपी रोहतक पर उनके पति को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, जातिगत भेदभाव करने और उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप लगाए गए थे.

अमनीत कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भी लिखित पत्र भेजकर मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की थी. इसके साथ ही उन्होंने अपने पति का पोस्टमार्टम भी रुकवा दिया था. सूत्रों के मुताबिक, पोस्टमॉर्टम की अनुमति मिलने तक शव को सेक्टर 16 अस्पताल के शवगृह में रखा गया है.

मुख्यमंत्री का हस्तक्षेप और परिवार से मुलाकात

मुख्यमंत्री नायब सैनी ने मामले में सक्रिय हस्तक्षेप किया. उन्होंने गुरुवार को पहले डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर से मुलाकात की और जांच की स्थिति का जायजा लिया. इसके कुछ ही घंटे बाद मुख्यमंत्री दिवंगत आईपीएस

अधिकारी के परिवार से मिलने उनके सेक्टर 11 स्थित आवास पहुंचे. मुख्यमंत्री ने परिवार को भरोसा दिलाया कि जांच निष्पक्ष और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी. उन्होंने कहा कि जांच में किसी भी तरह का दबाव नहीं डाला जाएगा और सभी आरोपों की गंभीरता से समीक्षा की जाएगी.

इसके बाद से ही चर्चा थी कि हरियाणा डीजीपी को छुट्टी पर भेजा जा सकता है. उनकी जगह ओपी सिंह को कार्यवाहक डीजीपी बनाए जाने की संभावना है. इसी तरह रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया को भी छुट्टी पर भेजे जाने की चर्चा है.

परिवार की चार प्रमुख मांगें

आईएएस अमनीत कुमार ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में चार प्रमुख मांगें रखी थीं. सुसाइड नोट में नामित सभी व्यक्तियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज की जाए. सभी

आरोपियों को तुरंत निलंबित और गिरफ्तार किया जाए ताकि जांच पर कोई प्रभाव न पड़े. परिवार, विशेषकर उनकी दो बेटियों को स्थायी सुरक्षा कवर प्रदान किया जाए. परिवार की गरिमा और अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, क्योंकि वे अभी भी डर और मानसिक दबाव में हैं.

इन मांगों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने FIR दर्ज की और जांच प्रक्रिया शुरू की.

सुसाइड नोट में 13 अफसरों पर आरोप

वाई पूरन कुमार के सुसाइड नोट में कुल 13 वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आरोप थे, जिनमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, पूर्व मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, पूर्व एसीएस राजीव अरोड़ा, डीजीपी हरियाणा शत्रुजीत सिंह कपूर, रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं.

उन्होंने लिखा कि मेरे बैचमेट्स मनोज यादव, पी.के. अग्रवाल और टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने मिलकर जातिगत उत्पीड़न किया. मैंने गृह मंत्री और मुख्य सचिव को लिखित शिकायत दी, पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. आईपीएस कुलविंदर सिंह ने उन्हें फोन पर चेतावनी दी कि डीजीपी ने आदेश दिया है कि तुम्हें स्थायी रूप से हटाया जाएगा, संभल जाओ. वहीं आईपीएस माटा रवि किरण ने उनके प्रति आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिसे उन्होंने आत्महत्या का मुख्य कारण बताया. उन्होंने अंतिम पन्ने में लिखा मैं अब और नहीं सह सकता. जो लोग मुझे इस स्थिति तक लाए, वही मेरी मौत के जिम्मेदार हैं.

साउंडप्रूफ बेसमेंट में गोली मारकर की थी आत्महत्या

बता दें कि वाई पूरन कुमार ने मंगलवार को अपने घर के साउंडप्रूफ बेसमेंट में सर्विस गन से गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी. सुसाइड से एक दिन पहले 6 अक्टूबर को वाई पूरन कुमार ने अपनी वसीयत भी तैयार की थी जिसमें उन्होंने अपनी सारी चल-अचल संपत्ति पत्नी अमनीत पी. कुमार के नाम की. उसी दिन उन्होंने आत्महत्या नोट भी लिखा और पत्नी को भेजा.

घटना के समय अमनीत पी. कुमार जापान में मुख्यमंत्री नायब सैनी के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल में थीं. उन्होंने अपने पति को 15 बार कॉल किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. चिंतित होकर उन्होंने अपनी बेटी अमुल्या से संपर्क किया, जिसने घर जाकर अपने पिता को बेसमेंट में मृत पाया. #ypurankumar #ips

भागवत मूर्ति डॉ. शिवकरण पाण्डेय महाराज का आराधन महामहोत्सव 12 अक्तूबर को

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। आनन्द वाटिका क्षेत्र स्थित कल्पतरु कृपा आश्रम में संस्कृत के प्रकांड विद्वान, भागवत मूर्ति स्वर्गीय डॉ. शिवकरण पाण्डेय महाराज का आराधन महामहोत्सव 12 अक्तूबर 2025 को प्रातः 08 बजे से अत्यन्त श्रद्धा एवं धूमधाम के साथ आयोजित किया जाएगा। जानकारी देते हुए डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने बताया है कि महोत्सव के अंतर्गत प्रातः 08 बजे समस्त भक्तों-श्रद्धालुओं एवं शिष्य परिकर के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के मध्य स्वर्गीय डॉ. शिवकरण पाण्डेय महाराज के चित्रपट का पूजन-अर्चन किया जाएगा।तत्पश्चात वृहद सन्त-विद्वत सम्मेलन आयोजित होगा।जिसमें कई प्रख्यात संत-विद्वान और धर्माचार्य आदि भाग लेंगे।मध्याह्न 12 बजे से संत,ब्रजवासी, वैष्णव सेवा एवं वृहद भंडारा आदि के आयोजन होंगे। महोत्सव के संयोजक आचार्य नेत्रपाल शास्त्री ने सभी से इस महोत्सव में शामिल होने का आग्रह किया है।

आचार्य पंडित ऋषि राहुल का जन्मदिवस बहुत ही धूम धाम से उनके अनुयायियों द्वारा आयोजित कर मनाया गया

फरीदाबाद हरियाणा में आचार्य पंडित ऋषि राहुल जी का जन्मदिवस बहुत ही धूम धाम से उनके अनुयायियों द्वारा आयोजित कर मनाया गया। इस आयोजन में उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए हवन किया गया और तत्पश्चात भंडारे के प्रसाद वितरण का पवित्र कार्य किया गया । पंडित ऋषि राहुल जी से समाचार पत्रिका की खास बातचीत में उनसे काफी बाते पूछने पर जानकारियां प्राप्त हुई । पंडित ऋषि राहुल जी के यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे पॉडकास्ट हुए है और इनके अपने चैनल पर भी हजारों में इनके फॉलोवर है । पंडित ऋषि राहुल जी एक वैदिक ज्योतिषी हैं और भगवान भैरव नाथ जी की साधना में ज्यादा समय व्यतीत करते है । अपने साथ हुई बातचीत में उन्होंने अपने अनुभव भी बताए कि किस तरह आज की युवा शिक्षित पीढ़ी को बहुत से लोगों ने भ्रमित किया हुआ है और विशेष साधना करने के नाम पर उनके जीवन में नुकसान हुआ है । युवाओं को जागरूक करने के लिए ही उन्होंने अपने सभी पॉडकास्ट में काफी मनो उत्साहित बातों पर जोर दिया है । पंडित ऋषि राहुल जी ने बताया कि उन्होंने समाज कल्याण के लिए एक पुस्तक ऋषि अमृतमय को भी लिखा है और उसका पब्लिकेशन अभी चल रहा है और शीघ्र ही वह पुस्तक का विमोचन करेंगे ।

पंडित ऋषि राहुल जी ने मानवता के लिए धर्म कार्य करने को ही सबसे बड़ी ईश्वर की साधना और पूजा बताया है । उनका कहना है कि ईश्वर को आप उस मूर्ति में भी देख सकते है जिसका निर्माण स्वयं ईश्वर ने किया है अर्थात मानव । पंडित ऋषि राहुल जी पिछले ग्यारह वर्षों से वैदिक ज्योतिषी के माध्यम से लोगो का मार्गदर्शन कर चुके है । काफी अच्छे और कुछ लोगों को सहयोग से इन्होंने फरीदाबाद में एक ऐसी यज्ञशाला बनाने का संकल्प लिया है कि कोई भी व्यक्ति या परिवार निःशुल्क या बहुत ही कम शुल्क में पूजा पाठ, हवन अथवा अनुष्ठान करवा सके । पंडित ऋषि राहुल जी ने कहा कि ऐसा संकल्प उन्होंने इसलिए लिया है क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग इसलिए भी अनुष्ठान एवं पूजा हवन से प्राय परहेज करते है क्योंकि यह सब जगह , फ्लैट , या महंगा पड़ जाता है ।।

फिर विद्वान की दक्षिणा और समान ।

इसलिए पंडित ऋषि राहुल जी ने बताया कि वो ऐसा योजना के साथ ये कार्य करने के लिए संकल्पित है ताकि दक्षिणा और समान मिला कर एक सिद्ध यज्ञशाला में भक्त अपनी मनोकामना या कार्य सिद्धि का हवन पूजा पाठ अथवा अनुष्ठान कर सके और कहीं भी उन्हें पंडित , या समान किसी चीज के लिए परेशान होना पड़े ।

पंडित ऋषि राहुल जी ने अपने जीवन में कभी किसी को गलत तरह की सिद्धि साधना के लिए प्रेरित नहीं किया वो कहते है कि भक्ति से बड़ा कोई साधन नहीं है और उससे ही भगवान सिद्ध श्री हो जाते है ।

पंडित ऋषि राहुल जी प्रत्येक वर्ष अपने जन्मदिवस पर इसी तरह हवन कर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए भंडारा प्रसाद वितरण करते है और जन मानस का भी आशीर्वाद लेते है । हमारी समाचार पत्रिका की तरफ से भी पंडित ऋषि राहुल जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।

भारत-ब्रिटेन नई आर्थिक साझेदारी की दास्तान -प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की ऐतिहासिक सफ़ल भारत यात्रा 2025- व्यापार निवेश ,तकनीक और विश्वास की नई परिभाषा

"डेड इकोनॉमी" कहने वालों को करारा जवाब

उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में 125 से अधिक शीर्ष सीईओ, अग्रणी उद्यमी, विश्वविद्यालयों के कुलपति और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं, जो यात्रा के महत्व को रेखांकित करता है- एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र

वैश्विक स्तरपर ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर कीर स्टार्मर की 9-10 अक्टूबर 2025 की भारत यात्रा ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय जोड़ दिया है। यह यात्रा केवल दो दिनों की औपचारिक मुलाक़ात नहीं, बल्कि 21वीं सदी के वैश्विक व्यापारिक समीकरणों में भारत की निर्णायक भूमिका को स्वीकार करने की ठोस अभिव्यक्ति है।भारतीय पीएम के निमंत्रण पर भारत पहुंचे स्टार्मर का मुंबई एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत हुआ, जहां से इस यात्रा की शुरुआत ने एक ऐसा संदेश दिया ₹भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन का निर्णायक केंद्र हैं₹ ।पीएम ने ब्रिटेन पीएम के साथ मुलाकात की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारत और ब्रिटेन के रिश्ते तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और₹नई ऊर्जा से भरे हुए हैं₹एक तस्वीर में पीएम मोदी ब्रिटिश पीएम के साथ एक ही कार में नजर आए मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यहमानता हूं कि अमेरिका द्वारा भारत को डेड इकोनामी कहे जाने व 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने के बाद भारत-यूके रिश्तों का नया दौर शुरू हो गया है, व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी पर केंद्रित कूटनीति ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत डेट इकोनामी नहीं है, आज हम मीडिया में उपलब्ध जानकारी क़े सहयोग से आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे, भारत-ब्रिटेन नई आर्थिक साझेदारी की दास्तान, प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर की ऐतिहासिक सफ़ल भारत यात्रा 2025- व्यापार, निवेश, तकनीक और विश्वास की नई परिभाषा।

साथियों बात अगर हम ब्रिटेन पीएम की दो दिवसीय यात्रा की करें तो, यह ऐसे समय में हो रही है जब भारत और ब्रिटेन दोनों ही अपने-अपने आर्थिक और रणनीतिक भविष्य के पुनर्संरचना के दौर से गुजर रहे हैं। यात्रा का प्रमुख उद्देश्य व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग को सुदृढ़ करना है। ब्रिटिश पीएम के साथ आए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल में 125 से अधिक शीर्ष सीईओ, अग्रणी उद्यमी, विश्वविद्यालयों के कुलपति और सांस्कृतिक संस्थानों के प्रमुख शामिल हैं, यह अपने आप में इस यात्रा के महत्व को रेखांकित करता है ।यह केवल एक राजनयिक यात्रा नहीं, बल्कि ब्रिटिश व्यापारिक समुदाय का भारत के प्रति बदलता नजरिया दर्शाने वाली ऐतिहासिक घटना है। ब्रिटेन के कई औद्योगिक घराने अब भारत को मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी हब के रूप में देख रहे हैं, न कि केवल एक उपभोक्ता बाज़ार के रूप में।"डेड इकोनॉमी" कहने वालों को करारा जवाब हैं।

साथियों बात अगर हम अमेरिकी राष्ट्रपति द्वाराकुछ समय पहले भारत की अर्थव्यवस्था को "डेड इकोनामी" कहकर प्रश्न उठाए गए थे। वहीं भारत पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के बाद, वैश्विक व्यापार जगत में भारत की नीतियों को लेकर बहस तेज़ हो गई थी ।लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की यह यात्रा उस सोच को सीधा जवाब देती है। ब्रिटिश पीएम ने मुंबई में उतरते ही कहा कि "भारत 2028 तक दुनियाँ की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, और ब्रिटेन उस यात्रा का मजबूत भागीदार बनेगा।"यह बयान न केवल आर्थिक विश्वास का प्रतीक है, बल्कि यह उन तमाम संशयवादियों के लिए एक संदेश है जो भारत की विकास गाथा पर सवाल उठाते रहे हैं।

साथियों बातें कर हम ब्रिटेन के जेम्बो डेलिगेशन की करें तो यह विश्वास की कूटनीतिक मिसाल हैं, इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ हो जब ब्रिटेन का इतना बड़ा प्रतिनिधिमंडल किसी देश की यात्रा पर आया हो। यह "जेम्बो डेलिगेशन" भारत-ब्रिटेन संबंधों की गहराई और गंभीरता दोनों को दर्शाता है। 125 से अधिक शीर्ष सीईओ और शिक्षाविदों के साथ प्रधानमंत्री स्टार्मर का आना इस बात की पुष्टि करता है कि ब्रिटेन भारत को एक ऐसे रणनीतिक सहयोगी के रूप में देख रहा है, जो उसके पोस्ट-ब्रेक्सिट युग में वैश्विक प्रभाव को बनाए रख सकता है ।इस प्रतिनिधिमंडल में ऑक्सफोर्ड कैमब्रिज और लंदन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्स जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं, जो शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत के साथ साझेदारी की नई संभावनाओं पर विचार करेंगे। वहीं, तकनीकी कंपनियों के प्रमुख भारत में एआई, ग्रीन एनर्जी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में निवेश की नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं।

साथियों बात अगर हम मोदी- स्टार्मर शिखर वार्ता साझेदारी की नई परिभाषा की करें तो नई दिल्ली में मोदी और कीर स्टार्मर के बीच हुई शिखर बैठक में व्यापार, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और संस्कृति को केंद्र में रखकर गहन चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने यह स्पष्ट किया कि भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा ।बैठक में भारत ने ब्रिटेन को रक्षा उत्पादन, अंतरिक्ष तकनीक और ग्रीन एनर्जी मिशनों में साझेदारी के लिए आमंत्रित किया। वहीं ब्रिटेन ने भारत में अपने निवेश को तीन गुना बढ़ाने का आश्वासन दिया।"इनोवेशन पार्टनरशिप" के तहत दोनों देशों के बीच स्टार्टअप्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में संयुक्त रिसर्च पर सहमति बनी।

साथियों बात अगर हम भारत की ओर झुकता ब्रिटेन, वैश्विक शक्ति समीकरण में बदलाव कोसमझने की करें तो, ब्रिटेन पीएम की यात्रा ब्रिटिश विदेश नीति में एक मौलिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह वही ब्रिटेन है जिसने दशकों तक भारत को ₹डेवलपिंग नेशन₹ की दृष्टि से देखा था। लेकिन अब यह मान्यता बदल चुकी है। भारत को ब्रिटेन अब एक इक्वल पार्टनर, एक टेक्नोलॉजिकल पॉवरहाउस और एक वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्वीकार कर रहा है ।ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन को यूरोपीय संघ के बाहर नए आर्थिक साझेदारों की तलाश थी। ऐसे में भारत उसकी पहली प्राथमिकता बनकर उभरा है। ब्रिटिश मीडिया इसे"यूकेस पीवोट टू इंडिया "कह रहा है।

साथियों बात अगर हम भारत के लिए अवसर और जिम्मेदारी दोनों को समझने की करें तो, यह यात्रा भारत के लिए एक बड़ा अवसर लेकर आई है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी है। भारत को अब यह साबित करना होगा कि वह केवल निवेश आकर्षित करने वाला देश नहीं, बल्कि विनिर्माण, नवाचार और नीति स्थिरता के लिहाज से विश्वसनीय साझेदार भी है ।भारत के लिए यह समय है कि वह अपने मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, और स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों को ब्रिटिश सहयोग के साथ वैश्विक स्तर पर पहुंचाए। विशेष रूप से एआई, सेमीकंडक्टर, और क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में भारत की भूमिका निर्णायक बन सकती है।

साथियों बात अगर हम संस्कृति और शिक्षा, साझेदारी के मानवीय आयाम को समझने की करें तो, भारत-ब्रिटेन संबंध केवल अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं हैं। दोनों देशों के बीच संस्कृति, शिक्षा और सामाजिक मूल्य का भी गहरा जुड़ाव है। इस यात्रा में "कल्चरल एक्सचेंज मिशन" पर भी सहमति बनी, जिसके तहत ब्रिटेन और भारत के बीच कलाकारों, फिल्म निर्माताओं और विद्यार्थियों के आदान-प्रदान को बढ़ावा मिलेगा ।ब्रिटिश विश्वविद्यालयों में भारतीय छात्रों की संख्या पहले ही रिकॉर्ड स्तर पर है। अब ब्रिटेन ने भारत को "प्राथमिक शिक्षा भागीदार" के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। इसके तहत उच्च शिक्षा में द्विपक्षीय डिग्री कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स और कोर्स एक्सचेंज की शुरुआत होगी।

साथियों बात अगर हम यात्रा का ऐतिहासिक महत्व भविष्य के वैश्विक समीकरणों की झलक, यह यात्रा केवल भारत और ब्रिटेन के संबंधों की मजबूती का प्रतीक नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति समीकरणों में एशिया की केंद्रीय भूमिका को भी स्थापित करती है ।जब दुनियाँ अमेरिका- चीन प्रतिस्पर्धा में उलझी हुई है, तब ब्रिटेन का भारत की ओर झुकाव इस बात का संकेत है कि 21वीं सदी का आर्थिक केंद्र अबएशिया की धरती पर स्थित है ।भारत इस साझेदारी से न केवल व्यापारिक लाभ प्राप्त करेगा, बल्कि वह पश्चिमी देशों के साथ अपने कूटनीतिक संतुलन को भी और मजबूत करेगा।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि विश्वास, साझेदारी और भविष्य की एक नई कहानी, ब्रिटिश पीएम की भारत यात्रा 2025 इतिहास में "इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के पुनर्जागरण" के रूप में दर्ज होगी। इस यात्रा ने दिखा दिया कि भारत अब किसी के समर्थन का आकांक्षी नहीं, बल्कि साझेदारी का निर्णायक केंद्र बन चुका है ।ब्रिटेन के लिए यह यात्रा भारत के प्रति विश्वास की पुनर्स्थापना है, वहीं भारत के लिए यह अपनी वैश्विक स्थिति को और ऊंचा उठाने का अवसर। व्यापार, शिक्षा, तकनीक और संस्कृति, इन चारों स्तंभों पर खड़ी यह नई साझेदारी आने वाले दशक में विश्व की आर्थिक दिशा तय कर सकती है ।भारत और ब्रिटेन अब केवल साझेदार नहीं, बल्कि वैश्विक पुनरुत्थान के सह-निर्माता हैं, एक ऐसा अध्याय जो आने वाली पीढ़ियाँ "न्यू ऐज ऑफ़ इंडो - ब्रिटिश पार्टनरशिप" के नाम से याद करेंगी।

पंडारा में बनेगा बड़ा मछली बाजार: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे वर्चुअली शिलान्यास

मनोरंजन सासमल , बरिष्ठ पत्रकार

भुबनेश्वर: पंडारा में एक बड़ा मछली बाज़ार बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इसका शिलान्यास करेंगे। यह मछली बाज़ार 5 एकड़ ज़मीन पर बनेगा। थोक मछली बाज़ार नंबर 4 के लिए कई तरह की समस्याएँ थीं। यह योजना तीन साल से अटकी हुई थी। अब प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 50 करोड़ रुपये मिले हैं।लेकिन यह लगभग 60-80 करोड़ रुपये की परियोजना होगी। इससे खुदरा विक्रेताओं, थोक विक्रेताओं, कोल्ड स्टोरेज, मछली पालकों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं, सभी को लाभ होगा। भुवनेश्वर महानगर निगम की महापौर सुलोचना दास ने यह जानकारी दी।उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाँच एकड़ ज़मीन पर बनने वाली इस मछली मंडी का शिलान्यास करेंगे। कल प्रधानमंत्री वर्चुअली इसका शिलान्यास करेंगे। इस मछली मंडी से न सिर्फ़ उपभोक्ताओं को बल्कि मछली व्यापारियों को भी फ़ायदा होगा।

समाज में परिवर्तन की वाहक बने बालिकाएं

रमेश सर्राफ धमोरा

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक अंतर्राष्ट्रीय पालन दिवस है। 11 अक्टूबर 2012 को पहली बार बालिका दिवस मनाया गया था। तब से हर वर्ष 11 अक्टूबर को पूरी दुनियां में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस दुनिया भर में लड़कियों द्वारा उनके लिंग के आधार पर सामना की जाने वाली लैंगिक असमानता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस असमानता में शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार, चिकित्सा देखभाल और भेदभाव से सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा और जबरन बाल विवाह जैसे क्षेत्र शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 की थीम है मैं लड़की हूं, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूं। संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां। यह थीम संकट की परिस्थितियों में लड़कियों की दृढ़ता, नेतृत्व और सशक्त भूमिका पर केंद्रित है। यह थीम उन चुनौतियों पर प्रकाश डालती है जिनका सामना बालिकाएं करती हैं। जैसे संघर्ष, जलवायु परिवर्तन और असमानताएं। यह थीम बालिकाओं को केवल संकट के शिकार के रूप में नहीं बल्कि परिवर्तन के वाहक के रूप में पहचानने पर जोर देती है। यह थीम शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में निवेश का आह्वान करती है ताकि वे बेहतर और समावेशी दुनिया का निर्माण कर सकें।

आज हर क्षेत्र में बालिकाओं के आगे बढने के बावजूद भी वह अनेको कुरीतियों की शिकार हैं। ये कुरीतियों उनके आगे बढने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े-लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। देश में आज भी प्रतिवर्ष लाखों लड़कियों को जन्म लेने से पहले ही कोख में मार दिया जाता है। आज भी समाज के अनेक घरों में बेटा, बेटी में भेद किया जाता है। बेटियों को बेटों की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती है। समाज में आज भी बेटियो को बोझ समझा जाता है।

भारत में हर साल तीन से सात लाख कन्या भ्रूण नष्ट कर दिये जाते हैं। इसलिए यहां महिलाओं से पुरुषो की संख्या 5 करोड़ ज्यादा है। समाज में निरंतर परिवर्तन और कार्य बल में महिलाओं की बढ़ती भूमिका के बावजूद रूढिवादी विचारधारा के लोग मानते हैं कि बेटा बुढ़ापे का सहारा होगा और बेटी हुई तो वह अपने घर चली जायेगी। बेटा अगर मुखाग्नि नहीं देगा तो कर्मकांड पूरा नहीं होगा।

पिछले कुछ वर्षों में देश में जन्म के समय लिंगानुपात में बढ़ोतरी होना शुभ संकेत हैं। संसद में एक सवाल का जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री ने बताया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना ने बालिकाओं के अधिकारों को स्वीकार करने के लिए जनता की मानसिकता को बदलने की दिशा में सामूहिक चेतना जगाई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय लिंग अनुपात (एसआरबी) में 12 अंकों के सुधार के रूप में परिलक्षित होता है। जो कि 2014 में 918 था। जबकि 2023-24 में 12 अंक बढ़कर 930 हो गया।

हमारे देश में यह एक बड़ी विडंबना है कि हम बालिका का पूजन तो करते हैं। लेकिन जब हमारे खुद के घर बालिका जन्म लेती है तो हम दुखी हो जाते हैं। देश में सभी जगह ऐसा देखा जा सकता है। देश के कई प्रदेशों में तो बालिकाओं के जन्म को अभिशाप तक माना जाता है। लेकिन बालिकाओं को अभिशाप मानने वाले लोग यह क्यों भूल जाते हैं कि वह उस देश के नागरिक हैं जहां रानी लक्ष्मीबाई जैसी विरांगनाओं ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे।

हमारे यहां आज भी बेटी पैदा होते ही उसकी परवरिश से ज्यादा उसकी शादी की चिन्ता होने लगती है। आज महंगी होती शादियों के कारण बेटी का बाप हर समय इस बात को लेकर चिंतित नजर आता है कि उसकी बेटी की शादी की व्यवस्था कैसे होगी। समाज में व्याप्त इसी सोच के चलते कन्या भ्रूण हत्या पर रोक नहीं लग पायी है। कोख में कन्याओ को मार देने के कारण समाज में आज लड़कियों की काफी कमी होने से लिंगानुपात गड़बड़ा गया है।

अगर समाज में बेटियों को उचित शिक्षा और सम्मान मिले तो बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नही रहेगी। इसलिए यदि यह कहा जाय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना नही हम सबकी एक जिम्मेदारी है तो इसमें कुछ गलत नही है। यदि हम सभी एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहते है तो हम सबका यही फर्ज बनता है हम बेटियों को भी भयमुक्त वातावरण में पढ़ाये। उन्हें इतना सशक्त बनाये की खुद गर्व से कह सके की देखो वह हमारी बेटी है जो इतना बड़ा काम कर रही है।

आज लड़किया लड़को से किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। कठिन से कठिन कार्य लड़किया सफलतापूर्वक कर रही हैं। देश में हर क्षेत्र में महिला शक्ति को पूरी हिम्मत से काम करते देखा जा सकता है। लड़कियों ने अपने काम और समर्पण के दम पर कई क्षेत्रों और क्षेत्रों में खुद को साबित किया है। वे अधिक प्रतिभाशाली, आज्ञाकारी, मेहनती और परिवार और अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। लड़कियां अपने परिवार और माता-पिता के प्रति अधिक देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली होती हैं और वे हर काम में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देती हैं। देश की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का अहम योगदान है। वे श्रम शक्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और व्यवसायों की वृद्धि और विकास में योगदान देती हैं।

एक तरफ जहां बेटी को जन्मते ही मरने के लिये लावारिश छोड़ दिया जाता है। वहीं झुंझुनू जिले की मोहना सिंह जैसी बालिकायें भी है जो आज देश में फाईटर प्लेन उड़ा कर पूरे देश में जिले का मान बढ़ा रही हैं। समाज में सभी को मिलकर लडका-लडकी में भेद नहीं करने व समाज के लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करने की प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देश में बालिकाओं के साथ हर दिन बलात्कार, प्रताडना की घटनायें अखबारो की सुर्खिया बनती हैं। बालिकायें कही भी अपने को सुरक्षित नहीं समझती हैं। चाहे घर हो या स्कूल अथवा कार्य स्थल। हर जगह वहशी भेडिये उन पर नजरे गड़ायें रहते हैं। उन्हे जब भी मौका मिलता है नोंच डालते हैं। ऐसे माहौल में देश की बालिकायें कैसे आगे बढ़ पायेगीं।

समाज के पढ़े लिखे लोगों को आगे आकर कन्या भ्रूण हत्या जैसे घिनोने कार्य को रोकने का माहौल बनाना होगा। ऐसा करने वाले लोगों को समझा कर उनकी सोच में बदलाव लाना होगा। लोगों को इस बात का संकल्प लेना होगा कि ना तो गर्भ में कन्या की हत्या करेगें ना ही किसी को करने देगें। तभी देश में कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लग पाना संभव हो पायेगा। सरकार व समाज को मिलकर ऐसे वातावरण का निर्माण करने का प्रयास करना चाहिये जिसमें बालिकायें खुद को महफूज समझ सकें। समाज और राष्ट्र के विकास के लिए बालिकाओं के महत्व को स्वीकार करना और बढ़ावा देना आवश्यक है।

हम सभी जानते हैं कि एक लड़की समाज के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। वह एक मा, एक बेटी, एक पत्नी इस तरह कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। उसे घर की शांति बनाए रखने वाली स्तंभ माना जाता है और फिर भी उसका अपमान किया जाता है। स्त्रियां ही संतति की परम्परा में मुख्य भूमिका निभाती है फिर भी प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक कहे जाने वाले समाज तक स्त्रियां उपेक्षित ही रही है।

हमारे समाज का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज अपनी बच्चियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें कितना महत्व देते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाना न केवल एक नैतिक दायित्व है बल्कि सामाजिक विकास के लिए एक जरूरी आवश्यकता भी है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि लड़कियों को आगे बढ़ने, सीखने के समान अवसर मिले। तभी हम एक संतुलित, न्यायसंगत और समृद्ध समाज बना सकेगें।

(लेखक राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

सपा महासचिव ओड़िशा प्रताप बारीक़ ने छोड़े समाजवादी पार्टी छोड़ी। राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने की जानकारी

मनोरंजन सासमल ,बरिष्ठ पत्रकार

भुवनेश्वर: समाजवादी पार्टी की ओडिशा राज्य समिति के महासचिव प्रताप किशोर बारिक ने पार्टी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इस संबंध में उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, ओडिशा प्रभारी सुनील सिंह यादव और प्रदेश अध्यक्ष यादव को अपना त्यागपत्र सौंप दिया है और बताया है कि वे जल्द ही राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होंगे। 06/10/2025 को होटल मेफेयर में आयोजित चौधरी चरण सिंह की स्मृति सभा में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी और ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र हाथी से मुलाकात कर इस विषय पर चर्चा की और कहा कि वे आगामी विलय समारोह में ओडिशा के पिछड़े वर्ग के कई नेताओं के साथ पार्टी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी एक हिंदू विरोधी पार्टी है जो देश के लोकतंत्र और आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। साथ ही, यह एक विशेष जाति के लोगों को बढ़ावा देती है और पार्टी के ओडिशा प्रदेश अध्यक्ष की ओडिशा के लिए कोई योजना नहीं है। श्री बारिक ने समाजवादी पार्टी की आलोचना करते हुए कहा है कि इसका कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए उड़िया लोग इस पार्टी को स्वीकार नहीं करेंगे।

गढ़वा में सोलर पावर घोटाले पर हाईकोर्ट गंभीर, आरोपियों को भेजा नोटिस

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड के गढ़वा जिले में हुए सोलर पावर घोटाले से जुड़े मामले की एक जन हित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में संलिप्त अधिकारियों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला साल 2020 से 2021 के बीच का है, जब गढ़वा जिला के बंशीधर नगर नगर पंचायत में सोलर पैनल, मास्क लाइट और फॉगिंग मशीन की बाजार दर से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदारी की गई थी। आरोप है कि गढ़वा जिला के नगर पंचायत के बंशीधर नगर में सोलर पैनल, मास्क लाइट और फॉगिंग मशीन की खरीदारी मार्केट से ऊंचे दामों पर की गई थी। 15-20 हजार की कीमत वाली सोलर पैनल की खरीदारी 84 हजार में की गई थी, जबकि 20 हजार की कीमत वाली फॉगिंग मशीन की खरीदारी 1 लाख 10 हजार में की गई थी। जो निम्न गुणवत्ता वाले उपकरण थे। सभी उपकरणों की खरीदारी नोएडा की इग्नाइट कंपनी से की गई थी, जबकि खरीदारी बजाज महाकाल कंपनी से करना था। इससे राज्य सरकार के राजस्व को बड़ा नुकसान हुआ। याचिका में नगर पंचायत से जुड़े मुख्य अभियंता कार्यपालक अभियंता सहायक अभियंता और कनीय अभियंता को प्रतिवादी बनाया गया है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि इन सभी अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर निजी लाभ के उद्देश्य से मनपसंद एजेंसी से उपकरणों की खरीदारी करवाई, जो नियमों के विरुद्ध है। झारखंड के प्रायः हर जिले में सोलर पैनल, लाईट खरीदने, आदि पर बड़ी अनियमितता देखने को मिला है। जहां बड़ी घोटाले की तरफ यह इंगित करता है।

बालू चोरों के विरूद्ध राहुल नदी मे झपटे , बाकी जिलों में कट रही चांदी ?

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची, झारखंड में इन दिनों सरकारी राजस्व चोरों के निवाला बनता देख कुछ अधिकारी अपने हिम्मत का मिशाल दे रहे हैं। जहां अनेक हिम्मत लालों को यह सब दिखाई नहीं पड़ना बेहद खेद की बात है ! इस क्रम में सरैयाहाट के अंचल अधिकारी राहुल कुमार शानु अपने कार्यों को लेकर किर्तिमान स्थापित करने चले हैं। शानु को जब सरैयाहाट के अंचल अधिकारी के तौर पर मंगलवार को दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के पथरिया नदी से कुछ ट्रेक्टरों से अवैध रूप से बालू उठाव किये जाने की सूचना मिली तब उन्होंने शेर की भांति पानी में झपट कर बालू पकड़ा। इतना ही नहीं सीओ राहुल कुमार शानू जब पथरिया नदी के पास पहुंचे तो उन्होंने सात-आठ की संख्या में ट्रैक्टर को अवैध रूप से बालू का उठाव करते देखा। शानु के मौके पर पहुंचने पर सभी चालक ट्रैक्टर लेकर भागने लगे। इस पर अंचलाधिकारी शानु अपनी जान की परवाह किये बगैर वे बालू लदे ट्रैक्टर को पकड़ने के लिए नदी में कूद पड़े। इस दौरान अंचलाधिकारी शानु ने अकेले बहादुरी का परिचय देते हुए बालू लदे दो ट्रैक्टरों को पकड़ लिया और हंसडीहा थाना का सौंप दिया। इसकी सूचना जिला खनन पदाधिकारी को दी। इस सूचना पर खान निरीक्षक मंजीत कुमार दूबे हंसडीहा थाना पहुंचे और दोनों ट्रैक्टरों के खिलाफ लिखित आवेदन देकर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कराया है। खान निरीक्षक मंजीत दूबे के मुताबिक दोनों जब्त ट्रैक्टर में नंबर अंकित नहीं। इस कारण जब्त ट्रैक्टर के चेसिस नंबर और इंजन नंबर से निबंधन का पता लगाया जाएगा। मालूम हो कि एनजीटी और झारखंड मिनरल माइनिंग की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के संबंध में हंसडीहा थाना को आवेदन दिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार इन दिनों इस क्षेत्र में कई जगहों पर अवैध रूप बड़े पैमाने पर बालू डंप किया जा रहा है। हंसडीहा थाना क्षेत्र के सरसा गांव, दीनानाथ मंदिर के समीप, हंसडीहा जवाहर नवोदय विद्यालय कैंपस, हंसडीहा रेलवे स्टेशन, कुशियारी सहित कई जगहों पर बालू डंप कर रखा गया है। इतना ही नहीं हंसडीहा थाना क्षेत्र के कई जगहों से बालू डंप कर रात के अंधेरे में ट्रकों के माध्यम से गोड्डा भेजा जा रहा है। वैसे सरायकेला खरसावां जिले में भी अवैध बालू उठाव परिवहन जारी है। जहां रात के अंधेरे में भोर तक जिले कुछ घाटों में यह जारी है। माइनिंग विभाग के पास पर्याप्त संसाधन मसलन मैन पावर का नहीं होना। दुशरी तरफ पुलिस - चोरों के क्रियाकलाप इमानदार अफसरों के लिए जिले में धब्बा डाल रहा है। जिसपर लोगों की तीव्र प्रतिक्रिया आने जा रही है।

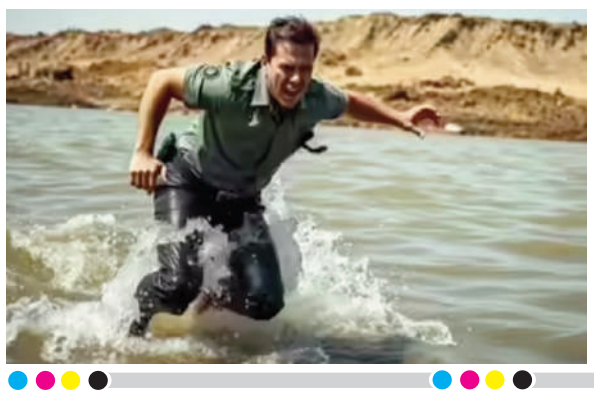

सीरवी समाज प्रीमियर लीग (SSPL)-8 क्रिकेट प्रतियोगिता व महिला वर्ग के खेल 26 से

परिवहन विशेष न्यूज

तेलंगाना: हैदराबाद सीरवी फ्रेन्डस क्लब हैदराबाद द्वारा आयोजित सीरवी समाज प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के 8 वें संस्करण तथा महिला वर्ग के खेलों का शुभारम्भ रविवार 26 अक्टूबर को सीरवी क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद एवं लिजेंड ग्राउंड किसरा में आयोजित किया जाएगा। फ्रेन्डस क्लब के सुरेश सैंणचा ने बताया कि हर वर्ष की भांति सीरवी समाज प्रीमियर लीग-8 का तथा इस प्रतियोगिता के साथ महिला वर्ग के खेलो का भव्य शुभारंभ 26 अक्टूबर को प्रातः 7.15 को प्रतियोगिता के मुख्य प्रायोजक वाहिनी पाइप्स हेमराज सैणचा टुमकुर ट्राफी प्रायोजक बुधाराम गौतम काग बीरमगुडा, मैन ऑफ द मैच प्रायोजक तुलसाराम सिन्दडॉ चिल्कानगर सीरवी समाज मल्लापुर बडेर अध्यक्ष, टॉस का बॉस प्रायोजक रायल गोल्ड पॉट मार्केट राजूराम, ओमप्रकाश व हापुराम बर्फा,अंपायर प्रायोजक आर एस सिल्वर पॉट मार्केट घेवरराम संजय गोविंद राम

महेन्द्र व देवेंद्र , विशेष योगदान जी पी एंटरप्राइसेज आर पी रोड़ अशोक पाण्डे तथा मुख्य अतिथियों के करकमलों द्वारा किया जायेगा। पिछले साल सफल आयोजन की वजह से इस बार भी खेलों को लेकर महिला वर्ग खिलाड़ीयों में भारी उत्साह नजर आ रहा है क्रिकेट में 24 टीमें हिस्सा लेंगी KCG धम्माईगुड़ा, ऑलवीन XI, कर्मनघाट वॉरियर ,आई जी क्लब , सिकंदराबाद क्लब , लिंगम्मपल्ली आर्मी , संगारेड्डी सुपर किंग, शमशाबाद बुल्स ,कापरा ग्रेट फाईटर, सीरवी किंग्स XI,अलवाल, साधनगर स्ट्राइकर ,रामनगर रायल ,अस्टिक मेडचल ,एल बी नगर टाइगर्स , सीरवी रेंजर्स ,शंकरपल्ली ब्लास्टर , नाचाराम स्ट्राइकर , जुबली हिल्स क्लब, एल बी नगर, टी एम जी टाइटंस, बालनगर धुम XI, माताजी XI बीरमगुडा, सैनिकपुरी ,प्रत्येक टीम 5 लीग मैच खेलेगी। तथा 4 क्वाटर फाईनल, 2 सेमीफाइनल और फाईनल मुकाबले खेले जाएंगे। क्रिकेट प्रतियोगिता के साथ साथ महिला वर्ग के खेलों में एथेलेटिक्स तथा पारंपरिक खेल शामिल होंगे। महिला वर्ग के सभी खेल सीरवी क्रिकेट ग्राउंड अलियाबाद शामिरपेट में आयोजित होंगे। यह प्रतियोगिता सीरवी फ्रेंड्स क्लब हैदराबाद तेलंगाना द्वारा आयोजित की जा रही है। भोजन की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर की जाएगी। सभी मैचों का लाईव प्रसारण युट्युब चैनल पर किया जाएगा। प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सीरवी फ्रेन्डस क्लब के सभी सदस्यों का विशेष सहयोग रहेगा। सभी सीरवी बन्धुओं से निवेदन है इस प्रतियोगिता मे अपना तन-मन-धन से सहयोग करके प्रतियोगिता को सफल बनावे।

झारखंड निर्माण में कुल 854 आन्दोलन कारी चिन्हित जारी हुई 37 वीं सूची

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

रांची। झारखंड गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने झारखंड आंदोलनकारियों की 37वीं सूची जारी कर दी है. इस सूची में 854 आंदोलनकारियों को चिह्नित कर शामिल किया गया है. ये आंदोलनकारी राज्य के 10 जिलों बोकारो, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, खूंटी, रांची और सरायकेला के रहने वाले हैं. जारी सूची के अनुसार, जामताड़ा जिले में सबसे अधिक 306 आंदोलनकारी चिह्नित हुए हैं. जबकि देवघर में 271 आंदोलनकारियों की पहचान की गई है. वहीं, बोकारो जिले में सबसे कम केवल एक आंदोलनकारी को चिह्नित किया गया है. गृह विभाग द्वारा जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि चिह्नित किए गए आंदोलनकारियों को संकल्प के प्रावधानों के अनुरूप सुविधाएं संबंधित जिले के डीसी द्वारा प्रदान की जाएंगी. डीसी को यह भी सख्त निर्देश दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि किसी भी स्थिति में किसी एक आंदोलनकारी या उनके आश्रितों को दोबारा देय सुविधाएं प्रदान न हों।

कृत्रिम बुद्धिमता (आर्टिफिशल इंटेलिजेंस -ए आई) कितनी सटीक - भारत में उसका भविष्य!

चंद्र मोहन

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (ए आई) एक तकनीक है जो मशीनों को मानव-जैसी बुद्धिमत्ता, सोचने, सीखने, और समस्या-समाधान करने में सक्षम बनाती है.

ए.आई. एल्गोरिदम और डेटा का उपयोग करके मानव के तर्क, निर्णय लेने, और स्वायत्त कार्य करने की क्षमताओं का अनुकरण करता है जैसे छवियों को पहचानना, भाषा को समझना और रचनात्मक सामग्री तैयार करना.

इसमें मुख्य विशेषता यह है कि यह मानव बुद्धि का अनुकरण करती है. ए.आई. का मुख्य लक्ष्य कंप्यूटर और मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और कार्य करने में सक्षम बनाना है.

यह डेटा पर आधारित है.ए.आई. सिस्टम बड़ी मात्रा में डेटा से सीखकर पैटर्न, प्रवृत्तियों और भविष्य की घटनाओं की भविष्यवाणी करना सीखता है.

यह स्वायत्त कार्य करती है. ए.आई. मशीनें स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकती हैं, जो मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता को कम करता है, जैसे स्व-चालित कारें इसका एक उदाहरण हैं -

विभिन्न क्षमताएँ:

ए.आई. विभिन्न कार्य कर सकता है जिनमें शामिल हैं:

छवियों और भाषा को पहचानना

डेटा का विश्लेषण करना

समस्याओं का समाधान करना

रचनात्मक सामग्री (जैसे टेक्स्ट, चित्र) बनाना

शब्दावली:

मशीन लर्निंग (एम एल): ए.आई. प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली एक तकनीक.

डीप लर्निंग: मशीन लर्निंग का एक सबसेट जो मानव-प्रेरित तरीके से डेटा और पैटर्न को

समझता है.

उदाहरण के तौर पर

चैटबॉट्स: ग्राहक सेवा के लिए मानव भाषा को समझने और प्रतिक्रिया देने में सक्षम.

जेनरेटिव एआई (जेन ए आई): मौलिक टेक्स्ट, चित्र, वीडियो और अन्य सामग्री बनाने में सक्षम, आई बी एम द्वारा विकसित.

स्व-चालित कारें: स्वतंत्र रूप से नेविगेट करने और चलाने के लिए ए.आई. का उपयोग करती हैं.

इंटरनेशनल डेटा कॉरपोरेशन के अनुसार भारत का कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) बाजार 20.2 प्रतिशत की सीएजीआर से बढ़कर 2020 में 3.1 बिलियन डॉलर से 2025 तक 7.8 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है. (आईडीसी).

यदि भारत को कृत्रिम बुद्धिमत्ता का महाशक्ति बनना है तो अपने कौशल में सुधार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है.

एआई की क्षमता लगभग असीमित है और इसका उपयोग दुनिया भर में शैक्षिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए किया जाएगा जिससे शिक्षण अधिक कुशल, समावेशी और प्रत्येक छात्र की आवश्यकताओं के अनुकूल बन सकेगा.

अगले 10 साल वर्ष 2025 से वर्ष 2035 तक एआई एक बेहतरीन सहायक के रूप में कार्य करेगा.

अगले दशक में एआई हमारे निजी और पेशेवर जीवन में गहराई से समा जाएगा. हम सिर्फ़ एआई का इस्तेमाल नहीं करेंगे— हम उस पर निर्भर भी रहेंगे.

एआई भविष्यवाणी

इस वर्ष 2025 के संबंध में, प्रमुख रुझानों में नवाचार और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एआई का परिवर्तनकारी शक्ति बनना, ए आई एजेंटों, मल्टीमॉडल मॉडल और आर ए जी (रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जेनरेशन) जैसी प्रगति का तेजी से अपनाना और जेनएआई पर फोकस से हटकर उच्च-मूल्य वाले उपयोग के मामलों की ओर बढ़ना शामिल है. नियामक वातावरण लचीला रहने की उम्मीद है लेकिन कंपनियों को बदलते राज्य नियमों पर ध्यान देना होगा. इसके अलावा, कंपनियों द्वारा आंतरिक रूप से ए आई प्रतिभा को विकसित करने और ए आई सुरक्षा से संबंधित चिंताओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे.

एआई के लिए महत्वपूर्ण रुझान और विकास

एआई की परिवर्तनकारी भूमिका:

2025 में एआई एक उपकरण से कहीं बढ़कर होगा, जो उद्योगों में नवाचार, दक्षता और ग्राहक जुड़ाव को बढ़ावा देने वाली एक परिवर्तनकारी शक्ति होगी.

नई ए आई प्रौद्योगिकियां:

एआई एजेंट, मल्टीमॉडल मॉडल और रिट्रीवल-ऑगमेंटेड जेनरेशन (आर ए जी) जैसी प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले व्यवसाय प्रतिस्पर्धी बने रहेंगे.

उच्च-मूल्य वाले उपयोग-मामलों पर ध्यान केंद्रित करना: 2025 जेनएआई पर वर्तमान फोकस से आगे बढ़कर उच्च-मूल्य वाले उपयोग-मामलों की ओर एक बदलाव देखेगा, जो उत्पादकता में सुधार और लागत को कम करने में मदद करेगा.

एजेंटिक एआई का उदय:

यह साल एजेंटिक एआई के उदय का प्रतीक होगा जो वास्तविक दुनिया की बाधाओं को दूर करने के लिए एआई को अधिक सक्षम बनाएगा.

एआई के मुख्य नुकसानों में नौकरी छूटना, डेटा में पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव बढ़ना, गोपनीयता का उल्लंघन, उच्च लागत, मानवीय रचनात्मकता और सहानुभूति का अभाव और जटिल निर्णयों में पारदर्शिता की कमी शामिल हैं. इसके अलावा, एआई पर अत्यधिक निर्भरता से मानवीय कौशल कमजोर हो सकते हैं और गलत निर्णय लिए जा सकते हैं.

नौकरी और रोजगार पर असर -

नौकरी का विस्थापन: ऑटोमेशन के कारण कई मैनुअल और दोहराए जाने वाले कार्य एआई द्वारा किए जा रहे हैं जिससे लोगों की नौकरियां जा सकती हैं.

कार्यबल में परिवर्तन: एआई के कारण कार्य-भूमिकाएँ बदल रही हैं, जिससे कार्यबल और बाज़ारों में बड़े बदलाव आ रहे हैं.

सामाजिक और नैतिक मुद्दे -

पूर्वाग्रह और भेदभाव: एआई को प्रशिक्षित करने के लिए इस्तेमाल किए गए डेटा में पूर्वाग्रह होने पर, एआई सिस्टम भी पक्षपाती हो सकते हैं, जिससे समाज में भेदभाव बढ़ सकता है.

निजता का उल्लंघन -

एआई सिस्टम डेटा का विश्लेषण करते हैं, जिससे गोपनीयता भंग होने और व्यक्तिगत जानकारी के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है.

निर्णयों में पारदर्शिता की कमी -

कई एआई सिस्टम इतने जटिल होते हैं कि उनके निर्णय लेने की प्रक्रिया को समझना इंसानों के लिए मुश्किल होता है.

2050 में एआई के लिए भविष्यवाणियां स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन और पर्यावरण प्रबंधन जैसे उद्योगों में इसके एकीकरण की कल्पना करती हैं, जबकि मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण और एआई हार्डवेयर में नवाचार इन परिवर्तनों को आगे बढ़ाएंगे.

पटाखों से आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक तथा मानसिक रोग ही पैदा होता है

विजय गर्ग

कुछ समय पहले देश की सर्वोच्च अदाल ने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पर सुनवाई की थी। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने दिल्ली–एनसीआर में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही क्यों पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए? देश में जहां–जहां प्रदूषण की विकट समस्या है, उन शहरों और कस्बे में भी पटाखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? 2 जितना अधिकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का है, उतना ही जहां समस्या का भी है:

खुशी का इजहार करने के लिए और भी कई तरीके हैं। ₹ इनमें संगीत-नृत्य का आयोजन, नगाड़े एवं ढोलक बजाना, लोकगीत गायन या खुल कर नृत्य करना हो सकता है। भूले-बिसरे पारंपरिक तरीके भी अपनाए सकते हैं। सहभोज को भी इसमें शामिल किया जा सकता है। लेकिन सवाल है कि कुछ लोग खुशी की अभिव्यक्ति को केवल पटाखों से जोड़ कर क्यों देखते हैं। जब पटाखों पर सवाल उठता है, तब कई लोग तर्क देते हैं कि इससे हैं कि इससे अधिक वाहनों और फैक्टरियों से प्रदूषण फैलता है, तो इस पर भी गौर किया जाना चाहिए। इस तर्क में दम है, लेकिन वाहनों का निजी और सार्वजनिक उपयोग कहीं महत्त्वपूर्ण है। इसके समांतर पटाखों के पक्ष में के पक्ष में तर्कों को कसौटी पर रखना चाहिए। पटाखे हर तरह से पर्यावरण के लिए नुकसानदायक ही नहीं, खतरनाक भी हैं। अरबों रुपए के आर्थिक नुकसान के साथ हर वर्ष पटाखों से काफी लोगों की मौत हो जाती है। पटाखा फैक्टरियों में इन्हें बनाते समय और पटाखों का इस्तेमाल करने के दौरान कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं।

कुछ समय पहले देश की सर्वोच्च अदाल ने पर्यावरण प्रदूषण से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई पर सुनवाई की थी। इस दौरान प्रधान न्यायाधीश ने दिल्ली-एनसीआर में ही पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर सवाल किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही क्यों पटाखों पर प्रतिबंध होना चाहिए? देश में जहां-जहां प्रदूषण की विकट समस्या है, उन शहरों और कस्बे में भी पटाखों पर प्रतिबंध क्यों नहीं होना चाहिए? 2 जितना अधिकार दिल्ली के लोगों को साफ हवा में सांस लेने का है, उतना ही जहां समस्या का भी है:

उन सभी शहरों के लोगों बेहद चिंताजनक बनी रहती है। अदालत के मुताबिक, प्रदूषण के संबंध जो भी नीति हो, वह अखिल भारतीय स्तर पर एक जैसी होनी चाहिए। पहले पांच मई 2025 को सर्वोच्च अदालत ने इसके ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा और और राजस्थान सरकारों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पटाखों पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया था और चेतावनी दी थी कि इसका पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले भी कई बार सर्वोच्च न्यायालय इस बाबत आदेश जारी कर चुका है। इन आदेशों का कितना पालन हुआ, यह सभी जानते हैं। हालांकि हरित पटाखों को लेकर कुछ हलकों में सकारात्मक धारणा रही।

पटाखों के इस्तेमाल से अनिद्रा, तनाव, कान के पर्दे फटने और बीमार लोगों के लिए बेहद गंभीर हालात पैदा करने जैसी तमाम परेशानियां सामने आती हैं। इनसे हुई गंदगी, उसके रसायन और बिखरे हुए कागज किसी मुसीबत से कम नहीं होते। मगर विडंबना यह है कि आम आदमी सभी तरह के आदेशों, , सरकारी प्रतिबंधों और परामर्श को हमेशा अनदेखा करता आया है। पटाखों पर तमाम पाबंदियों के बावजूद बड़े पैमाने पर पटाखे और सुतली बमों का इस्तेमाल होता है। दीपावली और उसके आसपास एक-दो दिन तक रास्ते में चलना भी मुश्किल हो जाता है। कई दिनों तक विषैले धुएं का गुबार वातावरण में छाया रहता है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। पटाखों की ऐसी लड़ी जलाई जाती है कि सड़क पर यह लोगों के लिए जानलेवा बन जाती है। सवाल यह है कि ये सब किसकी खुशी के लिए होता है ? इस त्योहार पर होड़ देखी जा सकती है कि देखते हैं कौन कितना आगे है पटाखे फोड़ने में। खबरों के मुताबिक, दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कई परिवार एक हजार से लेकर एक लाख रुपए तक के पटाखे कुछ ही घंटों में जला देते हैं। सवाल है कि यह त्योहार मनाने का तरीका है या प्रदूषण फैलाने की प्रतियोगिता ?

इस पर विचार किया जाना चाहिए कि पटाखों का इस्तेमाल कई जटिल समस्याओं को भी जन्म देता है। पटाखों को जलाने पर इसकी तेज आवाज और इससे निकलने वाले विषैले कण-धुआं बेहद घातक हैं। ये पटाखे चलाने वालों में ही समस्या नहीं पैदा करते, बल्कि वहां मौजूद दूसरे लोग भी उससे प्रभावित होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक पटाखे जलाने से सल्फर डाई आक्साइड, कार्बन मोनोआक्साइड, नाइट्रोजन आक्साइड के अलावा लेड सहित अन्य रसायन वातावरण में फैल कर कई तरह की गंभीर समस्याएं पैदा करते हैं। ये सभी बेहद जहरीले होते हैं। दिल, दिमाग, यकृत, गुर्दे, खून और हड्डियों तक गंभीर रूप से असर करते हैं। इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण के साथ मिट्टी और जल प्रदूषण भी होता है।

अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़े में रोग जैसी बीमारियों की एक वजह पटाखे भी बन गए हैं। हृदयाघात का खतरा और दिल की धड़कन अनियमित होना सामान्य बात है। श्वसन से ताल्लुक रखने वाली समस्याओं और त्वचा संबंधी बीमारियों का जोखिम भी पटाखों से बढ़ जाता है। एक शोध के मुताबिक पटाखे सार्वजनिक जल आपूर्ति को भी जहरीला बना सकते हैं। उस पानी का इस्तेमाल करने वाली आबादी कई तरह की शारीरिक और मानसिक बीमारियों का शिकार हो सकती

अनुसंधान । इसका वनस्पतियों पर भी बुरे असर का पता लगा है। बताया गया है कि वनस्पतियों के विकास और पैदावार दोनों पर असर पड़ता है। धूल तक जहरीली हो जाती है। पटाखे जमीन के नीचे के पानी को भी प्रदूषित कर सकते हैं। यही नहीं थाइराइड की बीमारी भी पैदा सकते हैं। श्वास नली में विषैले तत्त्व जाने से इसके क्षतिग्रस्त होने का खतरा होता है।

पटाखों त्रों से वायु, ध्वनि, भूमि और जल प्रदूषण होता है। यानी ये पूरे पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। पटाखों ने आर्थिक नुकसान के साथ शारीरिक तथा मानसिक रोग ही पैदा नहीं किए, बल्कि कई तरह के सवाल भी खड़े किए हैं। इसके अलावा सांस्कृतिक परंपराओं और विधानों पर भी सवालिया निशान लगते हैं। जिन पटाखों को खुशी मनाने के नाम पर जलाया जाता है, वे हिंसक और शोर-गुल पसंद संस्कृतियों का कभी हिस्सा हुआ करते थे। भारत में मध्यकाल में इनका प्रचार-प्रसार ज्यादा ज्यादा हुआ और देखते-ही-देखते ये भारतीय समाज के हर में खुशी का इजहार करने

। जरिया बन गए। हमारे यहां किसी भी उत्सव और पर्व-त्योहार का हिस्सा ये नहीं होते थे, क्योंकि इनका यहां निर्माण ही नहीं होता था। शांति, प्रेम,

सद्भाव और सहिष्णुता वाली भारतीय संस्कृति में खुशी प्रकट करने के लिए

नृत्य, संगीत समारोह, आका , संगीत समारोह, आम की पत्तियों से बंदनवार सजाने, चित्रकारी करने

और अनेक प्रतीकों का प्रयोग किए जाने की परंपरा रही है।

पटाखों पर सरकारी प्रतिबंध और सर्वोच्च अदालत के आदेश का सभी राज्य की पुलिस कितना पालन करवा पाएगी, यह तो दीपावली और दूसरे त्योहारों पर पता चलेगा, लेकिन लोगों को जागरूक करने का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाना चाहिए। जिससे आने वाले समय में पटाखे को लेकर किसी तरह की प्रदूषण संबंधी समस्याएं न पैदा हों। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले वक्त पटाखों पर प्रतिबंध महज दिल्ली- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ही नहीं, बल्कि हर उस शहर में भी लगाया जाएगा, जहां प्रदूषण की समस्या हमेशा बनी रहती है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

मानव चेतना के संकट को अभिव्यक्त करते हैं लास्लो

-हरीश शिवनानी

कई दिनों की उत्कंठा के बाद आख़िरकार साहित्य का नोबेल पुरस्कार घोषित हो गया और इस बार भी किसी भारतीय को नहीं मिला। चर्चा थी कि अमिताव घोष या विनोद कुमार शुक्ल रवींद्रनाथ टैगोर की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे पर ऐसा हो न सका। नोबेल पुरस्कार देने वाली स्वीडिश अकादमी ने विश्व के इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए हंगरी के लेखक लास्लो क्रास्नाहोरकाई को चुना। ज्यूरी के मुताबिक लास्लो के लेखन में 'मानवता की नाजुकता और इतिहास की जटिलता को उजागर करने वाली गहन, अपोकैलिप्टिक(सर्वविनाशकारी) दृष्टि' है। यह लास्लो की अद्वितीय साहित्यिक उपलब्धियों और वैश्विक साहित्य में योगदान का प्रमाण है। क्रास्नाहोरकाई का साहित्य, जो अपनी जटिल संरचना, लंबे वाक्यों और दार्शनिक गहराई के लिए जाना जाता है, समकालीन विश्व की अस्थिरता और मानव चेतना के संकट को गहरे स्तर पर अभिव्यक्त करता है।

क्रास्नाहोरकाई का साहित्य साम्यवाद, फासीवाद और पूंजीवाद जैसे ऐतिहासिक और राजनीतिक ढांचों के प्रभावों को गहराई से खंगालता है।उनके उपन्यास, जैसे 'सतानटैंगो' और 'द मेलानकली ऑफ रेसिस्टेंस', साम्यवादी हंगरी के पतन और उसके बाद की अराजकता को चित्रित करते हैं। हालांकि, उनकी रचनाएं केवल ऐतिहासिक नहीं हैं; वे सार्वभौमिक हैं। लेखक के अनुसार, मानवता का संकट समय और स्थान से परे है। फियोना सैम्पसन का मानना है कि क्रास्नाहोरकाई का साहित्य वर्तमान विश्व की अस्थिरता को प्रतिबिंबित करता है, जहां लोकतंत्र और सभ्यता के ढांचे कमजोर पड़ रहे हैं। उनकी विचारधारा में मानव स्वभाव की नाजुकता और सत्ता के दुरुपयोग के प्रति गहरी चिंता झलकती है। न्क्रास्नाहोरकाई का मानना है कि मानव समाज बार-बार अपने ही बनाए ढांचों में उलझकर पतन की ओर बढ़ता है। उनकी रचनाएं व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों स्तरों पर इस पतन को चित्रित करती हैं। उदाहरण के लिए, 'सतानटैंगो' में एक छोटे से हंगेरियन गांव में सामूहिक भ्रम और निराशा का चित्रण साम्यवाद के पतन के बाद की सामाजिक और नैतिक रिक्तता को दर्शाता है।

क्रास्नाहोरकाई की लेखन शैली उनकी सबसे विशिष्ट विशेषता है। आलोचकों ने उनके लंबे, जटिल वाक्यों को 'संगीतमय और सम्मोहक' बताया है, जो पाठक को एक ट्रांस जैसी अवस्था में ले जाते हैं। उनकी रचनाएं पारंपरिक कथानक या संवाद पर निर्भर नहीं करतीं; इसके बजाय, वे चेतना के प्रवाह और आंतरिक एकालापों पर आधारित होती हैं। उनकी शैली फ्रांज़ काफ्का और थॉमस बर्नहार्ड की परंपरा को आगे बढ़ाती है, जिसमें एक ही वाक्य कई पृष्ठों तक चल सकता है, जैसे 'द मेलानकली ऑफ रेसिस्टेंस' में। यह शैली पाठक के लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यही उनकी रचनाओं की गहराई का रहस्य भी है क्योंकि उनके वाक्य संरचना में एक दार्शनिक और काव्यात्मक गुणवत्ता है। उदाहरण के लिए, 'वार एंड वार' में एक पांडुलिपि के माध्यम से नायक की मानसिक अवस्था को उकेरा गया है, जो वास्तविकता और भ्रम के बीच की रेखा को धुंधला करती है। उनकी रचनाएं पारंपरिक कथानक की संरचना को तोड़ती हैं और पाठक को एक गहरे, लगभग ध्यानात्मक अनुभव में डुबो देती हैं। क्रास्नाहोरकाई के उपन्यासों में प्रमुख थीम्स में अपोकैलिप्टिक (सर्वविनाशकारी) दृष्टि, सामाजिक पतन और मानव की अर्थ की खोज शामिल हैं। उनके उपन्यास 'इतिहास के अंत' की भावना को चित्रित करते हैं, जहां समाज अपने ही वजन के नीचे ढह रहा है। 'सतानटैंगो' में, एक गांव के निवासियों का एक रहस्यमय नेता के पीछे चल पड़ना इस बात का प्रतीक है कि कैसे लोग भ्रम और झूठे वादों में आसानी से फंस जाते हैं। यह उपन्यास साम्यवादी हंगरी के पतन के बाद की निराशा को दर्शाता है, लेकिन इसकी थीम्स सार्वभौमिक हैं, जो आज के लोकलुभावन और अस्थिर विश्व से भी मेल खाती हैं।

श्रवणशक्ति से भी जुड़ी है बुजुर्गों की सुरक्षा

विजय गर्ग

बुजुर्गों की सेफ्टी को लेकर सामने आयी एक जरूरी रिसर्च चेताने वाली है। जो उम्रदराज लोगों में सहज सी समझी जाने वाली स्वास्थ्य समस्या को लेकर सजग करती है। द लैंसेट पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन के मुताबिक बुजुर्गों द्वारा हियरिंग एड्स का इस्तेमाल करने और उनकी काउंसलिंग करने से उनकी गिरने की घटनाओं में कमी आती है। हम सब जानते हैं कि घर के बुजुर्ग लोगों के साथ गिरने और चोट लगने के वाकये खूब होते हैं। आमतौर पर इसका कारण उम्र के चलते शरीर में आई थकावट को माना जाता है। ऊर्जा की कमी से शरीर का संतुलन बिगड़ने को ऐसे हादसों की वजह के तौर पर देखा जाता है। ऐसे में यह रिसर्च बड़ों की सेफ़्टी को लेकर एक और समस्या पर भी ध्यान देने की बात लिए है।

सुनने में परेशानी भी समस्या

सुनने में दिक्कत का सामना कर रहे 70 से 84 वर्ष की आयु के 977 बुजुर्गों पर अमेरिका में हुए इस क्लिनिकल ट्रायल में सामने आया कि केवल शरीर का बैलेंस या सोचने-समझने की क्षमता ही नहीं, सुनने की शक्ति में कमी आना भी बुजुर्गों के गिरने का एक बड़ा कारण हो सकता है। इस अध्ययन में शामिल आधे प्रतिभागियों को हियरिंग एड्स देने और उनके फैमिली मेंबर्स की काउंसलिंग करने से बड़ा बदलाव आया। हियरिंग एड्स काउंसलिंग लेने वालों में गिरने की घटनाओं में 27 प्रतिशत की कमी देखी गई। जिसका मतलब है कि बुजुर्गों की सुरक्षा उनकी श्रवण शक्ति से भी जुड़ी है। ऊंचा सुनने की परेशानी चोट पहुंचाने वाली ऐसी दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ा देती है। जबकि इस समस्या की तरफ ध्यान कम ही जाता है। जिस तरह दूसरी हेल्थ प्रॉबलम्स को लेकर

जांच कारवाई जाती है, सजगता बरती जाती है। इस परेशानी को लेकर वैसी जागरूकता नहीं है। ऐसे में बुजुर्गों की सुनने की शक्ति कम होने की स्वास्थ्य समस्या पर ध्यान देना भी जरूरी है।

ना हो देरी

आमतौर पर जब बुजुर्ग बातचीत ही नहीं समझ पाते तब सुनने की शक्ति घटने की समस्या को गंभीरता से लिया जाता है। संवाद का सिलसिला रुक जाने पर परिजन समझते हैं कि अब बुजुर्ग सुन नहीं पा रहे। ना सुनने के कारण जवाब भी नहीं दे पा रहे। ऐसे में यह रिसर्च चेताती है कि सुनने की शक्ति को सिर्फ संवाद से ही नहीं, सुरक्षा से भी देखा जाए। हालांकि सुनने की क्षमता में गिरावट आना सामाजिक-पारिवारिक रूप से बुजुर्गों के अलग-थलग पड़ जाने का भी बड़ा कारण है। अपनों से कुछ-सुन ना पाने की स्थितियां अवसाद और अकेलेपन की भी वजह बनती हैं। ऐसे में समय रहते सचेत होना जरूरी है। इस आयुवर्ग में हड्डियों या जोड़ों की समस्याएं तो होती ही हैं, शारीरिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। ऐसे में हियरिंग कैपेसिटी कम होना तो हादसों को न्योता देने वाला बन जाता है। तो हियरिंग एड्स और काउंसलिंग के माध्यम से घर के बड़ों को बहुत सी दुर्घटनाओं से बचाया जा सकता है। सक्रियता के मामले में उनका लाइफस्टाइल बेहतर हो सकता है। अपनों-परायों से अच्छे से संवाद कर पाना इमोशनल हेल्थ अच्छी रखने में मददगार है।

हर मोर्चे पर आए चेतना

गिरना उम्रदराज लोगों में सबसे आम दुर्घटना है। ऐसे में यह रिसर्च उम्रदराज लोगों से जुड़ी एक बड़ी समस्या को लेकर घर-परिवार के सदस्यों, पॉलिसी मेकर्स और डॉक्टर्स सभी को सजग करने वाली है। बुजुर्गों की हियरिंग हेल्थ की संभाल-देखभाल के प्रति जागरूक रहने की बात लिए है। आजकल बहुत से बुजुर्ग अकेले रहते हैं। ऐसे में सुनने की क्षमता कम होना बाहर ही नहीं घर के भीतर भी दुर्घटना का शिकार बनाता है। गिरने पर कई बार फ्रैक्चर या सिर में चोट लगने से बुजुर्गों के साथ गंभीर हादसे भी हो जाते हैं। पिछले साल द एविडेंस जर्नल में छपे अध्ययन के मुताबिक हमारे यहां 60 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के 11.43 प्रतिशत बुजुर्गों के साथ गिरने के हादसे हुए। इस उम्र में खोखली और कमज़ोर हड्डियों की समस्या ऑस्टियोपोरोसिस भी आम है। यही कारण है कि बुजुर्गों में गिरने की घटनाएं होने पर हड्डियां टूटने का खतरा अभिक होता है। आंकड़े बताते हैं कि गिरने से बुजुर्गों को लगभग 20 मामलों में कूल्हे की हड्डी का फ्रैक्चर या सिर में गंभीर चोट का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन हादसों के कारणों में शामिल श्रवण शक्ति की कमी को लेकर भी सचेत रहना जरूरी है।

सेवानिवृत्त प्रिंसिपल मलोट पंजाब

आवाज-नेतृत्व वाली एआई: भारत के डिजिटल अंतर को पूरा करना

विजय गर्ग

वर्षों से भारत का डिजिटल विभाजन उपकरणों तक पहुंच के बारे में नहीं था, बल्कि आवश्यक सेवाओं तक पहुंच। जबकि अरबों के पास इंटरनेट से जुड़े फोन हैं, लाखों लोग अभी भी स्वास्थ्य देखभाल, बैंकिंग, शिक्षा या सरकारी सेवाओं तक पहुंच नहीं पा रहे हैं क्योंकि डिजिटल दुनिया स्क्रीन, साक्षरता और इंटरफेस के आसपास डिजाइन की गई थी जो अधिकांश भारतीय संवाद करने के तरीके के अनुरूप नहीं है।

यह बदल रहा है. आवाज-आधारित एआई और बड़े भाषा मॉडल सभी के लिए एक समकक्ष बनाकर भाषा को नए इंटरफ़ेस में बदल रहे हैं। यदि इसका सही लाभ उठाया जाए, तो यह बदलाव केवल समावेशन को बढ़ावा नहीं देगा; इससे भारत की अगली आर्थिक वृद्धि लहर शुरू हो सकती है।

समकक्ष के रूप में आवाज

इंटरनेट और मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अनुसार, 2026 तक ग्रामीण भारत में 56 प्रतिशत नए इंटरनेट उपयोगकर्ता होंगे, जिनमें से दो तिहाई महिलाएं हैं। कल्पना कीजिए कि कोई ग्रामीण किसी नंबर को डायल कर रहा है, अपनी मातृभाषा में सरकारी योजनाओं के बारे में पूछताछ कर रहा है। बस एक प्राकृतिक बातचीत, AI द्वारा संचालित। आवाज प्रौद्योगिकी से प्रेरित यह बदलाव साक्षरता और डिजिटल नेविगेशन की बाधाओं को दूर करता है, जिससे भागीदारी सार्वभौमिक होती है।

फाउंडेशन के रूप में संप्रभु AI

इस क्रांति के लिए भारत केवल वैश्विक प्रौद्योगिकियों पर भरोसा नहीं कर सकता। भारत की 1600 बोली या संचार को आकार देने वाली सांस्कृतिक बारीकियों के लिए बड़े भाषा मॉडल नहीं बनाए जाते हैं। यही कारण है कि संप्रभु AI बुनियादी ढांचा महत्वपूर्ण है। भशिनी परियोजना और सरवम एआई जैसी स्टार्ट-अप पहल ऐसे मॉडल विकसित कर रही हैं जो न केवल भारतीय भाषाओं को समझते हैं बल्कि उनकी लय, स्वर और बारीकियों को भी कैप्चर करते हैं। सुविधा से परे, यह सुनिश्चित करना कि एआई समाधान राष्ट्रीय ढांचे के भीतर डेटा को संसाधित करेंगे - विशेष रूप से एक ऐसी दुनिया में जहां डेटा सार्वभौमिकता की चिंता बढ़ रही है।

प्रमुख क्षेत्रों में आवेदन

आवाज एआई के अनुप्रयोग भारत की वृद्धि के हर स्तंभ को छूते हैं। स्वास्थ्य सेवा में, एआई-चालित हेल्पलाइनें प्रथम स्तरीय triage को संभाल सकती हैं, जिससे भारत के डॉक्टर-रुग्ण अनुपात 1:1511 का तनाव कम हो जाता है। कृषि में, एआई छोटे किसानों को कीमतों और मौसम के बारे में वास्तविक समय अपडेट प्रदान कर सकता है - अकेले डिजिटल खेती $65 बिलियन का मूल्य खोल सकती है। बैंकिंग में, सुरक्षित वॉयस लेनदेन लाखों पहली बार उपयोगकर्ताओं को वित्तीय सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, जो आरबीआई के समावेशन प्रयासों के अनुरूप है। शिक्षा और नौकरियों में, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र क्षेत्रीय भाषाओं में प्रश्न पूछ सकते हैं तथा अंग्रेजी-भारी इंटरफेस की आवश्यकता के बिना व्यक्तिगत करियर मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

अगली छलांग

भारत की वृद्धि हमेशा पैमाने के बारे में रही है। पहली छलांग लोगों को मोबाइल फोन के माध्यम से जोड़ती है। दूसरी छलांग यूपीआई के माध्यम से डिजिटल भागीदारी का निर्माण करती है। अगली छलांग समावेशन पर केंद्रित होगी, जहां पहुंच आय या साक्षरता से नहीं बल्कि बोलने और समझने की सरल क्षमता से परिभाषित होती है। यह अपग्रेड से अधिक है; यह एक परिवर्तनकारी बदलाव है। डेलोइट के अनुसार, मोबाइल अर्थव्यवस्था 2030 तक भारत की जीडीपी में 1 ट्रिलियन डॉलर का योगदान दे सकती है - लेकिन केवल तभी जब इसमें प्रत्येक नागरिक शामिल हो। 400 से अधिक जीवित भाषाओं और एक विशाल ग्रामीण बाजार के साथ, आवाज-आधारित AI इस विकास की रीढ़ है। भारत का वॉयस एआई बाजार पहले से ही 2030 तक 1.8 बिलियन डॉलर के मूल्य पर है, लेकिन वास्तविक गुणक प्रभाव सांस्कृतिक रूप से जड़ वाले, सार्वभौमिक समाधानों से आएगा जो देश भर में फैलेंगे।

प्रश्न यह नहीं है कि क्या उन्नत प्रौद्योगिकियां डिजिटल अंतर को पार कर सकती हैं - वे पहले से ही कर सकते हैं। वास्तविक प्रश्न यह है कि भारत इसे सार्वभौमिक बनाने के लिए बुनियादी ढांचा, विश्वास और डिजाइन सोच कितनी जल्दी बना सकता है।

यदि हम सफल होते हैं, तो अंतर न केवल बंद हो जाएगा; यह एक गुणक बन जाएगा - प्रत्येक भारतीय के लिए डिजिटल पहुंच को सशक्तीकरण, अवसर और विकास में बदल देगा।

पंजाब से रिटायर्ड प्रिंसिपल एजुकेशनल स्तंभकार मलोट पंजाब

स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी : 2047 तक भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता की राह

भारत 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनने का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाने, प्रदूषण कम करने और सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी दो मजबूत आधारस्तंभ हैं। सौर, पवन, ग्रीन हाइड्रोजन, बायोफ्यूल और बायोगैस के माध्यम से भारत एक ऐसा मॉडल प्रस्तुत कर रहा है जिसमें विज्ञान, पर्यावरण और आत्मनिर्भरता एक साथ आगे बढ़ते हैं। यदि यह रणनीति निरंतरता और नीति–सुदृढ़ता से लागू हुई, तो 2047 तक भारत न केवल ऊर्जा स्वतंत्र बल्कि हरित महाशक्ति के रूप में उभरेगा।

- डॉ सत्यवान सौरभ

भारत वर्ष 2047 में अपनी आज़ादी के सौ वर्ष पूरे करेगा। यह वह समय होगा जब राष्ट्र केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि आर्थिक और ऊर्जा दृष्टि से भी आत्मनिर्भर बनने का स्वप्न देख रहा है। आज भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता देश है। हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा भाग जीवाश्म ईंधनों — अर्थात कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस — से पूरा होता है। किंतु इन संसाधनों की सीमित उपलब्धता और इनके दुष्परिणाम अब स्पष्ट हैं। तेल आयात पर अत्यधिक निर्भरता भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ डालती है। अतः ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में "स्वच्छ प्रौद्योगिकी" और "जैव प्रौद्योगिकी" ही भारत के भविष्य की आधारशिला सिद्ध हो सकती हैं।

ऊर्जा स्वतंत्रता का अर्थ केवल पेट्रोल या डीज़ल के आयात को रोक देना नहीं है, बल्कि यह ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का संकल्प है जिसमें ऊर्जा उत्पादन, वितरण और उपभोग — सभी स्तरों पर पर्यावरण अनुकूल, टिकाऊ और स्वदेशी समाधान अपनाए जाएँ। स्वच्छ प्रौद्योगिकी का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, कार्बन उत्सर्जन घटाना और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। वहीं जैव प्रौद्योगिकी, जीवित सूक्ष्मजीवों और प्राकृतिक जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से नई ऊर्जा संभावनाएँ खोजने में सहायक बनती है।

भारत की बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और शहरीकरण के कारण ऊर्जा की माँग लगातार बढ़ रही है। आज भारत अपनी कुल तेल आवश्यकताओं का लगभग अस्सी प्रतिशत विदेशों से आयात करता है। यह न केवल विदेशी मुद्रा पर भार डालता है बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी संकट में डालता है। यदि भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र बनना है तो उसे परंपरागत ईंधनों के स्थान पर नवीकरणीय और स्वच्छ स्रोतों को प्राथमिकता देनी होगी।

सरकार ने इस दिशा में कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय सौर मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम, फेम योजना और राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति जैसी योजनाएँ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव रख रही हैं। इन पहलों का उद्देश्य है — जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना, स्वदेशी तकनीकों को बढ़ावा देना और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना।

भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में विश्व का अग्रणी देश बन रहा है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बड़े सौर पार्क स्थापित किए गए हैं। 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार

पवन ऊर्जा और जलविद्युत परियोजनाएँ भी तेज़ी से आगे बढ़ रही हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी के प्रयोग से ऊर्जा उत्पादन अधिक कुशल और पर्यावरण अनुकूल बनता जा रहा है।

ऊर्जा स्वतंत्रता के लिए केवल उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं है। ऊर्जा का संचयन और उसका स्मार्ट उपयोग भी उतना ही आवश्यक है। नवीकरणीय स्रोतों की अनियमितता — जैसे सूर्य का न उगना या हवा का न चलना — ऊर्जा आपूर्ति को प्रभावित करती है। इसके समाधान के रूप में बैटरी भंडारण और स्मार्ट ग्रिड तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। इनसे ऊर्जा को संग्रहीत कर आवश्यकता पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है।

भारत का "ग्रीन हाइड्रोजन मिशन" इस दिशा में ऐतिहासिक पहल है। हाइड्रोजन वह ईंधन है जो जल के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है और इसके उपयोग से कार्बन उत्सर्जन लगभग शून्य रहता है। यह इस्पात, परिवहन और उर्वरक जैसे भारी उद्योगों के लिए स्वच्छ ऊर्जा विकल्प प्रस्तुत करता है। 2030 तक पाँच मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। यह भारत को तेल आयात से काफी हद तक मुक्त कर सकता है।

परिवहन क्षेत्र में "विद्युत वाहन" एक और बड़ा परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में तेल की खपत का लगभग एक-तिहाई भाग यातायात से संबंधित है। फेम-2 योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। इससे पेट्रोल-डीज़ल की खपत घटेगी, प्रदूषण कम होगा और नागरिकों को सस्ती व स्वच्छ यात्रा सुविधा मिलेगी।

अब बात करें जैव प्रौद्योगिकी की — यह भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए ऊर्जा स्वतंत्रता का स्वदेशी समाधान बन सकती है। जैव प्रौद्योगिकी से बायोफ्यूल, बायोगैस और बायोडीज़ल जैसे वैकल्पिक ईंधन तैयार किए जाते हैं। इनका स्रोत है — कृषि अपशिष्ट, पशु मल, औद्योगिक जैविक कचरा तथा शैवाल।

कृषि अवशेषों से ईंधन बनाने की तकनीकें अब "सेकंड जेनरेशन" और "थर्ड जेनरेशन" स्तर तक पहुँच चुकी हैं। हरियाणा के पानीपत में स्थापित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का बायो-एथेनॉल संयंत्र इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ पराली से एथेनॉल तैयार किया जा रहा है, जो पेट्रोल में मिलाया जाता है। इससे किसानों को पराली जलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती और पर्यावरण प्रदूषण में कमी आती है।

भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा की बचत होगी बल्कि किसानों की आय भी बढ़ेगी। जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से ऊर्जा फसलों में आनुवंशिक सुधार किया जा रहा है ताकि उनसे अधिक मात्रा में एथेनॉल और बायोडीज़ल प्राप्त हो सके।

शैवाल आधारित ईंधन उत्पादन की दिशा में भी अनुसंधान चल रहा है। समुद्री शैवाल कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर ऊर्जा उत्पन्न करने में सक्षम हैं। इस प्रक्रिया से "बायो-हाइड्रोजन" भी निर्मित किया जा सकता है। यदि इसे बड़े पैमाने पर अपनाया गया तो यह पारंपरिक पेट्रोलियम का विकल्प बन सकता है।

"बायोरिफाइनरी मॉडल" भी भारत की जैव-आर्थिक प्रगति में नई दिशा दे रहा है। इस मॉडल में एक ही जैविक कच्चे माल से ऊर्जा, रसायन, प्लास्टिक विकल्प और अन्य मूल्यवान उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यह मॉडल शून्य अपशिष्ट नीति के अनुरूप है और ग्रामीण उद्योगों को सशक्त बनाता है।

ग्रामीण भारत में बायोगैस संयंत्रों की स्थापना से ऊर्जा क्रांति लाई जा सकती है। गोबर और जैविक कचरे से उत्पन्न बायोगैस घरेलू उपयोग के साथ-साथ लघु उद्योगों को भी ऊर्जा प्रदान कर सकती है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, स्वच्छता और आत्मनिर्भरता तीनों को बल मिलता है।

ऊर्जा स्वतंत्रता केवल तकनीकी विषय नहीं है, यह सामाजिक और आर्थिक बदलाव का प्रतीक भी है। हमें अपनी जीवनशैली में ऊर्जा दक्षता को अपनाना होगा। "ऊर्जा बचत ही ऊर्जा उत्पादन है" — इस सिद्धांत को व्यवहार में उतारना होगा।

सरकार को अनुसंधान और नवाचार में निवेश बढ़ाना होगा। विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और निजी उद्योगों के बीच सहयोग से स्वदेशी प्रौद्योगिकियाँ विकसित की जा सकती हैं। साथ ही, जैविक कचरे से ऊर्जा उत्पादन हेतु वित्तीय प्रोत्साहन और सब्सिडी की नीति को सुदृढ़ बनाना होगा।

अंतरराष्ट्रीय सहयोग भी इस दिशा में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। भारत "अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन" का संस्थापक सदस्य है, जिसने 100 से अधिक देशों को सौर ऊर्जा विकास के लिए जोड़ा है। इसी प्रकार "जी-20" और "संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन" जैसे मंचों पर भारत स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक नेता के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है।

2047 तक ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने से भारत को आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय — तीनों क्षेत्रों में लाभ होगा। विदेशी मुद्रा की बचत, प्रदूषण में कमी, ग्रामीण आय में वृद्धि और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। जैव प्रौद्योगिकी आधारित उद्योग नए रोजगार और उद्यम के अवसर भी प्रदान करेंगे।

अंततः भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता केवल आर्थिक स्वायत्तता नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आत्मसम्मान का प्रतीक होगी। जिस दिन भारत अपने खेतों, प्रयोगशालाओं और सूरज की किरणों से अपनी पूरी ऊर्जा आवश्यकता पूरी करेगा, उस दिन वह सच्चे अर्थों में "आत्मनिर्भर भारत" कहलाएगा।

2047 तक की यह यात्रा कठिन अवश्य है, किंतु असंभव नहीं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी और जैव प्रौद्योगिकी के संयुक्त प्रयासों से भारत न केवल ऊर्जा आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि विश्व को हरित विकास और सतत ऊर्जा की दिशा में मार्गदर्शन देने वाला देश भी बन सकता है।

भारत को अपनी विरासत और पहचान को अगली पीढ़ी तक अपने ग्रंथों के माध्यम से पहुँचाना होगा" : डॉ. सोम देव भारद्वाज

लोंगोवाल,10 अक्टूबर (जगसीर सिंह)-

स्लाईट लोंगोवाल में निदेशक प्रोफेसर मणि कांत पासवान के मार्गदर्शन में तथा डीन (पूर्व छात्र एवं औद्योगिक संबंध) कार्यालय के संयोजन से 'मंथन' का द्वितीय एपिसोड सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस सत्र का विषय था — "प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित विज्ञान का विश्लेषण मंथन पहल का उद्देश्य छात्रों में रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करना है, ताकि वे भारत की प्राचीन ज्ञान परंपराओं को आधुनिक विज्ञान के दृष्टिकोण से समझ सकें। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में डॉ. सोम देव भारद्वाज ने प्राचीन भारतीय ग्रंथों में निहित वैज्ञानिक तत्वों और ज्ञान परंपराओं पर प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी राष्ट्र तब तक वास्तविक प्रगति नहीं कर सकता, जब तक वह अपनी सांस्कृतिक और वैचारिक विरासत पर गर्व करना नहीं सीखता "प्राचीन भारतीय ग्रंथ केवल आध्यात्मिक मार्गदर्शक नहीं हैं, बल्कि वे वैज्ञानिक खोज, निरीक्षण और तर्क का भंडार हैं। एक सशक्त राष्ट्र बनने के लिए हमें अपनी बौद्धिक धरोहर से पुनः जुड़ना होगा और उसे आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से पुनर्व्याख्यायित करना होगा ।अपने संबोधन में प्रो. रवि कांत मिश्रा, डीन (पूर्व छात्र एवं औद्योगिक संबंध) ने शोधार्थियों को प्रेरित किया कि वे भारतीय ग्रंथों का गहन अध्ययन करें और उनमें निहित वैज्ञानिक ज्ञान को पुनः खोजें। उन्होंने कहा कि कई विदेशी विश्वविद्यालय भारतीय ग्रंथों पर गहराई से शोध कर रहे हैं और उनसे नवीन आविष्कारों की दिशा में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में भारतीय शोधार्थियों को भी अपनी विरासत को गर्वपूर्वक आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि "मंथन जैसी पहल हमें अपनी प्राचीन भारतीय ज्ञान

परंपराओं को अतीत की धरोहर के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य के लिए असीम वैज्ञानिक प्रेरणा स्रोत के रूप में देखने की प्रेरणा देती है।" प्रो. सुरिंदर सिंह, डीन (अनुसंधान एवं परामर्श) ने वेदों में वर्णित वैज्ञानिक सिद्धांतों पर व्यवस्थित और साक्ष्य-आधारित अनुसंधान की आवश्यकता पर बल दिया। प्रो. कमलेश प्रसाद, डीन (फैकल्टी एवं स्टाफ वेलफेयर) ने पारंपरिक भारतीय आहार प्रणाली के वैज्ञानिक दृष्टिकोण और उसके मानव स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव को रेखांकित किया। प्रो. ए.एस. शाही, डीन (एकेडमिक्स) ने भारतीय शास्त्रों और गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षाओं के बीच सामंजस्य को दर्शाया, यह बताते हुए कि भारत की परंपरा आध्यात्मिकता और वैज्ञानिक चिंतन के समन्वय की रही है। कार्यक्रम के अंत में "प्राचीन भारतीय ग्रंथों और परंपराओं में निहित वैज्ञानिक ज्ञान तथा आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान" विषय पर एक इंटरएक्टिव चर्चा आयोजित की गई, जिसमें शिक्षकों, शोधार्थियों और विद्यार्थियों ने सक्रिय भागीदारी की।

इस विचार-विमर्श ने सभी को प्रेरित किया कि वे प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान से जोड़ते हुए, ज्ञान, तर्क और खोज पर आधारित राष्ट्रीय गर्व की भावना को सशक्त करें।

मैं लड़की हूं — संकट नहीं, समाधान हूं!

जब एक बालिका जन्म लेती है, वह केवल एक जीवन नहीं लाती—वह एक नई दृष्टि, अनंत संभावनाओं का सूर्य, और समाज को बदलने की अटल शक्ति लाती है। उसकी मुस्कान में भविष्य की गूंज और आंखों में सपनों का सागर छिपा है। लेकिन यह कटु सत्य भी है कि आज भी दुनिया के कई हिस्सों में वह भेदभाव, असमानता और अन्याय के साये में अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस, जो हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है, केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक क्रांतिकारी उद्घोषणा है—"मैं लड़की हूं, मैं बदलाव की अगुआ हूं।" यह दिन बालिकाओं की अदम्य शक्ति का उत्सव है और उनके अनदेखे संघर्षों को सम्मान देने का आह्वान।

संयुक्त राष्ट्र ने 2025 के लिए इस दिवस का विषय चुना है—"मैं लड़की हूं, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूं: संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां", यह विषय आज की सच्चाई को उजागर करता है—बालिकाएं अब परिवर्तन की प्रतीक्षा नहीं करतीं; वे उसकी सशक्त वाहक हैं। चाहे जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष हो, डिजिटल समानता की मांग हो, या सामाजिक न्याय की लड़ाई—हर मोर्चे पर बालिकाएं अपनी अमिट छाप छोड़ रही हैं। संकटों में, जब दुनिया ठहर जाती है, यही बालिकाएं आगे बढ़ती हैं। कोविड-19 महामारी इसका जीवंत उदाहरण है। यूनेस्को के आंकड़ों के अनुसार, उस दौरान लगभग 24 मिलियन बच्चे, विशेषकर लड़कियां, स्कूल छोड़ने के कगार पर थे। फिर भी, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किशोरियों ने मास्क बनाए, स्वास्थ्य जागरूकता फैलाई, और ऑनलाइन शिक्षा के लिए अपने समुदायों को प्रेरित किया। यह साबित करता है कि नेतृत्व उम्र या लिंग से नहीं, बल्कि दृढ़ संकल्प और संवेदना से परिभाषित होता है।

इन प्रेरक कहानियों के बीच एक कड़वी सच्चाई भी है। यूनिसेफ की 2023 की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में 129 मिलियन लड़कियां स्कूल से वंचित हैं। प्राकृतिक आपदाओं, युद्धों और गरीबी के कारण सबसे पहले इन्हीं की शिक्षा छिनती है। जलवायु परिवर्तन जैसे संकटों में, लड़कियां न केवल पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करती हैं, बल्कि सामाजिक असमानता का भी शिकार बनती हैं। बांग्लादेश और भारत में बाढ़ व चक्रवातों के दौरान लड़कियों को अक्सर परिवार की जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, जिससे उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित होते हैं। लेकिन यही लड़कियां समाधान की मशाल भी थाम रही हैं। मलावी और युगांडा में किशोरियां जलवायु कार्यकर्ता बनकर स्थानीय स्तर पर वृक्षारोपण और टिकाऊ खेती को बढ़ावा दे रही हैं। यह दिखाता है कि संकट की अग्रिम पंक्ति में लड़कियां केवल पीड़ित नहीं, बल्कि परिवर्तन की सशक्त अगुआ हैं।

डिजिटल असमानता एक और अनदेखा संकट है। आज डिजिटल पहुंच केवल सुविधा नहीं, बल्कि मौलिक अधिकार है। फिर भी, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन (आईटीयू) के 2024 के आंकड़ों के अनुसार, विकासशील देशों में केवल 37% महिलाएं और लड़कियां इंटरनेट का उपयोग करती हैं, जबकि पुरुषों के लिए यह आंकड़ा 43% है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लाखों लड़कियों को स्मार्टफोन और डिजिटल शिक्षा की कमी झेलनी पड़ती है। यह केवल तकनीकी संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक सोच का अभाव है। केन्या और नाइजीरिया में लड़कियां डिजिटल शिक्षा के लिए अभियान चला रही हैं, कोडिंग सीख रही हैं, स्टार्टअप शुरू कर रही हैं, और तकनीकी क्षेत्र में अपनी जगह बना रही हैं। यह एक नई क्रांति की शुरुआत है, जो हमें यह सवाल पूछने को मजबूर करती है—क्या हम वाकई अपनी लड़कियों को डिजिटल युग में नेतृत्व के लिए सशक्त कर रहे हैं?

लड़कियों की मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास एक अनमोल शक्ति है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। हम उन्हें सशक्त बनाने की बात करते हैं, लेकिन क्या हम उन्हें ठोकर खाकर फिर उठने का हौसला देते हैं? समाज लड़कियों से हर कदम पर पूर्णता मांगता है, पर गलतियों से सीखने की आजादी उन्हें शायद ही मिलती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, सामाजिक दबाव और लैंगिक असमानता के कारण किशोरियों में तनाव और चिंता की दर लड़कों से कहीं अधिक है। अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस हमें सिखाता है कि नेतृत्व का मतलब केवल जीत नहीं, बल्कि हर मुश्किल में खुद पर भरोसा कायम रखना है। हमें हर लड़की को यह यकीन दिलाना होगा कि उसकी आवाज अमूल्य है और उसकी असफलताएं उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी शक्ति का सबूत हैं।

परिवर्तन की शुरुआत घर की चौखट से होती है। क्या हम अपनी बेटियों को निर्णय लेने की आजादी देते हैं? क्या उनकी राय को बेटों जितना सम्मान मिलता है? एक अध्ययन बताता है कि भारत में केवल 27% परिवार किशोरियों को घरेलू फैसलों में शामिल करते हैं। नेतृत्व की नींव घर में पड़ती है। जब एक बेटी को यह विश्वास मिलता है कि वह गलती कर सकती है, उससे सीख सकती है, और फिर दुनिया को चुनौती दे सकती है, तभी वह सच्चा नेतृत्व निभाती है।

हमें एक ऐसा समाज रचना होगा जहां हर बालिका बिना डर के बोले, बिना बाधा के सीखे, और बेझिझक सपने सजाए। इसके लिए शिक्षा में समावेश, रोजगार में समानता और सामाजिक ढांचे में संवेदनशीलता अनिवार्य है। लड़कियां बदलाव की मांग नहीं करतीं—वे बदलाव का चेहरा हैं। वे ग्रेटा थनबर्ग की तरह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया को झकझोर रही हैं। वे डिजिटल युग में तकनीकी क्रांति की नींव रख रही हैं। वे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो अपने समुदायों में समानता की लौ जला रही हैं।

"मैं लड़की हूं, मैं बदलाव का नेतृत्व करती हूं" सिर्फ एक नारा नहीं, एक अटल विश्वास है। यह हमें सिखाता है कि जब हम एक लड़की को बोलने का मंच देते हैं, तो हम भविष्य को नया आकार देते हैं। जब हम उसकी प्रतिभा पर भरोसा करते हैं, तो हम समाज को अडिग बनाते हैं। 11 अक्टूबर 2025 का अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस केवल एक तारीख नहीं, बल्कि एक क्रांति का आह्वान है। यह हर उस लड़की की आवाज को बुलंद करेगा, जो अपने भीतर दुनिया बदलने की ज्वाला रखती है। जिस दिन हर लड़की निर्भय होकर कह सके—"मैं डरती नहीं, मैं नेतृत्व करती हूं"—वही दिन इस उत्सव की सच्ची जीत होगा। क्योंकि एक ऐसा समाज, जहां लड़कियां संकटों में भी मुस्कराकर आगे बढ़ें, वही सच्चे अर्थों में प्रगतिशील है।

प्रो. आरके जैन "अरिजीत", बड़वानी

कानपुर धमाके की वजह बारूद का अवैध भंडारण, पटाखा वालों की तलाश में छापे, 6 सस्पेंड

सुनील बाजपेई

कानपुर। यहां मूलगंज के मिश्री बिसाती बाजार में बुधवार को हुए धमाके का सच सामने आया है। जिसके मुताबिक इस भीषण विस्फोट की वजह पटाखों का भंडारण था। साथ ही पुलिस ने इस घटना में किसी आतंकी साजिश से भी इनकार किया है। वहीं घटना के लिए दोषी मानते हुए मूलगंज थाना प्रभारी विक्रम सिंह, चौकी प्रभारी एसआइ रोहित तोमर सहित जेबरा मोबाइल कांस्टेबल चेतन कुमार, अमित कुमार, बीट कांस्टेबल ब्रह्मानंद, हेड कांस्टेबल इमामुल हक को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही ए सीपी को भी हटाया गया है।

अबतक तक चले सर्च आपरेशन में पुलिस ने 12 दुकानदारों को हिरासत में लिया है। मामले में पुलिस जिन दुकानदारों के यहां अवैध पटाखों का भंडारण मिला है। उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराने की तैयारी कर रही है।

मिश्री बाजार में मरकज मस्जिद से 100 मीटर दूर खड़ी चोरी की स्कूटी में बुधवार शाम भीषण विस्फोट हुआ था। इसकी चपेट में महिला समेत 12 लोग घायल हो गए थे, जिसमें आठ लोगों को उर्सुला में भर्ती कराया गया था। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि बगल में खड़ी लालबंगला निवासी अश्वनी कुमार की स्कूटी क्षतिग्रस्त और आसपास के कई घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए थे।

इस घटना को हादसा, शरारत और साजिश के बिंदुओं पर जांच शुरू कर दी गई। एटीएस समेत एजेंसियों ने जांच पड़ताल की। देर रात सर्च आपरेशन चला गया तो कई दुकानों में अवैध पटाखों का भंडारण मिला।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर कानून-व्यवस्था आशुतोष कुमार ने बताया कि जहां धमाका हुआ, वहां कई दुकानों में तैयार पटाखे और पटाखे बनाने का बारूद भारी मात्रा में था। एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला, जिसमें दुकान में रखे एक ढेर में हुआ विस्फोट दिखा है। जिससे विस्फोट की वजह स्पष्ट हो गई है। वहीं पुलिस बिना अनुमति रिहायशी इलाके में बारूद भंडारण व बिक्री करने वालों को गिरफ्तारी के लिए लगातार छापे भी मार रही।

जिला केमिस्ट एसोसिएशन ने एसपी एच राजेश छिब्बर से की मुलाक़ात

नशा मुक्ति अभियान में केमिस्टों के सहयोग की जरूरत: एसपी छिब्बर

सुनाम, 10 अक्टूबर (जगसीर सिंह)- जिला संगरूर केमिस्ट एसोसिएशन के वफद ने अध्यक्ष नरेश जिंदल के नेतृत्व में हाल ही में तैनात हुए एसपी (एच) राजेश छिब्बर से मुलाक़ात की । इस दौरान पदाधिकारियों ने एसपी को ऐसोसिएशन की गतिविधियों की जानकारी दी । साथ ही भरोसा दिलाया कि एसोसिएशन सरकार की युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के साथ चट्टान की तरह खड़ी है । एसपी राजेश छिब्बर ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान में केमिस्टों के सहयोग की जरूरत है और उन्हें पूर्ण भरोसा है कि जिला संगरूर की एसोसिएशन पूरा सहयोग देगी । उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों से अपील की कि यदि कोई केमिस्ट या अन्य व्यक्ति नशे के तौर पर उपयोग होने वाली दवाओं की बिक्री करता है तो उसकी जानकारी पुलिस को ज़रूर दें । इस मौके पर एसोसिएशन के सचिव विनीत जिंदल, कोषाध्यक्ष अजायब सिंह उपस्थित रहे ।

आवश्यकता और वैज्ञानिक सोच देती है आविष्कार को जन्म-डीएम दिव्यांग के लिए स्मार्ट हेंडीकेप्ट चेयर , व आर्मर ड्रोन रहे आकर्षण

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

कासगंज। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग उ0प्र0 शासन के निर्देशन में श्री गणेश इण्टर कॉलेज में जनपद स्तरीय विज्ञान मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन किया। जिसमें 192 बाल वैज्ञानिकों ने 140 विज्ञान मॉडलों की प्रस्तुति दी। प्रतियोगिता का आयोजन जिला विज्ञान क्लब के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि एमएलसी रजनीकान्त माहेश्वरी, कार्यक्रम अध्यक्ष जिलाधिकारी प्रणय सिंह, राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़, सीडीओ सचिन द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्ज्वलन कर किया गया। तत्पश्चात नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज एवं श्री गणेश इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती वंदना एवं स्वागत गान की मनमोहक प्रस्तुति दी। इससे पूर्व सभी अतिथियों को चौधरी दाताराम सिंह इंटर कॉलेज अलीपुर बरवारा के छात्र-छात्राओं द्वारा घोष बैंड एवं एनसीसी कैडेट्स की सलामी के साथ मंच तक ले जाया गया।

सभी अतिथियों का डीआईओएस डॉ इंद्रजीत, कार्यक्रम संयोजक डॉ. जयन्त कुमार गुप्ता एवं प्रधानाचार्य एचपीएन दुबे ने बुके, माला, शॉल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया।

जिलाधिकारी प्रणय सिंह, एमएलसी रजनीकांत महेश्वरी एवं अन्य आगंतुक अतिथियों ने विज्ञान मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिलाधिकारी द्वारा विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए मॉडलों की काफी सराहना की गई, उन्होंने कहा कि विज्ञान प्रदर्शनी से नए नवाचार और आइडिया मिलते हैं और इन्हें अन्य लोगों के साथ साझा किया जाता है। अच्छे मॉडल्स को जनहित के लिए क्रियाकारी मशीनों में बदलकर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं।

एमएलसी रजनीकांत माहेश्वरी ने कहा कि एक विद्यार्थी द्वारा प्रदर्शनी में जो स्वदेशी वस्तुओं का मॉडल दर्शाया गया है उसे निश्चायी निश्चित ही यह प्रतीत होता है, कि मा प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी का जो संकल्प है उसे यह मॉडल सार्थक बनाने का प्रयास करेगा।

राज्य महिला आयोग की सदस्य रेनू गौड़ ने विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने जो एक्सीडेंट प्रीवेंशन सिस्टम, स्मार्ट अलार्म सिस्टम फॉर ह्यूमन सेफ्टी, गरुण ड्रोन, आर्मर ड्रोन, रिन्यूबल सोलर एनर्जी, हाईड्रो पावर प्लांट, मॉडीफाइड रेलवे क्रासिंग गेट, बायो एनर्जी, मल्टीपरपज रोबोटिक व्हीकल आदि के मॉडल प्रस्तुत किए हैं वह काफी सराहनीय है।

उन्होंने कहा कि जिला विज्ञान क्लब जनपद में विद्यार्थियों एवं जनमानस के मध्य वैज्ञानिक गतिविधियों से वैज्ञानिक सोच और विज्ञान के प्रति रूचि बढ़ाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम का संचालन नोडल समन्वयक राजबहादुर ने किया।

जिला विज्ञान क्लब समन्वयक डॉ. जयन्त कुमार गुप्ता ने सभी का आभार व्यक्त किया।

इस दौरान उपजिलाधिकारी सदर संजीव कुमार, प्रधानाचार्य एचपीएन दुबे, कैप्टन आलोक कुमार दुबे, डी एस पाल, सह समन्वयक अभिषेक पांडे, अनुभव पाठक, दीपक मिश्रा, मदन राजपूत सुदेश वर्मा, राजकुमार कुशवाहा, डॉ सरिता शर्मा, दीपराज माहेश्वरी, डॉ. बीपी मौर्या, डॉ राजकुमार वर्मा, विमल कुमार सिंह, वेद प्रकाश, मनोज यादव, जितेंद्र सिंह पाल, अजय माहेश्वरी एवं जनपद के विज्ञान शिक्षक एवं शिक्षकाएं आदि मौजूद रहे।

गड्डिम्मैसमा दोमरा पोचमपल्ली स्थित में करवा चौथ के पावन अवसर पर पूजा-अर्चनाकर पति की लंबी उम्र के लिए चांद का दीदार करती हुई धार्मिक सेवा की गीता सोलंकी, रेखा हाम्बड़ , रेखा गेहलोत, लक्ष्मी सोलंकी व प्रवासी महिलाएं।

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

कासगंज : नकली DAP खाद पर बड़ी कार्रवाई, तीन गोदाम सीज। कासगंज में नकली DAP खाद के खिलाफ एसडीएम, तहसीलदार और कृषि अधिकारी की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई की। तीन गोदामों को सीज किया गया — दो सोरों कोतवाली क्षेत्र में और एक सदर कोतवाली के बंजारा नगला में। मौके से 65 बोरी तैयार नकली खाद, 211 बोरी कच्चा माल, 155 बोरी काला दाना, कांटा, सिलाई मशीन, खाली बोरियां और एक पिकअप लॉडर सहित चालक को पकड़ा गया। कार्रवाई में कृषि अधिकारी डॉ. अवधेश मिश्र, सदर एसडीएम, तहसीलदार व पुलिस टीम शामिल रही।

माओवाद ग्रसित प0 सिंहभूम में तीन शिक्षक लाखों रुपए अवैध वसूली करते निलंबित

कार्तिक कुमार परिच्छा, स्टेट हेड -झारखंड

चाईबासा: सिंहभूम , सरायकेला -खरसावां की बात छोड़े आज झारखंड का अनेक क्षेत्र शिक्षा माफियाओं कब्जे में त्राहि-त्राहि कर रहा है । सच तो यह है कि इन इलाकों के डीईओ हो या डीईएसई इनके क्षेत्र में बड़े पैमाने पर उगाही ने शिक्षा के क्षेत्र को कलंकित कर रखा है दशकों से . गत वर्ष सरायकेला के पूर्व डीईओ संतोष गुप्ता की हकीकत से जहां इस विभाग की कलाई खोल कर रख दिया था आज पुनः इसके पैतृक जिला पश्चमी सिंहभूम के चाईबासा में शिक्षकों से लाखों रुपये की अवैध वसूली के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. उपायुक्त चंदन कुमार के आदेश पर तीन शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया है. यह कार्रवाई विभागीय जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है. सवाल आता है वेतन दिलाने में दलालों भूमिका क्यों ? पढ़ाई का स्तर की मूल्यांकन क्यों नहीं ?

शिक्षा विभाग ने इस पूरे मामले की जांच तेज कर दी है, जिसमें कुछ और नामों के सामने आने की संभावना है. निलंबित शिक्षकों में राकेश महतो (मारवाड़ी प्लस टू उच्च विद्यालय, चक्रधरपुर), प्रदीप फेडरिक मिंज (प्लस टू उच्च विद्यालय,

गोइलकेरा) और अलोक मुंडू (प्लस टू उच्च विद्यालय, कुल्डा, बंदगांव) शामिल हैं.

मामला स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों से संबंधित है. आरोप है कि पांच शिक्षकों ने बकाया वेतन भुगतान कराने के नाम पर अन्य शिक्षकों से 35 से 40 लाख रुपये तक की राशि अवैध रूप से वसूली थी. यह रकम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और नकद के जरिए ली गई थी. इस मामले में शिक्षकों के एक समूह ने जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष लिखित शिकायत दर्ज कराई थी.

शिकायत में कहा गया कि वेतन दिलाने के नाम पर बड़ी रकम वसूली गई, लेकिन न तो वेतन मिला और न ही रकम वापस की गई. डीईओ की कार्रवाई के तहत जिला शिक्षा पदाधिकारी टोनी प्रेमराज टोप्पो ने बताया कि जांच में प्रारंभिक तौर पर तीन शिक्षकों की संलिप्तता सामने आई हैं. उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और विभागीय जांच जारी है. उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए दोषी पाए जाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह किसी भी पद पर हों.

आखिर इन तीनों सिंहभूम के औधौगिक इलाके को छोड़कर वाकी इलाकों में शिक्षा का गुणवत्ता स्तर क्या है ? कितने शिक्षक अधिकारियों की दलाली में लगे रहते यह तो पीड़ित शिक्षक गण दशकों से जानते आ रहे हैं .अगर मां सरस्वती के मंदिर में यह माजरा चलता हो तो यहां आने वाले समय में स्थिति कितनी भयावह होगी सहज अंदाजा लगाया जा सकता है . इन इलाकों में माओवाद ही समस्या नहीं गुणवत्ता हीन शिक्षा, जनप्रतिनिधियों की शैक्षणिक स्तर कम का होने से शिक्षा पर फोकस नहीं होना वह भी सरायकेला खरसावां में . आलोक को कभी ओडिशा फिर बिहार अब अब झारखंड में रख कर विकास की किरण नहीं पहुंचने देना जिसका उद्देश्य मूल रूप से रह रहे जनमानस की अवहेलना ही है .

"पोषण भी, पढ़ाई भी" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

रिपोर्ट अंकित गुप्ता कासगंज

गंजडुंडवारा। अनिल राठौर (ब्यूरो चीफ) विकास खण्ड गंजडुंडवारा के मीटिंग हाल में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा "पोषण भी, पढ़ाई भी" विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित

गंजडुंडवारा में बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा "पोषण भी, पढ़ाई भी" अभियान के अंतर्गत एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं को बच्चों के समग्र विकास — विशेष रूप से पोषण, स्वास्थ्य एवं प्रारंभिक शिक्षा — से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गईं।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी समान रूप से ध्यान देना आवश्यक है। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने के साथ-साथ खेल-खेल में पढ़ाई की गतिविधियाँ भी कराई जाएँगी ताकि बच्चे विद्यालय पूर्व अवस्था में ही सीखने की प्रक्रिया से जुड़ सकें।

कार्यक्रम में सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस अभियान को घर-घर तक पहुँचाने और समुदाय को जागरूक करने का आह्वान किया गया।

बिहार में किसकी बनेगी सरकार : बिहार की राजनीति — जहाँ सत्ता बदलती है पर व्यवस्था वही रहती है

अशोक कुमार झा

बिहार हिंदुस्तान का वह राज्य है जिसने राजनीति को दिशा दी, नेताओं को जननायक बनाया और जनता को उम्मीद और हताशा दोनों सिखाए । आज जब बिहार एक बार फिर चुनावी रणभूमि में उतरने जा रहा है तो सवाल सिर्फ यह नहीं है कि किसकी सरकार बनेगी बल्कि यह भी है कि क्या इस बार बिहार सचमुच बदलेगा ?

1990 के दशक का बिहार और २०२५ का बिहार — दोनों एक ही भूमि पर खड़े हैं पर हालात, चेहरों और चुनौतियों में ज़मीन-आसमान का अंतर है । इस बिहार में एक समय ऐसा भी था जब लालू प्रसाद यादव के दौर में "भूरा बाल साफ करो" जैसे नारे गूंजते थे. तब राजनीति जातीय संघर्ष और सामाजिक पहचान का प्रतीक थी पर आज वही बिहार विकास, रोज़गार और सुशासन की बात करता है — लेकिन यहाँ सवाल आज यह है कि क्या यह बदलाव केवल नारों तक सीमित है या ज़मीन पर भी कुछ बदला है ?

1990 का बिहार — लालटेन की रोशनी में अंधेरे का युग

1990 का दशक बिहार की राजनीति का सबसे निर्णायक काल था । जब लालू प्रसाद यादव ने समाज के वंचित वर्गों, पिछड़ों और दलितों को राजनीतिक मुख्यधारा में लाकर सामाजिक न्याय की नई परिभाषा दी थी लेकिन इस काल का दूसरा चेहरा भी उतना ही कठोर था —

भ्रष्टाचार, अपराध, अपहरण उद्योग, टूटी सड़कें, अंधेरी गलियाँ और चरमराती व्यवस्था।

शिक्षा की स्थिति

1990 के दशक में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह बिखरी हुई थी । स्कूलों में शिक्षक नहीं, कॉलेजों में क्लास नहीं, विश्वविद्यालयों में परीक्षा का इंतज़ार वर्षों तक चलता था । पटना विश्वविद्यालय जो कभी पूर्वी भारत का ऑक्सफोर्ड कहलाता था, वह कागज़ों में सीमित होकर रह गया था । गाँवों में बच्चे मजदूरी करने लगे थे, युवाओं का सपना दिल्ली, मुंबई और पंजाब की ट्रेनों में सिमट गया था ।

स्वास्थ्य सेवाएँ

उस समय सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था तब नाम मात्र की बची हुई थी । जिले के अस्पतालों में भी स्थिति यह थी कि दवा नहीं, डॉक्टर नहीं, मशीनें कबाड़ में पड़ी रहती थीं । उस समय मरीज इलाज के लिये या तो पटना मेडिकल कॉलेज तक जाते या फिर मरने की प्रतीक्षा करते । ऐसे में जनता का विश्वास सिर्फ निजी झोला-छाप डॉक्टरों पर था, न कि सरकारी डॉक्टरों पर ।

महिलाओं की स्थिति

महिलाओं की स्थिति उस समय सबसे दयनीय थी । घरों तक सीमित, शिक्षा से वंचित, और सामाजिक निर्णयों से बाहर — बिहार की महिला तब केवल "घरेलू जिम्मेदारी" का प्रतीक मात्र रह गई थी, उसकी कोई स्वतंत्र पहचान नहीं होती थी।

यातायात और बुनियादी ढाँचा

उस समय बिहार की सड़कों पर चलना जैसे बहुत बड़ी सज़ा हुआ करती थी । जर्जर सड़कों के कारण एक जिले से दूसरे जिले तक यात्रा करने में दिन लग जाते थे । ग्रामीण इलाकों में बिजली का नाम ही लोगों के लिए एक सपना था । शाम होते ही पूरा गाँव अंधेरे में डूब जाता था और लालटेन ही उम्मीद की आखिरी लौ हुआ करती थी ।

२००5 के बाद — 'सुशासन बाबू' और बदलाव की शुरुआत

२००5 में जब नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली तो बिहार की जनता ने पहली बार यह महसूस किया कि सरकार भी काम कर सकती है । उनके शासन ने अपराध पर नियंत्रण किया, सड़कों का जाल बिछाया और कानून-व्यवस्था को नई दिशा दी । "सात निश्चय योजना", "मुख्यमंत्री साइकिल योजना", "बालिका प्रोत्साहन योजना" जैसी पहलें समाज के हर वर्ग तक पहुँचीं ।

शिक्षा में सुधार

स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति, बालिकाओं को साइकिल, और स्कूल भवनों का निर्माण — इन सबने शिक्षा को जनांदोलन में बदला जिसका परिणाम भी मिला कि आज बिहार में प्राथमिक शिक्षा का प्रतिशत 1990 की तुलना में लगभग दोगुना हो गया है । हालाँकि उच्च शिक्षा अब भी चुनौतियों से भरी हुई है लेकिन कॉलेजों में लड़कियों की उपस्थिति ने समाज की तस्वीर ज़रूर बदली है ।

स्वास्थ्य में सुधार

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी अब डॉक्टर हैं, दवाएँ हैं, और इलाज भी सुलभ है । इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना ने गरीब परिवारों को इलाज की बड़ी राहत दी है । फिर भी, आज भी गाँव के अस्पतालों में संसाधनों की कमी है — जहाँ इलाज से पहले मरीज को यह सोचना पड़ता है कि "डॉक्टर मिलेगा भी या नहीं ।"

महिला सशक्तिकरण — एक नई क्रांति

नीतीश कुमार की नीतियों ने महिलाओं के सशक्तिकरण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई । 50% पंचायत आरक्षण, साइकिल योजना, शराबबंदी, और स्वयं सहायता समूहों ने महिला को एक निर्णयकर्ता बनाया जिसका नतीजा भी है कि आज बिहार की पंचायतों में लाखों महिलाएँ जनप्रतिनिधि हैं जो अब केवल रसोई नहीं संभालतीं बल्कि गाँव का विकास, शिक्षा, जल और सड़क की नीतियाँ भी तय करती हैं । यह 90 के दशक के बिहार की कल्पना से परे था ।

यातायात और इंफ्रास्ट्रक्चर

अब बिहार में गाड़ियाँ सड़क पर चलती हैं, सड़कें गाड़ियों पर नहीं । राष्ट्रीय राजमार्गों का जाल, ग्रामीण सड़कों का विस्तार, और बिजली की स्थिर आपूर्ति ने आज के बिहार की एक नई तस्वीर बनाई है । बिजली का वह राज्य जो कभी लालटेन से चलता था, आज यहाँ सुदूर गाँव में भी LED जगमगा रहा है।

केंद्र की नीतियाँ और बिहार की दिशा

केंद्र की योजनाओं ने बिहार के विकास को नई गति ज़रूर दी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है । प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों ने ग्रामीण जीवन में भी काफी कुछ बदलाव लाया है । इसके साथ ही रेलवे नेटवर्क का विस्तार, एक्सप्रेसवे, और शिक्षा संस्थानों की स्थापना से बिहार अब 'बदलते भारत' का हिस्सा भी दिखता है ।

लेकिन इन सबके बावजूद बिहार के सामने सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है — रोज़गार और उद्योग।

केंद्र की नीतियों ने दिशा ज़रूर दी पर राज्य सरकार को उन पर गति देनी होगी क्योंकि जब तक उद्योग नहीं आएंगे, तब तक पलायन नहीं रुकेगा, और जब तक पलायन नहीं रुकेगा, तब तक बिहार की आत्मा अधूरी रहेगी।

अब की राजनीति — गठबंधन, जनभावना और भविष्य की चुनौती

२०२5 का चुनाव बिहार के लिए सिर्फ एक और सत्ता परिवर्तन नहीं है, यह एक जनमत संग्रह है —

तीन दशकों के विकास, ठहराव, और उम्मीदों पर ।

नीतीश कुमार — अनुभव बनाम विश्वास का संकट

नीतीश अब भी बिहार के सबसे अनुभवी नेता हैं, लेकिन बार-बार गठबंधन बदलने से उनकी विश्वसनीयता पर असर पड़ा है । उनका शासन प्रशासनिक तौर पर बेहतर ज़रूर है, पर राजनीतिक रूप से अस्थिर ।

तेजस्वी यादव — उम्मीद और अनिश्चितता

आज तेजस्वी युवाओं की आवाज़ ज़रूर हैं, पर लालू युग की छाया से बाहर निकलना उनके लिए सबसे कठिन चुनौती है । वे रोज़गार और शिक्षा को मुद्दा बना रहे हैं, पर जनता यह देखना चाहती है कि क्या वे वादों से आगे जाकर नीति दे पाएंगे या नहीं ? अभी इसी बातों को लेकर अपनी चिंतन शुरू कर दिया है ।

भाजपा — संगठन की ताकत, चेहरे की कमी

जहाँ तक भाजपा का सवाल है तो वह केंद्र की शक्ति और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर सवार है पर राज्य में कोई करिश्माई चेहरा उसके पास अब तक तैयार नहीं हो पाया है । अगर कोई वैसा चेहरा तैयार भी होना चाहता है तो पार्टी की अंदरूनी नेतृत्व उसे आगे नहीं आने देती है । ऐसे में भाजपा के लिए यह चुनाव केवल सत्ता नहीं बल्कि राज्य में अपनी स्थायी नेतृत्व संरचना खड़ी करने का अवसर भी है ।

वैसे भाजपा के पास आज भी नितीश मिश्रा जैसे लोग हैं जो बिहार के * बार मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र होने के साथ साथ उनकी अपनी भी एक अलग लोकप्रियता बरकरार है जिस कारण वह अपने क्षेत्र की जनता के दिलों में अपने पिता की तरह ही राज करते हैं परन्तु पार्टी के अंदरूनी नेतृत्व ऐसे चहरे को खुद ही आगे नहीं आने दे रहे क्योंकि बिहार की राजनीति में जाति का समीकरण सभी पार्टियों पर हावी है ।

जनता का मन — बदलाव की इच्छा, लेकिन भरोसे की कमी

बिहार की जनता अब भावनाओं से नहीं, परिणामों से सोचती है क्योंकि वह जानती है कि सड़कें तो बनी हैं, पर रोज़गार का अभी भी अभाव है, जिस कारण पलायन जारी है । स्कूल हैं, पर उसमें गुणवत्ता का आज भी अभाव है , जिसकारण लोग आज भी अपने बच्चे को महँगी फ़ीस देकर निजी स्कूलों में पढ़ाने को विवश हैं । अस्पताल हैं पर वहां संसाधन की कमी है । ऐसे में बिहार की जनता अब चाहती है स्थायी परिवर्तन, न कि तात्कालिक राहत । आज महिलाओं में यह भावना अधिक है कि वे अब केवल मतदाता नहीं बल्कि नीति की दिशा बदलने वाली शक्ति हैं । इसलिये अब वह चाहती हैं कि शराबबंदी के साथ साथ रोजगार भी मिले और शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी ।

बिहार की असली लड़ाई अब विकास बनाम राजनीतिक यथास्थिति की है

तीन दशकों की यात्रा के बाद बिहार ने बहुत कुछ बदला है — लालटेन से LED, गड्ढों से हाईवे, डर से विश्वास, और बंद दफ्तरों से ऑनलाइन योजनाएँ लेकिन अभी भी बिहार का युवा बाहर काम करता है, किसान बाजार तक नहीं पहुँचता और गाँवों की स्वास्थ्य सेवा शहरों पर निर्भर है ।

इसलिए इस बार सवाल यह नहीं कि "कौन जीतेगा ?" सवाल यह है कि कौन बिहार को अगले २५ वर्षों के लिए सही दिशा देगा ?

क्या जनता उस नेतृत्व को चुनेगी जो जातीय दीवारों से ऊपर उठकर "विकास" को धर्म बनाए ?

या फिर राजनीति फिर उसी पुरानी गिनती में उलझ जाएगी — जहाँ गणित जीतता है पर जनता हारती है ?

बिहार का भविष्य अब जाति या गठबंधन नहीं, जनचेतना तय करेगी क्योंकि अब जनता जान चुकी है कि वोट से सिर्फ सरकार बनती है, पर विवेक से राज्य बनता है।

राउरकेला सरकारी अस्पताल में हाउसकीपिंग-सेक्योरिटी टेंडर विवाद पर स्वास्थ्य विभाग ने झाड़ा पल्ला

एन सी पी अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव के हस्तक्षेप के बाद विभाग ने दी सफाई

आउटसोर्सिंग एजेंसी की टेंडर प्रक्रिया जारी बताकर जिम्मेदारी से किनारा

जनस्वास्थ्य से जुड़े गंभीर प्रश्नों पर विभाग की चुप्पी पर उठे सवाल

परिवहन विशेष न्यूज

राउरकेला: राउरकेला सरकारी अस्पताल में चल रहे हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज टेंडर विवाद ने नया मोड़ ले लिया है ।राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजकुमार यादव द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल उठाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने पूरे मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि टेंडर प्रक्रिया फिलहाल जारी है।

सूत्रों के अनुसार, 28 सितंबर को निदेशक कार्यालय, राउरकेला गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने पत्र संख्या 4664 के माध्यम से सीडीएमओ सुंदरगढ़ को इस संबंध में सूचना दी, जिसमें विभाग ने केवल औपचारिक जवाब देते हुए कहा कि किसी भी बिल पर निदेशक के हस्ताक्षर नहीं हुए हैं और विवादित ऑक्सीजन प्लांट यूनिट फिलहाल मरम्मताधीन है।

इसके अलावा, वाटर एटीएम को अस्पताल के अधीन न बताकर भी विभाग ने स्पष्ट जवाब देने से बचा लिया, जबकि वह अस्पताल परिसर में ही स्थित है। इससे अनियमितताओं की संभावना और गहराती दिख रही है।

डॉ. यादव ने कहा कि "भ्रष्टाचार को अब बिल्कुल भी जगह नहीं दी जाएगी। पिछली सरकारों के भ्रष्ट तरीकों से बाहर निकलने का समय आ गया है।" उन्होंने चेतावनी दी कि यदि विभाग ने पारदर्शिता नहीं दिखाई, तो इस मुद्दे को वे आगे बढ़ाकर दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में कदम उठाएंगे।

घटकेसर में अन्नोजीगुडा स्थित में करवा चौथ के पावन अवसर पर पूजा-अर्चनाकर पति की लंबी उम्र के लिए चांद का दीदार करती हुई धार्मिक सेवा की कंचन देवी काग, पुष्पा देवी, अनीता देवी, गीता देवी, सीमा देवी, ममता देवी, सुनकी देवी, ज्ञानी देवी, गेरी देवी, लक्ष्मी देवी व प्रवासी महिलाएं।

सेना की जमीन बिक्री पर सरायकेला व रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन को 28 माह बाद जमानत

कार्तिक कुमार परिच्छा स्टेट हेड -झारखंड

रांची, राजधानी रांची व ओडिशा एक पूर्व जिला रहा संप्रति झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में उपायुक्त रहे चुके आई ए एस अधिकारी छवि रंजन को शुक्रवार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्त के आधार पर बेल दे दी है । कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए जमानत दे दी है । जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की अदालत ने छवि रंजन को कुछ शर्तों के साथ झारखंड के जमीन संबंधी संगीन मामले में जमानत प्रदान की है। यह मामला तब आया था जब बरियातू के सेना की जमीन की खरीद-बिक्री के मामले में ईडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। छवि रंजन को ईडी ने चार मई 2023 को गिरफ्तार किया था, तब से वह करीब 28 माह से जेल में बंद पड़े हैं । ईडी कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद छवि रंजन ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी।

जहां विगत छह अगस्त 2025 को हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद छवि सुप्रीम कोर्ट में गए । सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। शुक्रवार को दोनों पक्ष को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने शर्तों के साथ यह जमानत प्रदान कर दी।

ईडी ने पिछले 2023 में छवि रंजन के रांची स्थित आवास, सरकारी दफ्तरों और कई अन्य ठिकानों पर छापेमारी की थी। इन छापों में बड़ी मात्रा में दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और संपत्ति से जुड़े साक्ष्य जब्त किए गए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि छवि रंजन बिना अदालत की पूर्व अनुमति झारखंड से बाहर नहीं जा सकेंगे। साथ ही, उन्हें प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरह सहयोग करना होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वे किसी भी गवाह या सह-अभियुक्त से संपर्क नहीं करेंगे। कोर्ट ने यह टिप्पणी भी की कि चूंकि यह मामला अब भी ट्रायल के चरण में है, इसलिए जमानत देने से जांच या मुकदमे की निष्पक्षता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

वहीं, ईडी की ओर से पेश वकीलों ने अदालत में तर्क दिया कि छवि रंजन के खिलाफ मजबूत और ठोस सबूत मौजूद हैं, जिनमें भूमि सौदों से संबंधित दस्तावेज, बैंक लेन-देन और इलेक्ट्रॉनिक डाटा शामिल हैं। ईडी ने यह भी कहा था कि यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो जांच प्रभावित हो सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को यह कहते हुए खारिज किया कि जमानत देने से जांच की दिशा पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब मामला न्यायालय के अधीन है।

इस मामले में ईडी ने छवि रंजन के अलावा कारोबारी विष्णु अग्रवाल, बड़गाईं अंचल के राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद, सेना के कब्जे वाली जमीन का फर्जी रैयत प्रदीप बागची, जमीन कारोबारी अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फैयाज खान व मोहम्मद सद्दाम, अमित अग्रवाल और दिलीप घोष को आरोपी बनाया था

मछुआरों की अनोखी नाव रैली, मछली पालन का मांगा अधिकार, किसान सभा ने किया समर्थन

(रिपोर्ट : संजय पराते)

बुका (कोरबा)। छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला एक आदिवासी बहुल जिला है, जो संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इस कारण यहां के विकास कामों के लिए ग्राम सभाओं की सहमति जरूरी है, जिसका उल्लेख पेसा कानून में किया गया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि राज्य में चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या भाजपा की, दोनों ने इस कानून का उल्लंघन करके जल, जंगल, जमीन, खनिज जैसी प्राकृतिक संपदा को निजी ठेकेदारों और कॉरपोरेटों के हाथों सौंपने की ही साजिश रची है।

सन 1980 के दशक में हसदेव नदी पर पोढ़ी उपरोडा ब्लॉक में बाँगो बांध का निर्माण किया गया था, जिसमें 58 आदिवासी बाहुल्य गाँव पूर्णतः डूब गए और हजारों परिवारों को विस्थापित होना पड़ा। अपने गांव और जमीन, अपनी खेती-बाड़ी और आजीविका से उन्हें स्थाई रूप से वंचित कर दिया गया। विस्थापितों को मुआवजा तथा पुनर्वास देने में भी सरकार की गंभीर विसंगतिया सामने आई, लेकिन तत्कालीन कलेक्टर ने विस्थापितों को यह आश्वासन देकर शांत कर दिया था कि डूबान क्षेत्र में सभी विस्थापित परिवार मछली पालन कर अपना जीवन यापन कर सकेंगे। इसके बाद इस क्षेत्र में कई मछुआरा सहकारी समितियों का गठन भी किया गया। इन सहकारी समितियों के गठन के बाद विस्थापित परिवारों ने रॉयल्टी के आधार पर 14-15 सालों तक मत्स्य पालन भी किया।

वर्ष 2000 में मध्यप्रदेश को विभाजित करके छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया गया और प्राकृतिक

संपदा की कॉर्पोरेट लूट की मुहिम शुरू हो गई। तमाम संसाधन निजी हाथों को सौंपे जाने लगे। अजीत जोगी की कांग्रेस सरकार ने, जो छत्तीसगढ़ की पहली सरकार थी, पूरे राज्य परिवहन निगम को ही समाप्त कर दिया और इस निगम से जुड़ी अरबों रुपयों की संपत्ति निजीकरण के यज्ञ में स्वाहा कर दी गई। निजीकरण की नीति ने राज्य में आम जनता की आजीविका पर बड़े पैमाने पर हमला किया और बांगो बांध से प्रभावित मछुआरे भी अछूते नहीं रहे।

छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद सरकार की मत्स्य नीति में भी परिवर्तन आया और जोगी के बाद बनी भाजपा सरकार ने अब बांगो बांध को ठेके पर देने का निर्णय लिया। इससे मछली पालन हेतु बांध पर नियंत्रण का अधिकार निजी ठेकेदारों के पास चला गया और स्थानीय विस्थापित आदिवासी अपने ही जमीन और जल पर निजी ठेकेदारों के द्वारा मजदूर बना दिए गए। विस्थापित आदिवासियों ने विरोध तो किया, लेकिन संगठन और आंदोलन के अभाव में उनकी आवाज को किसी ने नहीं सुना। पिछले दो दशकों से बुका विहार जलाशय को निजी ठेकेदारों को सौंपा जा रहा है।

पिछली ठेके की अवधि जून 2025 को समाप्त हो गई, जिसके बाद पुनः10 वर्षों की लीज हेतु भाजपा सरकार द्वारा निविदा जारी कर दिया है। अपनी जमीन और रोजी-रोटी से वंचित मछुआरों ने यह तय किया है कि वे अब ठेकेदारों के लिए काम नहीं करेंगे और मत्स्य नीति में संशोधन के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे, ताकि पहले की तरह रॉयल्टी के आधार पर मछली पालन का उन्हें अधिकार मिले। इस मांग के आधार पर बांगो बांध के कारण स्थापित 52 गांवों के मछुआरे लामबंद हो गए हैं और उन्होंने आदिवासी मछुआरा संघ (हसदेव जलाशय) नामक संगठन का निर्माण भी कर लिया है।

विस्थापित आदिवासियों की मांगों को तब और बल मिला, जब उन्हें अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति जैसे जुझारू संगठनों का समर्थन मिला। किसान सभा कोरबा जिले में खनन प्रभावित विस्थापितों की मांगों पर और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति अडानी द्वारा कोयला खनन के लिए हसदेव के जंगल और आदिवासियों को उजाड़ने के खिलाफ लंबे समय से संघर्ष कर रही है। इन दोनों संगठनों के नेताओं की उपस्थिति में 5 अक्टूबर को बांगो बांध प्रभावित आदिवासियों का सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसे संबोधित करते हुए प्रशांत झा, दीपक साहू, रामलाल करियाम, मुनेश्वर पोर्ते, फिरतू बिंझवार, अथनस तिर्की, रामबली और विभिन्न वक्ताओं ने हसदेव जलाशय के निजीकरण का विरोध किया और मछुआरों के मछली पालन के जरिए आजीविका कमाने के नैसर्गिक अधिकार का समर्थन किया।

सम्मेलन के बाद सैकड़ों मछुआरों ने हसदेव जलाशय में नाव रैली करके प्रशासन से निविदा रद्द करने की मांग की। 6 अक्टूबर 2025 को एस.डी.एम.

मनुष्य के वास्तविक स्वरूप के दर्शन कराने वाला दर्पण है श्रीमद्भगवद्गीता : महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज

(डॉ. गोपाल चतुर्वेदी)

वृन्दावन। रतन छतरी-कालीदह रोड़ स्थित गीता विज्ञान कुटीर में वेदांत उपदेशक, श्रीमद्भगवद गीता को प्रकांड विद्वान, 112 वर्षीय वयोवृद्ध व प्रख्यात संत गीता विज्ञान पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज (हरिद्वार) अपनी धार्मिक यात्रा पर श्रीधाम वृन्दावन आए हुए हैं।उन्होंने यहां के कई प्रख्यात संतों, धर्माचार्यों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से मुलाकात कर धर्म- अध्यात्म व अन्य विषयों पर विचार-मंथन किया।

महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि संत और ब्राह्मण देश व समाज के निर्माता और मार्ग दर्शक होते हैं।परंतु इनकी पहचान कैसे की जाय ?जिसमें समता विद्यमान हो वही संत हैं। ज्ञान प्रधान ही सच्चे संत होते हैं और विद्या प्रधान ब्राह्मण होते हैं, जो प्रत्येक जीव में ब्रह्म का दर्शन करे, वही सच्चे ब्राह्मण हैं।

उन्होंने कहा कि निष्कामता परमार्थ के सभी साधनों की जननी है।अतः हम सभी को अपने कार्य निष्काम भाव से करने चाहिए।साथ ही जगत से समता व परमात्मा से ममता रखनी चाहिए।संसार व शरीर को अपना मानना सभी पापों का मूल है।अतः संसार के सभी प्राणियों की सेवा, ईश्वर से प्रेम तथा स्वयं को त्याग करना चाहिए।साथ ही हम सभी को संयम, सेवा, सुमिरन और सादगी का पंचामृत सदैव पान करते रहना चाहिए।

स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज ने कहा कि श्रीकृष्ण के मुख से निकली श्रीमद्भगवद्गीता साक्षात ओंकार स्वरूप है।गीता एक ऐसा सेतु है जिस पर से प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत सरलता से भव सागर को पार कर सकता है।साथ ही यह एक ऐसा दर्पण है जिसमें मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन होते हैं।इसीलिए इस ग्रंथ को संस्कृत वांग्मय का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य माना गया है।इसको ₹युद्धोपनिषद₹ भी कहा गया है।

कार्यक्रम के अंतगत ब्रज सेवा संस्थान के अध्यक्ष, ₹यूपी रत्न₹ डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज को ठाकुरजी का प्रसादी पटुका ओढ़ाकर सम्मानित किया।साथ ही उन्होंने पूज्य महाराजश्री और उनके द्वारा संचालित विभिन्न सेवा प्रकल्पों की जानकारी दी।साथ ही यह बताया कि महाराजश्री अपनी 112 वर्ष की आयु में भी समूचे विश्व में श्रीमद्भगवद्गीता का सघन प्रचार-प्रसार कर असंख्य व्यक्तियों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं।

डॉ. गोपाल चतुर्वेदी ने कहा कि महामंडलेश्वर स्वामी विज्ञानानंद सरस्वती महाराज सहजता, सरलता, उदारता की प्रतिमूर्ति हैं।वे पूर्ण समर्पण के साथ भारतीय वैदिक संस्कृति व संस्कृत भाषा के उन्नयन में जुटे हुए हैं।महाराजश्री ने कई वर्षों तक हिमालय की गुफाओं में रह कर कठोर साधना की है।

इस अवसर पर मुक्तानंद चित्रवीथि के संस्थापक व प्रख्यात चित्रकार द्वारिका आनंद, स्वामी लोकेशानंद सरस्वती महाराज, स्वामी हरिकेश ब्रह्मचारी, युवा साहित्यकार डॉ. राधाकांत शर्मा आदि की उपस्थिति विशेष रही।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023